

• 11 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट • मास्टर प्लान विसंगतियों का पुलिंदा

आक्षर

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

www.akshnews.com



हार बर्दाश्त नहीं

वर्ष 18, अंक-24

16 से 30 सितंबर 2020

पृष्ठ-48

मूल्य 25 रूपये

कैसे खुशहाल होगा किसान?

घोटालों की नर्सरी बना उद्यानिकी विभाग

R.N.I. NO. HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20



Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments



Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

योजना

9

11 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

मप्र में अब सड़क हादसों की केस स्टडी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में मप्र को चुना है। यह सब सड़क हादसों को रोकने के लिए सुरक्षित उपायों को खोजने के लिए किया जा रहा है। शासन के चार विभाग मिलकर...

राजपथ

10-11

सिंधिया का इम्तिहान

मप्र में उपचुनावों को लेकर बिहार चुनाव जैसी ही गहमागहमी बनी हुई है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तरह मध्यप्रदेश में उपचुनावों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है।

विवाद

16

घरे में शत्रु संपत्ति

मप्र की राजधानी भोपाल के लगभग डेढ़ लाख परिवारों की संपत्तियां एक बार फिर खतरे की जद में हैं। यदि भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की जूनियर बेगम आफताब जहां द्वारा वर्ष 1977 में लिखे गए कथित लेटर पर भरोसा...

अवैध खनन

18

नदियों का सीना छलनी

मप्र में अवैध खनन एक ऐसा रोग हो गया है, जिसकी जितनी दवा की जाती है, वह उतना बढ़ता जाता है। यानी सरकार नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर जितनी सख्त हो रही है, नदियों का सीना उतना ही छलनी हो रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि नर्मदा नदी में अवैध...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



मप्र वाकई अजब है, गजब है। एक तरफ प्रदेश अनाज उत्पादन में साल दर साल रिकार्ड दर्ज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां के किसान धोखाधड़ी, ठगी, कालाबाजारी, शोषण और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। रबी सीजन में यूरिया घोटाले से किसान परेशान थे कि इसी दौरान घटिया चावल के वितरण ने उन्हें हैरान कर दिया। अभी यह मामला चल ही रहा है कि करीब 100 करोड़ का पावर टिलर घोटाला सामने आया है।

14-15



29



36



45



राजनीति

30-31

विभाजन की ओर

पार्टी के कार्याकल्प की योजना तैयार करने के मकसद से पत्र लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेताओं की जिस तरह उपेक्षा हो रही है, उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस एक ओर विभाजन की ओर बढ़ रही है। क्योंकि वह दिशाहीन हो गई है और इसके चलते उसके कार्यकर्ता हताश हैं।

महाराष्ट्र

35

कंगना रनौत तो बहाना है

मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है, लेकिन राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। जहां कंगना के समर्थन में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई महाराष्ट्र में मोर्चा संभाले हुए है। वहीं सोशल मीडिया पर कंगना रनौत...

बिहार

38

सत्ता के समीकरण

बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार अभी से गर्म है। तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर राज्य के चुनावी गणित को समझने वालों के लिए यह कोई पहेली नहीं है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजों से...

6-7

अंदर की बात

41

महिला जगत

42

अध्यात्म

43

कहानी

44

खेल

45

फिल्म

46

व्यंग्य



ऐसे कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार...?

किंसी शायर का एक शेर है...

यहां तहजीब बिकती है यहां फर्मान बिकते हैं,
जरा तुम दाम तो बोलो यहां ईमान बिकते हैं।

यह शेर वैसे तो पूरे देश की व्यवस्था पर सटीक बैठता है, वहीं अजब-गजब वाले मप्र में तो इसे हर जगह महसूस किया जा सकता है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नए-नए कायदे कानून बनाती है, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन ईमान बेचने वालों के आगे उसके दावे कमजोर पड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती है। आलम यह है कि यहां भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले हैं, लेकिन इन मामलों पर कार्यवाही अटका दी जाती है। आज सैकड़ों प्रकरण शासन की मंजूरी न मिलने से अटके हैं। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रीय और दो राज्यस्तरीय एजेंसियां हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार से निजात नहीं मिल रही है। सरकारी कार्यालयों में हर छोटे-बड़े काम के बदले 'मिठाई' की मांग आम बात है। बैंक, इनकम टैक्स, राजस्व, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पुलिस जैसे विभागों में रिश्वतखोरी की सबसे अधिक शिकायतें आती हैं। इसकी वजह यह है कि सरकारी जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं, जिसके कारण भ्रष्टों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे भ्रष्टाचार करने वालों में कानून और कोर्ट का भय नहीं है। आय से अधिक संपत्ति या सरकारी काम में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ना जाने क्यों अभियोजन की अनुमति नहीं देती? किंसी अफसर, कर्मचारी के पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं? सरकारी काम में भ्रष्टाचार किया है या नहीं? यह कोर्ट तय करती है। सरकार के अनुमति नहीं देने से ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त पुलिस के प्रकरण जबर्न लंबित रहते हैं। जांच पूरी होने के बाद भी चालान पेश नहीं कर पाते। जांच एजेंसियों द्वारा सरकार को कई बार अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए पत्र लिखे जाते रहे हैं। कुछ मामलों में अनुमति मिल जाती, लेकिन कई मामले अटके रहते थे। इस कारण भ्रष्टों के खिलाफ जांच अटकी रहती है। यही नहीं ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पुलिस का स्टाफ वैसे ही वर्षों से काफी कम है और काम बहुत ज्यादा। ऐसे में जल्दी-जल्दी अनुमति मिले तो केस खत्म हो। अगर सरकार लोकायुक्त पुलिस को यह अधिकार दे दे कि अभियोजन की अनुमति लिए बगैर भी केस चलाया जा सकता है, तो भ्रष्टों पर नकेल कसी जा सकती है। सरकार को सिर्फ एक आदेश जारी करना है। सरकार इतना कर दे तो जो केस सालों से लंबित हैं, वह जल्दी ही निपट जाएं। कई बार समय पर चालान पेश नहीं हो पाने के कारण भी आरोपी को जमानत का लाभ मिल जाता है। बगैर अभियोजन स्वीकृति के केस लगाने पर भी केस कमजोर होता है। अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद भी अगले ही दिन संबंधित को जेल नहीं हो जाती। अभियोजन स्वीकृति की अनिवार्यता खत्म हो जाए तो लोकायुक्त पुलिस का डर भी भ्रष्टाचार करने वालों में रहेगा। लेकिन ये बातें हैं बातों का क्या? दरअसल वर्षों से यह मांग उठती रही है कि सरकार लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में दर्ज मामलों को निपटाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दरअसल, कुछ मामलों में राजनीतिक तो कुछ मामलों में प्रशासनिक हस्तक्षेप होने के कारण मामले अधर में लटके हुए हैं। इससे जांच प्रभावित होती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अभी तक कुछ लोगों को ही सजा हो पाई है, बाकी मौज कर रहे हैं।

-राजेन्द्र आगाल

प्रांशिक
अक्षर

वर्ष 18, अंक 24, पृष्ठ-48, 16 से 30 सितंबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जौन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2018-20

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्डोलेव मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पार्वती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो. -093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजर रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुध्ति सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वातधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जौन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



इंदौर फिर नंबर-1

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश के चार शहर टॉप-20 में शामिल हुए हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में एक के बाद एक चार साल से लगातार देश के सबसे साफ शहर का खिताब हासिल किया है। यह सब इंदौर के रहवासियों के सहयोग का नतीजा है।

● शैलेंद्र सिन्धोदिया, इंदौर (म.प्र.)

मेट्रो की सौगात

भोपाल और इंदौर के रहवासियों के लिए मेट्रो रेल एक बड़ी सौगात होगी। मप्र में सरकार की कोशिश है कि दिसंबर 2024 तक भोपाल और इंदौर में हर हाल में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो जाए। आने वाले कुछ सालों में इन शहरों में मेट्रो दौड़ेगी, जिससे यहां के लोगों को सहूलियतें होंगी।

● राजकुमार श्रीवास्तव, भोपाल (म.प्र.)

वर्दान है मनरेगा योजना

कोरोना संक्रमणकाल में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मनरेगा के तहत खूब काम हुए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा वर्दान खासियत हुआ है। प्रदेश में गत वर्ष की अपेक्षा 5 माह में लोगों को काम मिला है। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने में मनरेगा योजना अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है।

● अरविंद चव्हाण, ग्वालियर (म.प्र.)



कौन मारेगा बाजी?

प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। सभी पार्टियां अपने-अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। मप्र के इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस चुनाव को किसी महायुद्ध की तरह लड़ रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का फोकस ग्वालियर-चंबल अंचल में सबसे अधिक है। इसकी वजह यह है कि यहां सबसे अधिक सीटें हैं। जो पार्टी इस क्षेत्र में बाजी मारेगी, वह सत्ता के करीब पहुंच सकती है। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की परेशानी यह है कि दोनों पार्टियों में भितरघात का डर है। कांग्रेस के पास कई क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतारने के लिए उम्मीदवारों का टोटा है। भाजपा ने लगभग सभी सीटों के उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं।

● राकेश साहू, सीहोर (म.प्र.)

कांग्रेस के पास कई अनुभवी

कांग्रेस पार्टी के पास कई बड़े व अनुभवी चेहरे हैं, कांग्रेस उन्हें आगे क्यों नहीं करती। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो राजनीति में माहिर हैं। पिछले कुछ वर्षों से सबसे खराब दौर से गुजर और बिबर रही कांग्रेस को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि वर्किंग कमिटी की बैठक में पार्टी कुछ उभर पाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में पिछले कई दिनों से निगाहें लगाए बैठे थे। कांग्रेस को अपनी पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को रोकना चाहिए और पार्टी को मजबूत करना चाहिए।

● नूपुर सेन, नई दिल्ली



बजट से उम्मीद

कोरोनाकाल के कारण नहीं हो पाने वाला मप्र विधानसभा का सत्र आखिरकार अब आयोजित होने जा रहा है। राजभवन की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र के दौरान शिवराज सरकार अपना बजट भी पेश कर सकती है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए यह बजट अच्छा रहे।

● प्रिया सूर्यवंशी, गुना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



दांव पर दांव

बिहार की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा ने गहमागहमी बढ़ाई है। एक दल से दूसरे दल की टोह में नेता बेचैन हैं तो सियासी दलों के बीच भी अपने-अपने नफे नुकसान का आंकलन चल रहा है। बाहुबली पप्पू यादव और लोजपा के चिराग पासवान ज्यादा सक्रिय हैं। भाजपा की नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषित नीति के बावजूद इस पार्टी के बिहार के ही कई नेता अपनी डफली-अपना राग बजा रहे हैं। सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। कोई लोकसभा चुनाव के नतीजों के मापदंड से सीटों के बंटवारे की दुहाई दे रहा है तो कोई 2015 के विधानसभा चुनाव को पैमाना बनाने के पक्ष में है। जीतनराम मांझी से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को आगाह किया है कि दलित वोट पर अब लोजपा या पासवान परिवार का ही एकाधिकार नहीं है। श्याम रजत जद (एकी) छोड़ राजद में जा चुके हैं। तेजस्वी यादव खुलकर भाजपा से ज्यादा वार अपने मुंहबोले चाचा नीतीश पर कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया है कि नीतीश का भाजपा से तालमेल न हो तो दस सीटें भी नहीं जीत पाएगा जद (एकी)। यानी हर पार्टी और हर नेता दांव पर दांव चल रहा है। अब देखना यह है कि किसका दांव लगता है।

सतह पर गुटबाजी

पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी की जगह सत्ता में आने के ख्वाब तो देख रही है पर उसका अपना कुनबा ही सूबे में एकजुट नहीं है। गत दिनों प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा प्रस्ताव आ गया जिसकी किसी को न उम्मीद थी और न जानकारी। सांसद सुभाष सरकार ने अपने भाषण के बीच एक अनूठा प्रस्ताव पढ़ा-मैं प्रस्तावित करता हूँ कि दिलीप दा को अनुशासनात्मक और चुनावी प्रबंधन समितियों के गठन का अधिकार दिया जाए। दिलीप दा यानी पार्टी के सूबेदार सांसद दिलीप घोष। पार्टी की परंपरा तो ये समितियां आलाकमान को गठित करने का अधिकार देती है। प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए मुकुल राय अलबत्ता थे। आलाकमान कई बार कह चुका है कि चुनाव प्रबंधन का जिम्मा मुकुल राय को मिलेगा। मुकुल राय की हैसियत घटाने का मकसद ही होगा इसके पीछे। पर गुटबाजी तो सतह पर आ ही गई।



घाव पर नमक

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अब काशी और मथुरा की मांग भी उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हालांकि अभी ऐसी मांग सुनाई नहीं पड़ी है जबकि उनके एजंडे में तीनों विवादित धर्मस्थल शुरू से शामिल हैं। विहिप की जगह अब दूसरे धार्मिक संगठन इस एजंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मसलन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने काशी और मथुरा की मुक्ति की मांग कर डाली। कौन नहीं जानता कि परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मुलायम सिंह यादव से खासी घनिष्ठता रही है। अखिलेश यादव उपर के मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरि का मान बढ़ाना कभी नहीं भूले। कांग्रेस से भी हमदर्दी है महंत की। वो 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की मुखालफत कर चुके थे। जबकि ज्यादातर संत मोदी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। लेकिन नतीजा भाजपा के पक्ष में आया तो नरेंद्र गिरि की उपर और भाजपा शासित राज्यों में पूछ घट गई। इसीलिए भाजपाई दबी जुबान से आरोप लगा रहे हैं कि काशी और मथुरा की मुक्ति की मांग महंत नरेंद्र गिरि ने सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा और केंद्र सरकार को उलझन में फंसाने की मंशा से उठाई है। भाजपाई अब महंत पर दागी रईसों से निकटता रखने की शिकायत पर उतर आए हैं। महंत नरेंद्र गिरि का वैसे भी विवादों से पुराना नाता है।

भेंट चढ़ी फेयरवेल पार्टी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कोर्ट के न्यायाधीशों के मध्य कई मुद्दों पर असहमति रहने की परंपरा रही है। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला है कि किसी न्यायाधीश संग बार के संबंध इतने बिगड़ जाएं कि उनको सेवानिवृत्ति के समय बार फेयरवेल पार्टी न दे या फिर फेयरवेल दी जाए या नहीं चर्चा का मुद्दा बन जाए। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को लेकर ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। 2 सितंबर को रिटायर हुए मिश्रा संग वर्तमान बार एसोसिएशन के रिश्ते तलख हैं। प्रशांत अवमानना मामले की सुनवाई करने वाले अरुण मिश्रा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे के आपसी रिश्ते भी अच्छे नहीं बताए जाते हैं। गौरतलब है कि दवे प्रशांत भूषण के इस मामले में वकील भी हैं। ऐसे में पहले तो यह चर्चा जोंरों पर रही कि बार एसोसिएशन न्यायमूर्ति मिश्रा को फेयरवेल पार्टी नहीं देगा। फिर इसका जब खंडन स्वयं बार एसोसिएशन से आ गया तब न्यायमूर्ति मिश्रा की तरफ से सूचित किया गया कि कोविड-19 के चलते वे फेयरवेल समारोह में शामिल नहीं होंगे।

मंत्रियों के पहचान का संकट

कहा जाता है कि मोदी सरकार के कामकाज में मंत्रियों की कोई खास भूमिका नहीं होती है। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि अनेक केंद्रीय मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों का प्रभार है। इसलिए भी लोगों को उनके मंत्रालय को लेकर कंप्यूजन रहता है। स्थिति यह है कि पार्टी के पदाधिकारियों तक को अंदाजा नहीं है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। पिछले दिनों टेलीविजन की एक बहस में ऐसा वाक्या पेश हुआ, जब बहस के पैनल में शामिल आर्थिक जानकार को भी मंत्री का नहीं पता था और भाजपा के प्रवक्ता को भी। बहस में शामिल विपक्षी खेमे के एक व्यक्ति ने कृषि मंत्री का नाम पूछ लिया। आर्थिक मामलों के जानकार को तो कृषि मंत्री का नाम ही नहीं पता था, भाजपा के प्रवक्ता ने भी लटपटाते अंदाज में राधामोहन सिंह का नाम लिया। ध्यान रहे राधामोहन सिंह पिछली सरकार में कृषि व किसान कल्याण मंत्री थे। यह वाक्या दर्शाता है कि केंद्र के मंत्रियों के पहचान का संकट है।

पंच प्यारों का जलवा

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों पंच प्यारों का जलवा हर जगह महसूस किया जा रहा है। दरअसल, ये पंच प्यारे 5 जिलों के कलेक्टर हैं। इन पंच प्यारों का इकबाल इतना बुलंद है कि इनसे अन्य जिलों के कलेक्टर जल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जहां एक तरफ प्रदेश के अधिकांश जिलों के कलेक्टर की हालत पटवारी से भी बदतर हो गई है, वहीं इनका जलवा अभी भी कायम है। प्रशासनिक वीथिका में अफसरों की कानाफूसी से निकलकर यह बात सामने आई है कि उपचुनाव के इस दौर में शासन-प्रशासन ने कलेक्टरों को फुटबाल बना दिया है। रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वहीं घोषणा पर घोषणा हो रही है। कलेक्टरों के सामने घोषणाओं का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। उस पर आलम यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। वहीं 5 जिलों के कलेक्टर ऐसे हैं जिनको डांटना तो दूर उनसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की जाती है। ऐसे में अन्य जिलों के कलेक्टर इस सोच में पड़े हैं कि आखिरकार इन अफसरों ने ऐसा कौनसा तीर मार दिया है, जिससे इनका इकबाल बुलंद है। बताया जाता है कि पंच प्यारों में से चार मालवा जिले में कलेक्टर हैं। वहीं एक ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले में पदस्थ हैं। सूत्र बताते हैं कि इन पांचों को प्रशासन के पावरफुल साहब का साथ मिला है। इसलिए इनका जलवा कायम है। जो अन्य कलेक्टरों के लिए सोच का विषय बना हुआ है।

खुनस में वीडियो वायरल

गत दिनों इंदौर जेल के जेलर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह हनीट्रैप की एक आरोपी के साथ बात करते हुए देखे गए थे। इस पर प्रदेशभर में जमकर बवाल मचा था। आनन-फानन में इस मामले की तस्दीक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने इंदौर जेल का दौरा किया और मामले पर पर्दा डालने के लिए जांच कमेटी बैठा दी। दरअसल, यह वीडियो वायरल होने के बाद यह सवाल उठने लगा था कि कड़ी सुरक्षा वाली इस जेल में किस व्यक्ति ने मोबाइल ले जाकर यह वीडियो बनाया है और बाद में उसे वायरल किया है। सरकार की जांच कमेटी इसकी रिपोर्ट कब देगी यह तो वही जाने, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो जेल के ही एक अधिकारी ने अपने मोबाइल से बनाया था और उसे वायरल किया था। दरअसल, जिन साहब का यह वीडियो वायरल हुआ था उन्होंने उक्त अधिकारी के खिलाफ एक मामले को लेकर स्थानीय अखबारों में खूब खबरें छपवाई थीं। यहां बताते चलें कि जिस अधिकारी ने यह वीडियो वायरल किया था उन्होंने जेलर रहते हुए एक भूमिफिया की जमकर पिटाई की थी। यह मामला अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियों में छा गया। अब उसी का बदला लेने के लिए यह वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया।



डेढ़ करोड़ की लीला

शीर्षक पढ़कर आप भी चकरा गए होंगे। चकराने का मामला भी है। अपने प्रदेश में ऐसे अजब-गजब मामले बराबर आते रहते हैं, जिसे देख-सुनकर हम लोग चकराते रहते हैं। यहां जिस मामले की बात हो रही है, वैसे तो यह मामला पाप और घृणा का है। लेकिन इस पाप और घृणा में भी किस तरह कमाई की जाती है, यह बात इस मामले में सामने आई है। दरअसल, राजधानी में विगत दिनों एक हाईप्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। इसमें यह बात सामने आई थी कि शहर के रसूखदार किस तरह नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करते थे। हालांकि इसमें मुख्य आरोपी को छोड़कर किसी भी रसूखदार का नाम सार्वजनिक नहीं हो पाया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस सेक्स रैकेट में फंसे हर रसूखदार से उनका नाम हटाने के लिए जमकर चंदा वसूली की गई है। बताते हैं कि इस हाईप्रोफाइल मामले में एक मदिरा बनाने वाली कंपनी के नामदार का भी नाम उछला था। जनाब ने इस कामलीला में डुबकी लगाई थी कि नहीं यह तो वही जाने, लेकिन उनको इस लीला से निकालने के लिए एक माननीय को हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि माननीय ने इसके लिए उन जनाब से डेढ़ करोड़ का सौदा किया था। यही नहीं अगर विश्वस्त सूत्रों की मानें तो इनके जैसे कई और नामदारों को इस चक्करघिन्नी में फंसे होने का डर दिखाकर उनसे डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की पूजा ली गई है।

जो ना दे उसका भी भला...

आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। कुछ ऐसा ही हाल है प्रदेश के एक सबसे कमाऊ विभाग के मंत्री का। कहने को तो मंत्रीजी गुणा-भाग में भी माहिर हैं, लेकिन उनका कमाऊ विभाग में गुणा-भाग नहीं चल पा रहा है। बताते हैं कि इस कमाऊ विभाग में तबादले में बड़ा खेल होता है। मालदार जगह पर जाने के लिए अधिकारी-कर्मचारी मुंह मांगी लक्ष्मी की चढ़ोतरी देते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि विभाग में बड़े-बड़े तबादले हो जाते हैं और मंत्री तथा कमिश्नर को बाद में पता लगता है। सूत्र बताते हैं कि यह पूरा खेल प्रशासन के सबसे बड़े साहब और विभाग के बड़े साहब की मिलीभगत से चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि उपरोक्त दोनों अधिकारी विभाग में मंत्रीजी की चलने नहीं दे रहे हैं। स्थिति यह है कि मंत्रीजी को अफसरों द्वारा जो भी चढ़ोतरी मिलती है, वे उसी में खुश हो जाते हैं। वहीं कमिश्नर को तबादले की खबर पत्रकारों के वाट्सएप के मैसेज से चलती है। ऐसे में अब इस विभाग का भगवान ही मालिक है। मंत्री और कमिश्नर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

कुबेर के खजाने पर नजर

सत्ता और संगठन के लिए फंड जुटाने वाले विभाग के रूप में ख्यात एक विभाग के मंत्री इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली के कारण चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि मंत्रीजी कुबेर के खजाने पर नजर रख रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि विभाग में अपनी दादागिरी दिखाते हुए मंत्रीजी ने एक प्राइवेट व्यक्ति को तैनात कर लिया है। उक्त व्यक्ति का काम है कि वह विभाग द्वारा जाने वाली लक्ष्मीजी की डाक का हिसाब-किताब रखे। आलम यह है कि मंत्रीजी के कहे बिना एक भी पाई इधर से उधर नहीं जा रही है, लेकिन मंत्रीजी की पीठ के पीछे पार्टी फंड को जो करोड़ों रुपए जा रहे हैं, उसका हिसाब-किताब कौन रख रहा है, किसी को पता नहीं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी विभाग के अफसरों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने हर अफसर की कुंडली बनानी शुरू कर दी है। यहां बता दें कि उक्त मंत्री पूर्ववर्ती सरकार में भी इसी विभाग के मंत्री रहे हैं। वह जानते हैं कि इस विभाग में किस तरह कमाई की जा सकती है। इसलिए उन्होंने विभाग पर अपनी प्राइवेट टीम का पहरा बैठा दिया है। देखना यह है कि मंत्रीजी का यह पहरा और कितने दिन कायम रहता है।



महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक हैं, उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गुटबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज उनकी पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी सजग भावना क्या है?

● कंगना रनौत



काफिलों से चलने वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सरकार के दिल में डर बैठ गया है कि अब सरकार जाने वाली है। योगीजी का काफिला तो हमारे ख्याल से सबसे बड़ा काफिला है। इतना तो मैंने अपने जमाने में न मुलायम सिंह का देखा, न मायावती और न ही अखिलेश का। जितनी सिक्वोरिटी कम होगी, उतने ज्यादा शहर के हालात से आप वाकिफ होंगे।

● मुनव्वर राणा



गोल्डन एरो स्क्वाड में राफेल के शामिल होने पर बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि राफेल मिराज-2000 को पीछे छोड़ देगा। लेकिन सुखोई मेरा अब भी सबसे पसंदीदा फाइटर जेट है। 4.5 जेनरेशन का फाइटर प्लेन जवानों को मिला। इससे एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी। हमारे जवान अब आधुनिकता के साथ दुश्मनों का सामना करेंगे।

● एमएस धोनी



मैं सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रपति हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेफ्ट का एजेंडा पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है।

● डोनाल्ड ट्रंप



अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह का रिश्ता टॉक्सिक नहीं था। दोनों ने अलग होने के बावजूद एक-दूसरे का सपोर्ट किया है। अंकिता सुशांत के परिवार से बेहद करीब थी और आज भी है। और आज कुछ लोग जिन्हें ना रिया के बारे में पता है और ना ही स्थिति के बारे में वो अंकिता पर बुरी रोशनी डाल रहे हैं। अंकिता ने साफ कहा है कि वो भी जानना चाहती हैं कि आखिर सुशांत ने जो किया उसके पीछे क्या वजह थी। लोगों का दिमाग बहुत छोटा हो चुका है और वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं उनके दुखों को समझती हूँ मगर बिना कुछ जाने किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी कि हमने एक हीरा खोया है। और रही बात 2 सेकंड फेम की तो अंकिता को उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही एक स्टार है।

● रश्मि देसाई

वाक्युद्ध



मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गईं। केंद्र सरकार ने नहीं गिना तो क्या मौत नहीं हुई? मौतें तो बहुत हुईं मगर दुख है सरकार पर असर नहीं हुआ। मजदूरों का मरना जमाने ने देखा, लेकिन एक मोदी सरकार है जिसे खबर नहीं हुई। ऐसी सरकार की क्या जरूरत?

● राहुल गांधी

राहुल गांधी और कांग्रेस आज मजदूरों को लेकर इतनी चिंतित नजर आ रही है, लेकिन वे उस समय कहां थे जब मजदूरों को मदद की जरूरत थी। केंद्र सरकार के साथ ही भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने मजदूरों के लिए जो किया वह बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश ही नहीं विश्व ने देखा कि किस तरह मजदूरों की मदद की गई।

● जेपी नड्डा



म प्र में अब सड़क हादसों की केस स्टडी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में मप्र को चुना है। यह सब सड़क हादसों को रोकने के लिए सुरक्षित उपायों को खोजने के लिए किया जा रहा है। शासन के चार विभाग मिलकर केस स्टडी करेंगे। इस केस स्टडी के लिए आईआईटी मद्रास ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के जरिए सड़क दुर्घटनाओं का रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। चार विभागों की संयुक्त डाटा की समीक्षा के मंथन से सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर हल निकाला जाएगा।

मप्र के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट में 4 विभागों को रखा गया है, जिसमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। इनके हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। केंद्र ने अप्रैल 2021 तक का टारगेट तय किया है। इस दौरान सड़क हादसों का सॉफ्टवेयर पर डाटा अपडेट करने के लिए अधिकारी कर्मचारी और जांचकर्ता को टैबलेट दिए जाएंगे। इस टैबलेट पर डाटा तमाम एजेंसियों से जुटाकर एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास ने सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डाटाबेस नामक एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डाटाबेस तैयार किया है। इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस परियोजना की लागत 258 करोड़ रुपए है।

सिस्टम का मकसद है कि एकीकृत डेटा बेस न केवल सड़क सुरक्षा के तहत अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर आधारित विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय करने में भी सहायता करेगा। इससे राज्य और केंद्र, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारियों को समझने, सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए डाटा-आधारित सड़क सुरक्षा उपायों को विकसित एवं लागू करने में सक्षम होने की उम्मीद है। यह डाटाबेस 'वैज्ञानिक सड़क सुरक्षा प्रबंधन' की दिशा में पहला कदम है।

एकीकृत डाटाबेस एक व्यापक वेब-आधारित आईटी समाधान होगा जो पुलिस, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी विभिन्न एजेंसियों को जांच संबंधी, सड़क इंजीनियरिंग, वाहन स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार एकीकृत डाटाबेस पर प्राप्त विवरणों के माध्यम से विभिन्न प्राधिकारी भारत में सड़क दुर्घटनाओं की गतिशीलता को समझकर प्रवर्तन,



11 जिलों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट

मौत का आंकड़ा हुआ है कम

राज्य सड़क सुरक्षा सेल की प्रभारी प्रज्ञा जोशी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सड़क हादसों में पिछले साल की तुलना में इस साल 6 महीनों के अंदर भारी कमी आई है। हादसे में होने वाली मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और हादसों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जोशी ने बताया कि पुलिस की प्लानिंग आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। हादसों को कम करने और सुरक्षा के उपायों को जारी रखने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के करीब 4 जिले ऐसे हैं, जहां पर कोरोना वायरस के दौर में भी हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन जिलों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हादसों को कम करने और उस पर कंट्रोल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सड़क सुरक्षा सेल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 30 जून 2019 और 2020 की तुलनात्मक अध्ययन में कई खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के शुरुआती छह महीनों में सड़क हादसों की संख्या 27,578 थी, जबकि 2020 में यह संख्या 19,724 हो गई। यानी 28.48 प्रतिशत हादसों में कमी आई है।

इंजीनियरिंग, शिक्षा और आकस्मिकता के क्षेत्र में लक्षित उपायों को लागू कर सकेंगे ताकि देश में सड़क सुरक्षा स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस सिस्टम के लिए 6 राज्यों में मप्र को भी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने चुना है। यह प्रोजेक्ट कर्नाटक, मप्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उप्र में प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सर्वाधिक है। एकीकृत डाटाबेस

के परीक्षण के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा और इसके बाद इसे देशभर में लागू किया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग को 30 हजार से ज्यादा टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। एकीकृत डाटाबेस मोबाइल एप्लिकेशन पुलिस कर्मियों को फोटो और वीडियो के साथ सड़क दुर्घटना के विवरण को दर्ज करने में सक्षम बनाएगा, जिसके बाद उस घटना के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय के इंजीनियर को अपने मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त होगा। वह व्यक्ति दुर्घटनास्थल पर जाएगा तथा उसकी जांच करके आवश्यक विवरण जैसे- सड़क का डिजाइन आदि जानकारियां एकत्रित करेगा।

गौरतलब है कि मप्र में सड़क हादसों की रफ्तार को कोरोना ने रोक दिया है। इस बात की जानकारी पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की राज्य सड़क सुरक्षा सेल की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोनाकाल में सड़क हादसों की संख्या और उससे होने वाली मौत और घायलों की संख्या में कमी आई है। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की राज्य सड़क सुरक्षा सेल की प्रभारी प्रज्ञा जोशी ने बताया कि सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौत और घायलों की संख्या में कोरोना के कारण कमी आई है। कोरोना के कारण प्रदेशभर में लॉकडाउन लगाया गया था। समय-समय पर रियायत जरूर दी गई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से सड़क पर तैनात होकर काम किया।

● लोकेश शर्मा

मप्र का उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए असली इम्तिहान है। सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन धामा है, उनकी जीत-हार ही सिंधिया का भविष्य तय करेगी। अगर सिंधिया सभी को जिता देते हैं तो वे भाजपा में मोदी और शाह के बाद सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। वहीं हार होती है तो उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। इसलिए सिंधिया पूरे प्राण प्रण से चुनावी मैदान में इटे हुए हैं।

मप्र में उपचुनावों को लेकर बिहार चुनाव जैसी ही गहमागहमी बनी हुई है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तरह मध्यप्रदेश में उपचुनावों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे सहित 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने का इंतजार है। ये उपचुनाव इतने अहम हैं कि इनके नतीजों पर ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य टिका हुआ है। नतीजे मनमाफिक न आने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बहानेबाजी न कर सकें, इसलिए भाजपा नेतृत्व उनकी छोटी-छोटी बातों का भी ख्याल रखता आया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में इम्तिहान तो कायदे से अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। तैयारी तो जोरशोर से चल रही है, लेकिन उसमें लोचा नजर आने लगा है। नतीजे तो इम्तिहान के बाद ही आएंगे। लिहाजा भाजपा को पहले से ही रणनीति बदलनी पड़ी है। मध्यप्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होने वाले हैं और इनमें से 16 सीटें ग्वालियर-चंबल इलाके की हैं। ग्वालियर-चंबल अंचल सिंधिया परिवार का बरसों पुराना गढ़ है।

जिन इलाकों में उपचुनाव होना है वहां से भाजपा को फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीच खुद को काफी असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि सिंधिया को पीछे कर पार्टी ने मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा है और सिंधिया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनाव प्रचार से जोड़ दिया है। सवाल ये है कि क्या सिंधिया खुद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर भाजपा कार्यकर्ता सिंधिया को नहीं पचा पा रहे हैं।

भाजपा ने मध्यप्रदेश उपचुनावों को लेकर बड़ा बदलाव ये किया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधिया और शिवराज के ये दौरे भी तभी हो पाएंगे जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच माकूल माहौल तैयार कर चुके होंगे। भाजपा की डिजिटल रैली में अध्यक्ष जेपी नड्डा



सिंधिया का इम्तिहान

क्या विरोधी सिंधिया का करेंगे मन से समर्थन

असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने विधायकों के साथ भाजपा में आए हैं सभी को उन्हीं सीटों से टिकट दिया जाना है जहां से वे भाजपा उम्मीदवारों को हराकर चुनाव जीते थे। फिर तो भाजपा नेताओं को टिकट मिलने से रहा। बात सिर्फ टिकट न मिलने तक होती तो भी दर्द सहन हो जाता, ऊपर से आदेश ये मिल रहा है कि जिन कांग्रेस नेताओं से वे चुनाव हार गए थे अब उनके सपोर्ट में चुनाव प्रचार भी करना है। जयभान सिंह पवैया भी मध्यप्रदेश के उन भाजपा नेताओं में शुमार रहे हैं जो हमेशा ही सिंधिया घराने की राजनीति के आलोचक रहे हैं। जयभान सिंह पवैया के विरोध का जो रवैया माधवराव सिंधिया के जमाने में रहा वही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौर में भी कायम है और ये बात खुले दिल से स्वीकार करने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है। वैसे भी जयभान सिंह पवैया सिंधिया सीनियर और जूनियर दोनों ही के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मैदान में भी दो-दो हाथ कर चुके हैं। पवैया के सामने सबसे बड़ी मुश्किल भाजपा आलाकमान का आदेश है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करना। ये मुश्किल उन सभी भाजपा नेताओं के सामने है जो उन सीटों पर 2018 में चुनाव हार गए थे जहां अब उपचुनाव होने हैं।

ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिल खोलकर तारीफ की थी और तारीफों के मामले में तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी होड़ लगा ली थी, लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर की बातें साबित हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा था।

भाजपा को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ आमना सामना हो रहा है तो वे काफी संकोच महसूस

कर रहे हैं। हो भी क्यों न जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी और चुनाव मुहिम चलाते आ रहे हों, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल हो सकता है वे ही समझ सकते हैं। ऐसी ही मुश्किलें 2015 में बिहार चुनाव के दौरान जेडीयू और आरजेडी कार्यकर्ताओं को हुई थी और 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा कार्यकर्ताओं की भी। सच तो ये है कि जहां कहीं भी ऐसे बेमेल गठबंधन होते हैं या विरोधी दलों के नेता पाला बदलते हैं, कार्यकर्ताओं के सामने

सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। अक्सर यही चुनौतियां भारी भी पड़ती हैं और चीजें कभी वो शकल नहीं ले पातीं जैसी उम्मीद होती है। फिलहाल मध्यप्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है, जाहिर है कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले कार्यकर्ताओं का भी यही हाल हो रहा होगा।

अगस्त, 2020 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्यप्रदेश का तूफानी दौरा किया था। ग्वालियर-चंबल से लेकर इंदौर तक जगह-जगह वो सीनियर भाजपा नेताओं से लेकर भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं से भी मिले, लेकिन लगता है वो उनके मन की बात नहीं पढ़ पाए और उसके हिसाब से उनका डर भी नहीं खत्म कर पाए। हाल ही में भाजपा के ही कई नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आ जाने के बाद अपना हाल कश्मीरी पंडितों जैसा बताया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से तो शिवराज सिंह चौहान को भी ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं कि कुर्सी के लालच में वो समझौता कर चुके हैं। अब दूसरों को क्या पता कि शिवराज सिंह चौहान कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गले में हाथ डाल कर मुस्कुराते हैं। ये सिंधिया ही तो हैं जिनकी जिद के चलते वो मुख्यमंत्री होकर भी अपने कैबिनेट में चार से ज्यादा अपने मन के मंत्री तक नहीं बना पाए। वैसे शिवराज सिंह ऐसे अकेले नेता नहीं रहे बल्कि नरोत्तम मिश्रा से लेकर वीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर तक सभी के लिए हाल एक जैसा ही रहा। मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तो बोल भी दिया कि उनकी सिफारिशों को किसी ने तवज्जो नहीं दी। सिंधिया की हाल की नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अकेले हुई मुलाकात ने तो क्षेत्रीय भाजपा नेताओं का डर और भी बढ़ा दिया था। बहरहाल, अब तय ये हुआ है कि जहां कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने के लिए वो शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जाएंगे। दोनों स्टार प्रचारकों के इलाके में पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जगह-जगह कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके मन में जो सवाल हैं, दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 और 2013 का विधानसभा चुनाव भाजपा नरेंद्र सिंह तोमर की ही अगुवाई में लड़ी थी। माना जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर का जमीनी नेटवर्क काफी तगड़ा है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो सीधे कनेक्ट रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जरिए भाजपा में आए वीडी शर्मा को संघ में भी भरोसेमंद माना जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के



नरोत्तम क्यों रहे नदारद

नरोत्तम मिश्रा भी नरेंद्र सिंह तोमर की तरह मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में माने जाते हैं। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा भाजपा की शिवराज सिंह सरकार में गृहमंत्री हैं। शिवराज सिंह की सरकार बनवाने में नरोत्तम मिश्रा की भी बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस के बागी विधायकों को सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा के ही संपर्क में देखा गया था। ग्वालियर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा नेता के तौर पर पेश किया जा रहा था तो शिवराज सिंह चौहान सहित सारे नेताओं की मौजूदगी के बावजूद लोगों को नरोत्तम मिश्रा की कमी खल रही थी। बाद में भी जब सिंधिया को पीछे कर तोमर और वीडी शर्मा को भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच समझाने के लिए भेजा गया तो भी नरोत्तम मिश्रा को सीन से गायब पाया गया। क्या नरोत्तम मिश्रा की ग्वालियर-चंबल इलाके से गैर-मौजूदगी किसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जुड़ी हुई हो सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में कांग्रेस नेता के रूप में दबदबा रहा है तो नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा का भाजपा नेताओं के तौर पर। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा का मोर्चे से दूर होना एक स्वाभाविक सा सवाल और चर्चा का विषय बन रहा है। नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी चर्चाओं को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सीधे-सीधे खारिज करते हैं। कहते हैं, पार्टी जिसे जहां का जो काम सौंपती है, वो उसे वहां पहुंचकर पूरा करता है। नरोत्तम मिश्रा को भी सफाई देनी पड़ी है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि जिस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठ रहा है उसमें भी वो हजारों कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद थे और अब भी जहां पार्टी भेज रही है वहां का काम कर रहा हूं।

बीच पहुंचकर नरेंद्र सिंह तोमर समझाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब भाजपा के परिवार

का ही हिस्सा हैं और वे लोग भी जनता के बीच सिर उठाकर तभी चल सकेंगे जब उनको सेवा का मौका मिलेगा और ये मौका भी तभी मिलेगा जब पार्टी की सरकार होगी।

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्रिमंडल गठन से लेकर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे तक में भाजपा नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादातर बातें मान ली और यही वजह है कि कहा जाने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से गठित हुआ है। बड़े जिगरे के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथोंहाथ लेने वाली भाजपा के लिए मुश्किल ये हो रही है कि पार्टी के कई नेता अपना हाल कश्मीरी पंडितों जैसा बता रहे हैं -और ऊपर से नागपुर दरबार में अकेले हाजिरी लगाकर ग्वालियर के 'महाराज' ने अलग ही हड़कंप मचा रखा है।

हाल फिलहाल सिंधिया मध्यप्रदेश में उपचुनावों को लेकर खासे एक्टिव देखे गए हैं। ग्वालियर के साथ-साथ इंदौर दौरे में भी सुमित्रा महाजन सहित तमाम भाजपा नेताओं से वो मिले हैं। साथ ही, सिंधिया समर्थकों का दावा है कि ग्वालियर-चंबल संभाग में भाजपा के सदस्यता अभियान में उनकी वजह से हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हैं। असल में राज्य की 27 में से 16 विधानसभा सीटें इसी इलाके से आती हैं जहां उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों के नतीजों पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में भविष्य तय होना है। चूंकि भाजपा में तरक्की का रास्ता नागपुर से ही तय होता है, इसलिए संघ मुख्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हाजिरी उनको दी जाने वाली नई जिम्मेदारियों के लिए ग्रीन सिग्नल भी हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उनके मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं और इस मुलाकात के बाद ये संभावना बढ़ी हुई लगने लगी है।

● कुमार राजेन्द्र

बाहरियों पर भरोसा

उपचुनाव का घमासान शुरू हो गया है। भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। खुद कमलनाथ ने आगर और सांवेर से चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। दरअसल, उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने बिकाऊ बनाम टिकाऊ का नारा दिया है, लेकिन पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा से पहले जिन 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस को अपनों से अधिक बाहरियों पर भरोसा है। सूची में 11 सुरक्षित सीटों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। भाजपा अथवा अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को भी पार्टी ने टिकट दिया है। इससे कांग्रेस का बिकाऊ बनाम टिकाऊ का नारा कमजोर पड़ सकता है। मार्च में मध्य प्रदेश में नाटकीय घटनाक्रम हुआ। इस घटनाक्रम में कांग्रेस के 22 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी।

शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि इस घटनाक्रम के पीछे राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवारी बड़ी वजह बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और अनुसूचित जाति वर्ग के फूल सिंह बरैया उम्मीदवार बनाए गए। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को राज्यसभा की एक ही सीट मिल सकी। भाजपा ने दो सीटें जीतीं। पहली सीट पर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के तीन और विधायकों ने इस्तीफे दिए। दो विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। कुल 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा सितंबर के अंत तक होने की संभावना है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कहते हैं कि पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, वे सभी जीत रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में पंद्रह में से 11 नाम आरक्षित सीटों के हैं। कई चेहरे ऐसे हैं, जो कांग्रेस की खांटी नेता या कार्यकर्ता नहीं माने जाते। उम्मीदवार बनाए गए सत्यप्रकाश सखवार बसपा से विधायक रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए प्रेमचंद्र गुड्डू पुराने कांग्रेसी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा में चले गए थे। सिंधिया के दूसरे करीबी मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ भी दलबदल कर आए कन्हैया लाल अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया



12 सीटों पर कड़ी मशक्कत

प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली बार बिना शोर-शराबे के 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी और अब शेष 12 क्षेत्रों के लिए कश्मकश चल रही है। दूसरी पार्टी से आए कुछ और नेताओं को ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में मौका मिलने की संभावना है तो कुछ सीटों पर पार्टी अपने पुराने नेता या उनके पारिवारिक सदस्यों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के 18-19 सितंबर को ग्वालियर दौरे की संभावना है। मप्र कांग्रेस में पहला अवसर है, जब बिना शोर-शराबे के किसी चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। न प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन के नारे सुनाई दिए, न ही जिलों में बड़ा विरोध दिखाई दिया है। अब पार्टी के सामने 12 बची हुई सीटों जौरा, सुमावली, मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, पोहरी, मुगावली, सुरखी, बदनावर, मांधाता, सुवासरा और बड़ामलहरा पर प्रत्याशियों के नाम तय करने की चुनौती है। मांधाता विधानसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और उनके धुर विरोधी राजनारायण पुरनी के नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस के सामने सबसे ज्यादा कश्मकश ग्वालियर पूर्व सीट को लेकर है। यहां मुख्य रूप से सतीश सिकरवार, राकेश चौहान, संत कृपाल सिंह, देवेन्द्र शर्मा की दावेदारी बताई जा रही है। सतीश सिकरवार को कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उनके चचेरे भाई की दावेदारी भी दूसरी विधानसभा सीट से है तो एक ही परिवार से दो लोगों को उपचुनाव में टिकट मिलने की संभावना कम है।

गया। सिंधिया की करीबी महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए सुरेश राजे 2013 का विधानसभा चुनाव डबरा सीट से भाजपा के टिकट पर लड़े थे। भाजपा प्रवक्ता अशीष अग्रवाल कहते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में संघ लगाने की कोशिश में है। बसपा ग्वालियर-चंबल के इलाके में निर्णायक भूमिका में होती हैं। लेकिन, बसपा छोड़कर दूसरे दलों में जाने वाले नेता परंपरागत वोट बैंक अपने साथ नहीं ला पाए। फूल सिंह बरैया इसका उदाहरण हैं। बरैया, बसपा छोड़ने के बाद भाजपा में भी शामिल हुए, अपना दल भी बनाया। लेकिन, सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस ने उन्हें भांडेर से टिकट दिया है। बसपा से आए प्राणिलाल जाटव को भी परंपरागत वोट के भरोसे कांग्रेस ने करैरा से टिकट दिया है। बिसाहलाल सिंह के भाजपा में जाने से अनूपपुर में विश्वनाथ कुंजाम को मौका दिया। जिला पंचायत के सदस्य हैं। अनूपपुर आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है। ग्वालियर की दो शहरी सीटों में से केवल ग्वालियर में उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के खिलाफ सुनील शर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां ब्राह्मण चेहरा देकर चोंकाया। ग्वालियर पूर्व की सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। पहली सूची में कांग्रेस ने सिंधिया समर्थक पहली पंक्ति के नेताओं को घेरने की कोशिश की है।

● अरविंद नारद

भो पाल का मास्टर प्लान एक बार फिर विवादों में पड़ गया है। इसकी वजह यह है कि मास्टर प्लान में कई विसंगतियां सामने आई हैं। मास्टर प्लान-2031 के ड्राफ्ट में सामने आई ढेरों गलतियों के पीछे बड़ा कारण मौके पर जाकर हकीकत देखने के बजाय सैटेलाइट इमेज (चित्र) एवं जीआईएस बेस्ड सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करना रहा। इसलिए बिलखिरिया, नरोन्ह सांकल एवं कोलुआ खुर्द का हिस्सा नक्शे में हरे रंग में दिखाया गया और टीएंडसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) के जिम्मेदारों ने इसे वन भूमि मान लिया। वास्तविकता में यह कृषि भूमि है, जो 2005 के मास्टर प्लान में भी दर्शाई गई थी। पहले चरण की सुनवाई में जब दर्जनों किसानों ने आपत्ति जताई तो अफसरों की नौद खुली। अब वे समझाइश दे रहे हैं कि जमीन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, समस्या अभी दूर नहीं हुई है।

मास्टर प्लान को लेकर इसी सप्ताह 1731 में से 506 आपत्तियों की सुनवाई पूरी की गई है, जबकि शेष 1225 आपत्तियों की सुनवाई दूसरे चरण में अक्टूबर में होगी। पहले चरण की सुनवाई में अधिकांश आपत्तियां कृषि भूमि को वन भूमि बताने को लेकर रहीं। बिलखिरिया, नरोन्ह सांकल व कोलुआ खुर्द की अधिकांश भूमि को वन भूमि बताया गया है। इसे लेकर 60 से अधिक आपत्तियां लगाई गई थीं। हथाईखेड़ा क्षेत्र के भूखंडों को लेकर भी यही स्थिति रही। इसके अलावा कान्हासैया की जमीन को कृषि क्षेत्र बता दिया गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर, आरटीओ कार्यालय समेत अन्य व्यावसायिक केंद्र यहां पर हैं।

ड्राफ्ट में सड़कों को लेकर भी गफलत सामने आई है। कान्हाकुंज व अकबरपुर की सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर कर दी गई, जबकि मौजूदा स्थिति में चौड़ाई चार मीटर भी नहीं है। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि प्लान से गड़बड़ी नहीं हटी तो भविष्य में सड़क किनारे स्थित उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। अवधपुरी की एक सड़क को मास्टर प्लान में निरस्त किया गया है। इसके विरोध में 154 आपत्तियां लगाई गई थीं। साथ ही 8 सितंबर को हुई ऑनलाइन सुनवाई में लोगों ने सड़क को यथावत रखने की मांग की थी। इसके समर्थन में विधायक कृष्णा गौर भी आई थीं। जिन्होंने सड़क को क्षेत्र की जरूरत बताया था, लेकिन अब दूसरे पक्ष के लोगों ने निरस्त सड़क को प्लान में यथावत रखने की मांग उठाई है।

अवधपुरी तिराहे से खजूरीकलां जाने वाली मौजूदा मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क को नए प्लान में भी बरकरार रखने के निर्णय पर संयुक्त नगर विकास परिषद ने ऐतराज जताया है। परिषद के अध्यक्ष केपी द्विवेदी ने विधायक कृष्णा गौर से मुलाकात कर सड़क को निरस्त करने की मांग

मास्टर प्लान विसंगतियों का पुलिंदा



1225 आपत्तियों की सुनवाई अक्टूबर में

भोपाल मास्टर प्लान-2031 के ड्राफ्ट को लेकर कुल 1731 दावे-आपत्तियां आई थीं। इनमें से 506 आपत्तियों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो चुकी है। शेष 1225 आपत्तियों की सुनवाई अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में होगी। कोरोना संक्रमण के चलते यह सुनवाई भी ऑनलाइन ही होगी। टीएंडसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) के अधिकारियों की मानें तो 100 से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब के आसपास हो चुके अतिक्रमण को लेकर हैं। इसके संरक्षण के लिए भी बड़ी संख्या में लोग सुझाव देंगे। राजधानी की शान बड़ा तालाब चारों ओर से अतिक्रमण से घिरा हुआ है। खानूगांव, बेहटा, भैंसाखेड़ी, बोरवन क्षेत्र, हलालपुर आदि जगह 350 से अधिक पक्के निर्माण हैं, जबकि भदभदा क्षेत्र में भी पहाड़ी काटकर पक्के निर्माण हो रहे हैं। जिम्मेदार हर साल तीन या बांस-बल्ली का अतिक्रमण हटाकर खानापूर्ति जरूर करते हैं। लेकिन, पक्के अतिक्रमण को लेकर अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण तालाब से 50 मीटर के दायरे में भी अतिक्रमण हो चुका है। पिछले दिनों तेज बारिश के दौरान बड़ा तालाब अपनी हद बता चुका है। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में भी बड़े तालाब के संरक्षण व अतिक्रमण को लेकर ढेरों गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसलिए जून-जुलाई में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

की। द्विवेदी और उनके साथ विधायक से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि 153 लोगों की आपत्ति पर 3000 घरों को नहीं तोड़ा जा सकता। प्रतिनिधिमंडल से विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि 153 लोगों की संयुक्त आपत्ति के आधार पर निर्णय लिया गया है। इस पर द्विवेदी ने कहा कि हम 3000 लोगों की मांग पर सड़क निरस्त हुई है। इसके लिए हमने लंबा संघर्ष किया है। हमारी मांग पर ही मास्टर प्लान-2031 के ड्राफ्ट में इस सड़क को निरस्त किया गया था। ड्राफ्ट पर सुनवाई के पहले ही दिन इस सड़क का मुद्दा उठा था। क्रिस्टल आइडियल सिटी और रीगल मोहिनी होम्स सहित आसपास की कुछ अन्य कॉलोनियों के 153 लोगों ने सड़क को बरकरार रखने की मांग की। इस दौरान विधायक गौर ने

भी उनकी मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि यह सड़क इस क्षेत्र की लाइफ लाइन है। इस पर समिति के सचिव ज्वाइंट डायरेक्टर संजय मिश्रा ने सड़क बरकरार रखने की बात कही थी।

उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) और अन्य से भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण और जल निकाय से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्योकुमार और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. एसएस गर्बियाल की पीठ ने चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए एमओईएफ, शहरी विकास विभाग, एमपी वेटलैंड प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किए हैं।

● जितेन्द्र तिवारी

6 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव भाजपा के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। इन 27 सीटों में से मात्र 1 सीट आगर भाजपा के कब्जे वाली है, बाकी पर 2018 में कांग्रेस के विधायक जीते थे। वैसे तो भाजपा को सरकार में बने रहने के लिए मात्र 9 सीटों की जरूरत है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सभी 27 सीटों जीतने का टारगेट प्रदेश सरकार और संगठन को दिया है।

चुनावी तैयारी, संगठन व सरकार की सक्रियता, मैदानी जमावट और लोकप्रिय नेताओं की सूची देखें तो भाजपा उपचुनाव वाली सभी 27 सीटों जीतती नजर आ रही है। लेकिन पार्टी आलाकमान किसी भी खुशफहमी में नहीं रहने वाला है। इसलिए विगत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भोपाल पहुंचे और दो दिनों के मंथन के दौरान मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ नेताओं, संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सख्त लहजे में संदेश दे गए कि हार बर्दाश्त नहीं होगी। संगठन महामंत्री के सख्त रवैए के बाद सरकार के साथ पूरा संगठन चुस्त-दुरुस्त होकर मैदानी मोर्चा संभाल चुका है।

पार्टी के पदाधिकारी जहां चुनावी क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच सक्रिय हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभावार सभाएं कर सौगात बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 15 तो बसपा ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आगर-मालवा से कांग्रेस के चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। इसलिए इस बार उपचुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है।

यह उपचुनाव भाजपा के साथ ही शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व भी इस चुनाव को लेकर चिंतित है। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गत दिनों बीएल संतोष को चुनावी स्थिति जानने के लिए भोपाल भेजा था। उपचुनाव की 27 सीटों का रिव्यू करने आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंत्रियों के रवैए पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस भी मंत्री के क्षेत्र में हारे, उसकी माइंस मार्किंग होगी। जिताने पर सम्मान मिलेगा और जहां भी हार हुई तो उसके कारण सामने आने के बाद गाज भी गिर सकती है। मंत्री ही हार के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे।

चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक व मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बीएल संतोष के सानिध्य में दायित्वों की समीक्षा हुई है। मंत्रियों से कहा गया है कि वे विजय दिलाने का प्रयास करें। बहरहाल, संतोष ने अलग-अलग बैठकों में यह भी साफ किया कि 27 सीटों में 9 दलित वर्ग की सीटें हैं। पिछली बार यहां वोट घटे थे। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस इन सीटों पर



हार बर्दाश्त नहीं

असंतुष्ट बिगाड़ेंगे खेल

बैठक में यह बात भी सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से भाजपा के पुराने नेताओं में असंतोष है। खासकर उन नेताओं में ज्यादा रोष है, जो पिछले विधानसभा में चुनाव हार गए थे। उन सीटों पर उपचुनाव में सिंधिया के लोगों को ही टिकट मिलेगा। ऐसे में इन सीटों से कभी भाजपा के उम्मीदवार रहे लोग अपने सियासी कैरियर को लेकर चिंतित हैं। ग्वालियर पूर्व से भाजपा के उम्मीदवार सतीश सिकरवार ने पार्टी छोड़ भी दी है। इसके बाद भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। बगावत की आहट को देखते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मद्र में एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि भाजपा प्रदेश में अभी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। बीएल संतोष ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जमीनी स्तर पर भी लोगों से फीडबैक लिया। इस दौरान संगठन महामंत्री ने असंतुष्टों और पिछले विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों और उनकी मौजूदा सक्रियता के बारे में बात की। गौरतलब है कि सबसे ज्यादा असंतोष ग्वालियर-चंबल संभाग में है। भाजपा को झटका भी उसी इलाके में लगा है।

भी ज्यादा रखें।

कुछ जगहों से प्रत्याशियों व विधानसभा प्रभारियों की तरफ से संकेत मिले थे कि कुछ नेता काम नहीं कर रहे। इस पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने साफ कर दिया कि शिवराज सरकार मजबूती से चलाने का यह चुनाव है। इसमें प्रत्याशी गौण है, पार्टी प्रमुख है। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि अनूपपुर में रामलाल रौतेल समेत कुछ जगहों पर वे नेता काम नहीं कर रहे हैं, जो खुद चुनाव लड़ सकते थे। इसे भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है। सूत्र बताते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान बीएल संतोष ने भाजपा के साथ ही संघ के पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया।

उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि केवल लेटरहेड पर नाम से ही काम नहीं चलेगा बल्कि सबको मेहनत करना होगी। इसका मतलब साफ है कि सत्ता और संगठन में बैठे लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि वह उपचुनाव में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। विष्णु दत्त शर्मा ने 5 महामंत्रियों की घोषणा की है वह पद तो पा गए हैं अब उन्हें अपनी उपादेयता भी चुनावी चुनौती के बीच साबित करना होगी। पांच नए महामंत्री ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य



अंचल, भोपाल और मालवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रादेशिक फलक पर इन्हें अभी अपनी छाप छोड़ना बाकी है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद पूरे प्रदेश में लोग ना जानते पहचानते हों पर उन्हें अब अपनी पहचान बनाने के साथ ही पार्टी ने जिस भरोसे उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरे उतरने की चुनौती का भी सामना करना है।

रणवीर सिंह रावत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस कारण प्रदेश में किसानों के बीच वह एक जाना पहचाना नाम हैं। शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं तथा पिछड़ा वर्ग से आते हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी नजदीकी हैं। उपचुनाव की चुनौती को देखते हुए उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण माने जाने वाला महामंत्री का पद दिया गया है। एक ओबीसी चेहरा होने के कारण और किसान मोर्चे में उनकी सक्रियता को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हरिशंकर खटीक पहले राज्यमंत्री रह चुके हैं और हाल के विस्तार में मंत्री बनते-बनते रह गए थे, उन्हें पार्टी में महामंत्री बनाकर बुंदेलखंड अंचल का प्रतिनिधित्व दिया गया है। वह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। शरदेंदु तिवारी उस समय प्रदेश में सुर्विख्यों में आए जब उन्होंने चुरहट विधानसभा क्षेत्र में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को पराजित किया। वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी माने जाते हैं और एक युवा ब्राह्मण चेहरा हैं। उनकी लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके दादा चंद्र प्रताप तिवारी खाटी समाजवादी नेता थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। विंध्य की राजनीति में विधायक तिवारी नया नाम नहीं और न ही अनजान चेहरा हैं लेकिन संगठन में उन्हें सीधे महामंत्री का जो पद मिला है उस कसौटी पर उनका कसा जाना अभी बाकी है। कविता

पाटीदार सुंदरलाल पटवा सरकार में कद्दावर मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भेरूलाल पाटीदार की पुत्री हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की समर्थक होने के साथ ही साथ महिला होने के नाते संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संगठन में वे प्रदेश मंत्री और इंदौर जिला जनपद पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह भी ओबीसी हैं तथा इंदौर-उज्जैन संभाग में पाटीदार मतदाताओं की बड़ी संख्या है और कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भी रहती हैं इसलिए उपचुनाव की दृष्टि से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। भगवानदास सबनानी सिंधी समुदाय से आते हैं और भोपाल जिला भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा उमा भारती के कट्टर समर्थक हैं। वह अच्छे संगठक भी हैं। सबनानी उमा भारती के साथ भाजपा छोड़कर जनशक्ति पार्टी में गए और बाद में भाजपा में लौट आए।

उधर, उपचुनाव वाले जिलों में सरकार ने 6 दिन के अंदर 1600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात बांटकर मतदाताओं को गदगद कर दिया है। आगर मालवा, हाटपिपल्या, दिमनी, अम्बाह, मेहगांव, डबरा, भांडेर, पोहरी, सुमावली, जौरा, करैरा, गोहद, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, मांधाता, नेपानगर का दौरा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह सौगात बांटी है। इस दौरान इन नेताओं ने जनता से साफ-साफ शब्दों में कहा कि पिछली सरकार ने आपके साथ जो छलावा और धोखेबाजी की है, उसे भाजपा सरकार दुरुस्त करेगी। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयास से पार्टी सभी 27 सीटें जीतने की स्थिति में है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को जनता सबक सिखाएगी।

● सुनील सिंह

आरक्षित 9 सीटें बनेंगी भाजपा के लिए चुनौती

प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की नजर उन 9 सीटों पर है जो एससी और एसटी कोटे की हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग बहुल वाली इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने फोकस बढ़ा दिया है। 2018 के चुनाव में ये सीटें भाजपा के लिए हानिकारक साबित हुई थीं। लेकिन इस बार पार्टी 27 सीटों में इन 9 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित अम्बाह, गोहद, डबरा, भांडेर, अशोकनगर, सांची, सांवर के साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनूपपुर और नेपानगर में हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर कांग्रेस के चुनाव विन्ध पर जीतने वाले नेता अब भाजपा में आ चुके हैं। उपचुनाव में इनको भाजपा की ओर से टिकट मिलना तय है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के लिए ये सीटें जीतना चुनौतीपूर्ण हैं। भाजपा नेता लालसिंह आर्य के मुताबिक पिछले चुनाव में जिन अनुसूचित जाति वाली सीटों पर भाजपा को नुकसान हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा। अनुसूचित जाति का वोट भाजपा के पक्ष में आएगा। सरकार के हर वर्ग को लेकर लिए जा रहे फैसलों से इस बार का माहौल बदला हुआ है। उपचुनाव से पहले भाजपा की दलित वोटों की चिंता पर कांग्रेस ने पलटवार बोला है। भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि उपचुनाव आते ही भाजपा को दलित वोटों की चिंता सताने लगी है। लेकिन प्रदेश की सत्ता में भाजपा की वापसी के साथ ही दलित अत्याचार तेजी के साथ बढ़ें और अब किसी भी सरकारी सेवा के जरिए दलित वोटों को रिझाया नहीं जा सकता है। दरअसल 27 सीटों के उपचुनाव में भाजपा का टेंशन अनुसूचित वर्ग की सीटों को लेकर है। जो 2018 में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली साबित हुई थीं। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस हो गया है। दरअसल 4 साल पहले एट्रोसिटी एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर-चंबल संभाग में हुआ था। यहां 9 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण सभी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि अब पार्टी इन 9 सीटों पर अपने चेहरों को बदलने के साथ ही दलित वोटों को साधने पर नजर टिकाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी संबल योजना के जरिए एससी वर्ग को सरकार की योजनाओं से जोड़कर अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश में है।

भोपाल में शत्रु संपत्ति का मामला एक बार फिर सुर्रिवियों में है। इस बार भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बेगम अफताब जहां की संपत्ति का मामला सामने आया है। उनका 43 साल बाद एक पत्र सामने आया है, जिसमें उनकी संपत्ति को सरकारी घोषित करने की बात कही गई है।

घरे में शत्रु संपत्ति

मप्र की राजधानी भोपाल के लगभग डेढ़ लाख परिवारों की संपत्तियां एक बार फिर खतरे की जद में है। यदि भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खान की जूनियर बेगम अफताब जहां द्वारा वर्ष 1977 में लिखे गए कथित लेटर पर भरोसा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति कार्यालय ने अमल किया तो लगभग 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित हो सकती हैं। ऐसे में ईदगाह हिल्स, जहांगीराबाद, ऐशबाग, कोहेफिजा, हलालपुर, लालघाटी, बोरबन, बेहटा और लाऊखेड़ी यानी उपनगर बैरागढ़ के दो तिहाई आबादी के क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों की संपत्तियां केंद्रीय सरकार की मिल्कियत हो जाएगी।

दरअसल लगभग 43 सालों बाद एक ऐसा पत्र निकलकर सामने आया है जिसे बेगम अफताब जहां की ओर से भारत सरकार के सचिव और ऑफिसर इंचार्ज कस्टोडियन एनीमी प्रॉपर्टी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिनांक 2 मई 1977 को कराची पाकिस्तान से लिखा जाना उजागर होता है। वैसे बेगम अफताब जहां की मृत्यु वर्ष 2000 में हो चुकी है और नवाब साहब से उनकी कोई भी संतान नहीं है। इस पत्र की प्रति को ज्ञापन के साथ संलग्न करके भोपाल के सुलतानिया रोड रहवासी मधुदास बैरागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, मुख्य सचिव मप्र, भोपाल सांसद प्रजा सिंह ठाकुर और जिला कलेक्टर भोपाल को भेजा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि नवाब भोपाल की जूनियर बेगम अफताब जहां के नाम से भारत देश में विशेषकर भोपाल रायसेन और सीहोर में जहां कहीं भी संपत्तियां हैं उन्हें शत्रु संपत्तियां घोषित करते हुए केंद्र सरकार अपने आधीन ले। क्योंकि अफताब जहां ने 2 मई 1977 को इस संबंध में केंद्र सरकार के सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपनी ओर से सहमति प्रदान कर दी

क्या है शत्रु संपत्ति कानून ?

दरअसल पाकिस्तान और चीन को भारत का शत्रु देश माना जाता है। भारत का इन दोनों देशों से कालांतर में युद्ध होने के दौरान भारत के जो लोग दुश्मन यानी शत्रु देशों में जाकर बस गए और वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने अपने अधीन करने के लिए पहले डिफेंस एक्ट का सहारा लिया और उसके बाद वर्ष 1967 में पूर्ण रूप से एनीमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया गया। इस कानून में दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्तियों को शत्रु संपत्तियां घोषित करने का प्रावधान है। वर्ष 2015 में केंद्र की एनडीए सरकार ने इस कानून में संशोधन करके यह प्रावधान भी किया है कि दुश्मन मुल्क में जाकर बसने वाले लोगों की संपत्तियों पर वसीयत का कानून भी प्रभावशील नहीं होगा।

थी। किंतु इस पर अमल नहीं हो पाने के पीछे भूमिफिया नवाब भोपाल और अफताब जहां के कथित भोपाल में रहने वाले रिश्तेदार और सरकारी अफसरों की मिलीभगत संलिप्त थी। जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाने और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नीयत से पूरे मामले और पत्र को दबाकर रखा था। लेकिन उस राज पर से अब पर्दाफाश हो गया है क्योंकि 2 महीने पहले जून-जुलाई माह में केंद्रीय सरकार का एक अफसर इस पत्र की कॉपी लेकर जिस पर शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई की सील भी लगी है भोपाल आया था और अफताब जहां के नाम की जहां कहीं भी संपत्तियां हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र की थी। लेकिन इसकी भनक भूमिफिया और नवाब के रिश्तेदारों को लग गई थी और उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को दबा दिया है और अफताब जहां के नाम से संपत्तियों को खुद की मिल्कियत होना बताकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और सरकार को 15 हजार करोड़ से

अधिक का नुकसान हो रहा है।

अफताब जहां का पत्र सामने आने के बाद यह बात सामने आई है कि पत्र को अफसरों के साथ मिलीभगत कर दबाकर करोड़ों-अरबों रुपए की धनराशि कमाने का खेल चला है। ज्ञापन में कहा गया है कि अफताब जहां के हिस्से की जमीन पर खानूगांव, रियाज मंजिल, बैरागढ़ और हलालपुरा में लाखों लोग बसे हुए हैं। अकबर हसन, आजम हसन और अनवर मियां ने खुद को अफताब जहां का रिश्तेदार और उनकी संपत्ति का मालिक बताकर गैरकानूनी तरीके से जमीनों की खरीद-फरोख्त की है। इससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। आवेदक ने सरकार से मांग की है कि इन सारी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर सरकार अपने कब्जे में ले।

इसके पहले वर्ष 2013 में भोपाल में शत्रु संपत्ति घोषित होने का मामला सामने आया था। लेकिन तब यह मामला नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी पुत्री आबिदा सुल्तान को नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का एकमात्र उत्तराधिकारी गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होना पाते हुए नवाब भोपाल की समस्त संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। वर्तमान में यह मामला अभी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है और शत्रु संपत्ति कार्यालय के आदेश पर स्टे लगा हुआ है।

घर बचाओ संघर्ष समिति के उपसंयोजक और वकील जगदीश छवानी का कहना है कि मुझे पत्र पर संदेह है। 43 साल बाद यह पत्र कैसे सामने आया। अभी तक इसे कहां दबाकर रखा गया था। बेगम जहां ने इस पत्र को लिखा है, इस पर किस तरह विश्वास किया जाए। आज जिन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने की बात हो रही है उस पर हजारों परिवार रह रहे हैं। ऐसे में हम किसी को उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं होने देंगे। हमने मर्जर की लड़ाई लड़ी है। अब यह लड़ाई भी लड़ेंगे।

● राजेश बोरकर

मप्र सरकार ने 2024 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो को चलाने की घोषणा की है। लेकिन सरकार के सपनों के शहर इंदौर में ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण में पिछले दो साल से ठहराव है। भाजपा की पुरानी शिवराज सरकार से शुरू होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार से होकर फिर भाजपा सरकार में हम हैं। यानी दो साल में तीन

सरकारों ने मेट्रो रेल का राजनीतिक सफर किया, लेकिन परियोजना जहां की तहां खड़ी है। दो साल पहले भाजपा सरकार में परियोजना के पहले चरण के पहले हिस्से के करीब 5.3 किलोमीटर हिस्से का ठेका दिया गया था। इसके बाद एक साल पहले कांग्रेस सरकार ने इसका भूमिपूजन किया था, लेकिन एक साल में 5.3 किलोमीटर तो दूर, एक मीटर रूट भी नहीं बन पाया। परियोजना की घोषणा हुई थी, तब बताया गया था कि इसके पहले चरण के 32.5 किलोमीटर का काम चार साल में पूरा हो जाएगा। बचे हुए दो-तीन साल में परियोजना कैसे पूरी हो पाएगी, समझा जा सकता है।

भोपाल और इंदौर की मेट्रो रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमपीएमआरसी) का गठन किया है। इंदौर मेट्रो के 32.5 किलोमीटर के रूट में अलग-अलग हिस्सों में निर्माण का ठेका दिया जाना है। एमआर-10 पर आईएसबीटी से मुमताज बाग कॉलोनी तक 5.3 किलोमीटर के पहले हिस्से का टेंडर सितंबर 2018 में दिलीप बिल्डकॉन को दिया जा चुका है। इसके बाद सितंबर, 2019 में इस रूट के लिए एमआर-10 ब्रिज के पास ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भूमिपूजन भी कर दिया। इसके 6 महीने बाद ही सरकार बदल गई। प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार है। मेट्रो रेल परियोजना दोनों नेताओं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन एमपीएमआरसी का तकनीकी अमला कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रहा है।

एमपीएमआरसी ने दोनों रेल परियोजनाओं के लिए विदेशी कंपनी को 600 करोड़ रुपए से अधिक में कंसल्टेंसी का ठेका दिया हुआ है। सवाल उठ रहा है कि इतनी महंगी कंसल्टेंसी के बाद भी अब तक इंदौर में मेट्रो रूट का अलाइनमेंट और डिजाइन तय नहीं हो पाया है। इस कारण ठेका कंपनी भी काम शुरू नहीं कर पा रही है। प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट से लेकर कोठारी मार्केट तक करीब साढ़े छह किलोमीटर का रूट अंडरग्राउंड रहेगा। अंडरग्राउंड रूट के लिए भी अब तक जियो टेक्निकल सर्वे नहीं हुआ है। इसे लेकर एमपीएमआरसी के टेक्निकल डायरेक्टर



इंदौर में ठहराव, भोपाल में रफ्तार

इन बाधाओं को अभी किया जाना है दूर

हबीबगंज नाका पर मेट्रो सिविल वर्क में कई बाधाएं सामने आ रही हैं। यहां नगर निगम की पाइपलाइन है। इसके अलावा बीएसएनएल की लाइन भी बाधा है। रेलवे की बाउंड्रीवॉल को भी पीछे नहीं किया गया। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क की ओर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जैन मंदिर के सामने स्थित पेट्रोल पंप को लेकर निर्णय नहीं लिया गया। बिजली ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग नहीं की गई। हबीबगंज स्टेशन की ओर इलेक्ट्रिक लाइन व पोल नहीं हटाए गए। करोंद से एम्स के बीच एक भूमिगत स्टेशन बनाया जाएगा। यह सुभाष नगर फाटक के पास हो सकता है। स्टेशन तक जाने के लिए भूमिगत टनल का निर्माण भी करना होगा। स्टड फार्म की जमीन पर मेट्रो डिपो का निर्माण प्रस्तावित है। स्टेशन, टनल का निर्माण शुरू करने के पहले जियोटेक्निकल स्टडी कराई जा रही है। इस पर 3.65 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के बाद स्थान फाइनल किया जाएगा।

जितेंद्र दुबे और जीएम मनीष गंगारेकर की लापरवाही सामने आ रही है। जियो टेक्निकल सर्वे का टेंडर एक बार हो चुका था, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हो पाया है।

एमपीएमआरसी के टेक्निकल डायरेक्टर जितेंद्र दुबे कहते हैं कि इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन का काम शुरू होगा। कोरोना के कारण काम रुका था, लेकिन अब जल्द गति पकड़ेगा। अलाइनमेंट करना है, लेकिन डिजाइन का काम ठेकेदार को ही करना है। अंडरग्राउंड ट्रेक के जियो टेक्निकल सर्वे का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा, यह प्रक्रिया में है। एमपीएमआरसी के जीएम मनीष गंगारेकर कहते हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मुझे

कुछ नहीं कहना है। मुझे जो काम दिया गया है, वह कर रहा हूं। इससे ज्यादा बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं।

वहीं राजधानी में कोरोना के चलते ठप पड़ा हुआ मेट्रो का काम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। एम्स से सुभाष नगर के बीच बनाए जा रहे एलिवेटेड रूट में अब तक 80 पिलर बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं सुभाष नगर फाटक के पास तो इन पिलर में गर्डर डालने का काम भी शुरू हो गया है। पिछले तीन दिन में करीब चार गर्डर इस रूट पर डाले जा चुके हैं। जल्द ही एम्स के पास स्थित रूट में भी काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि कान्हासैया में पिलर बनाने और गर्डर का काम निरंतर चल रहा है। मैदामिल रोड पर काम तेजी से चल रहा है। पहले रूट में फिलहाल सुभाष नगर से एम्स तक एलिवेटेड रूट का निर्माण दिलीप बिल्डकॉन कर रहा है। इस पर 277 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनी ने एम्स की तरफ से पिलर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। भोपाल में एम्स से करोंद और डिपो चौराहा से रत्नागिरी तिराहा तक मेट्रो रूट बनाया जाना है।

2023 तक एम्स से सुभाष नगर तक का काम हर हाल में पूरा हो जाएगा। इसकी कुल लागत 6941 करोड़ 40 लाख रुपए है। मेट्रो प्रोजेक्ट में केंद्र व राज्य सरकार की 20-20 फीसदी की हिस्सेदारी होगी। बाकी राशि मप्र मेट्रो रेल कंपनी लोन, पीपीपी मोड व अन्य स्रोत से जुटाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में आने वाला करीब 250 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी। इसके लिए यूरोपियन इन्वेस्ट बैंक से लोन लिया जाना है। इधर, बीते दिनों मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए अगस्त 2023 तक एम्स से सुभाष नगर तक का मेट्रो का काम पूरा होने का दावा किया गया है। हालांकि, इसमें कई रुकावटें हैं, जिन्हें अभी दूर किया जाना बाकी है।

● विकास दुबे

म प्र में अवैध खनन एक ऐसा रोग हो गया है, जिसकी जितनी दवा की जाती है, वह उतना बढ़ता जाता है। यानी सरकार नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर जितनी सख्त हो रही है, नदियों का सीना उतना ही छलनी हो रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि नर्मदा नदी में अवैध खनन करने

नदियों का सीना छलनी

वालों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज होगा, लेकिन इसके बावजूद नदी को छलनी किया जा रहा है। नर्मदा ही नहीं बल्कि लगभग सभी नदियों में रेत का अवैध खनन जोरों पर है। शासन-प्रशासन की नाक के नीचे लगातार अवैध खनन हो रहे हैं। कभी-कभार कुछ छोटे माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है।

मप्र उन राज्यों में शामिल है, जहां अवैध खनन बड़े स्तर पर होता है। यहां कई जगह अवैध खनन चोरी-छिपे, तो कई जगह सीना ठोककर होता है। माफिया प्रदेश की प्रत्येक नदी में सक्रिय हैं। अकेले नर्मदा नदी से करीब एक हजार डंपर रेत प्रतिदिन चोरी-छिपे निकाली जा रही है। यह सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद सहित अन्य जिले के सीमावर्ती इलाकों में बेची जा रही है। इसमें से औसतन 400 डंपर रेत प्रतिदिन भोपाल आ रही है। 300 डंपर का स्टॉक किया जा रहा है। सारी रात नेशनल हाईवे-69 (औबेदुल्लागंज-नागपुर) पर रेत के डंपरों का रेला चलता है। मप्र की नदियों से रेत चोरी की यह स्थिति तब है, जब कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। अगर राज्य की सभी नदियों से निकलने वाली रेत की बात करें तो प्रतिदिन करीब 1600 डंपर रेत चोरी हो रही है।

प्रदेश में आम दिनों में प्रतिदिन 3500 से 4000 डंपर रेत बाजार में पहुंचती है, लेकिन खनिज निगम द्वारा नीलाम की गई 1450 खदानों में उत्खनन शुरू नहीं होने और लॉकडाउन की वजह से रेत की किल्लत शुरू हुई तो माफिया सक्रिय हो गए। नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा सहित प्रदेश की तमाम नदियों से रेत निकाली जा रही है। चोरी-छिपे आ रही रेत के दाम भी मनमाने हैं। माफिया 18 से 20 हजार रुपए में मिलने वाली एक डंपर रेत 32 से 36 हजार रुपए में बेच रहे हैं। भोपाल की ही बात करें तो यहां प्रतिदिन औसतन 400 डंपर रेत आ रही है। इसमें से महज 100 डंपर रेत बाजार में जाती है। शेष रेत बारिश के मद्देनजर स्टॉक की जा रही है ताकि वर्षाकाल में नदियों के घाट बंद होने के बाद मनमाने दामों पर बेची जा सके।

मप्र में अवैध रेत के काले कारोबार की व्यापकता का आंकलन इसी से लगाया जा



सरकार पर दोहरी मार

प्रदेश के रेत कारोबार में माफिया हमेशा से सक्रिय रहे हैं पर उनकी मौजूदा सक्रियता राज्य सरकार को भी भारी पड़ रही है। सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। कोरोना ने भी कमर तोड़ दी है। ऐसे में रेत से बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद थी तो माफिया ने कब्जा कर लिया। अब इस मामले में सरकार जल्दी नहीं चेती तो खदानों को तीन साल के लिए ठेके पर लेने वाले भी हाथ खड़े कर देंगे। मप्र सरकार की खनिज पॉलिसी धरी की धरी रह गई है। विभाग ने रेत ट्रकों की मॉनीटरिंग, चोरी की रेत पर अंकुश लगाने के लिए जीपीएस, पोर्टल सहित तमाम प्रबंध किए पर अब कुछ काम नहीं आ रहा।

सकता है कि यहां से उप्र, राजस्थान, महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रेत जाती है। छतरपुर सहित उप्र से सटे क्षेत्र से निकली केन नदी पर स्थित घाटों से फिर एक बार माफियाओं द्वारा रेत का उत्खनन शुरू कर दिया गया है। कई घाटों पर रेत माफियाओं ने अपनी मशीनें उतार दी हैं और अब मशीनों से बड़ी मात्रा में रेत निकालकर ट्रकों तथा डंपरों में भरकर उप्र भेजा जा रहा है। इस काले कारोबार को लेकर पुलिस व खनिज महकमा पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने के सीधे आरोप लग रहे हैं।

गौरिहार थाना की पहरा चौकी क्षेत्र में स्थित केन नदी के बरूआ परेई रेत खदान पर पोकलेन मशीनों से बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन चल रहा है। यह रेत निकालकर उप्र भेजी जा रही है, रोज करीब 30 ट्रकों व डंपरों में रेत लोड कर उत्तर प्रदेश की सीमा में भेजी जा रही है। रेत के इस काले कारोबार को लेकर पहरा चौकी पुलिस सहित खनिज अधिकारियों द्वारा संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि पहरा चौकी प्रभारी प्रदीप सर्राफ किसी भी प्रकार रेत माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप को नकारते हुए कहते हैं

कि वह लगातार अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।

गोयरा थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत हाजीपुर से निकली केन नदी के महुआ कछार गांव के केवट समाज के गरीब लोग सब्जी की फसल लगाते हैं। इसे बेचकर अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। रेत माफिया ने रेत उत्खनन के लिए इन गरीब किसानों की फसलें मशीनों से उजाड़ दी हैं। केन नदी के महुआ कछार घाट से शाम होते ही एलएंडटी मशीनें उतारकर रेत निकाली जाती है और रोजाना करीब डेढ़ दर्जन ट्रकों से यह रेत नदी के दूसरी ओर नरैनी होकर उप्र के लखनऊ और कानपुर शहरों में भेजी जाती है। इसके लिए रेत माफिया द्वारा पहले से पुलिस से सेटिंग कर ली जाती है। यही कारण है कि एक तो इन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर कार्रवाई की नौबत आती है तो इन्हें पहले से अलर्ट कर दिया जाता है।

अवैध खनन की अनदेखी की सबसे बड़ी वजह है इसमें होने वाला भारी मुनाफा। लागत के मुकाबले इस धंधे में कई गुना लाभ है। पुलिस, प्रशासन, नेताओं को मुनाफे का हिस्सा देने के बावजूद इससे जुड़े लोग जल्द ही करोड़पति हो जाते हैं। असल में, पिछले एक-डेढ़ दशक में महानगरों के इर्द-गिर्द जिस तेज गति से बहुमंजिली इमारतों, विशाल शॉपिंग मॉल्स और शानदार आवासीय परियोजनाओं के निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके लिए कच्चे माल यानी रेत, बजरी और अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ी है। इस जरूरत को साधने के लिए राज्य सरकारें खनन के वैध ठेके आवंटित करती हैं, पर उससे माल महंगा हो जाता है और पुलिस, प्रशासन व नेतागण समेत खनन माफिया के लिए भारी कमाई के अवसर भी सिकुड़ जाते हैं। लिहाजा, अवैध खनन कभी तो चोरी-छिपे और कभी गठजोड़ कर खुलेआम किया जाता है।

● रजनीकांत पारे

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार से सरकार की आमदनी का प्रमुख जरिया है। देशभर में लागू हुए जीएसटी कानून के बाद यह उम्मीद जताई गई थी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टैक्स चोरी रोकने में यह फॉर्मूला कारगर साबित होगा। लेकिन हाल ही में स्टेट जीएसटी की रिपोर्ट इन तमाम दावों के उलट ही आई है। जबलपुर स्थित स्टेट जीएसटी दफ्तर से पेश की गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है कि महाकौशल के 8 जिलों में पिछले 17 महीनों में जीएसटी चोरी के 190 मामले दर्ज किए गए। इसमें एक अरब से ज्यादा का टैक्स चुराने की कोशिश की गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कार्रवाई में 153 बोगस जिन्हें हम जाली या फिर शेल कंपनियां भी कह सकते हैं, उनका पता चला है। शेल कंपनियों के माध्यम से करोड़ों के वारे-न्यारे भी किए गए। ना केवल मध्यप्रदेश बल्कि देशभर के विभिन्न राज्यों में इन शेल कंपनियों से व्यापार कर आदान-प्रदान भी किया गया।

बेशक कार्रवाई इनमें से सिर्फ 153 फर्म पर ही की गई लेकिन इनका बड़ा जाल देशभर में फैला हुआ है। स्टेट जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर सुनील मिश्रा ने बताया कि विभाग की इन 8 जिलों में टैक्स चोरी करने वालों पर पैनी नजर है। अब जब अनलॉक के बाद फिर व्यापार पटरी पर दौड़ पड़ा है तो उसके बाद भी छिंदवाड़ा और जबलपुर में 8 बड़ी कर चोरी के मामले सामने आए हैं। स्पष्ट है कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों का एक बड़ा गिरोह टैक्स चुराने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है।

टैक्स चोरी और बोगस कंपनियों के जरिए व्यापार चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे व्यापारी ये वजह बताते हैं कि टैक्स की जटिलता के कारण ये समस्या खड़ी हो रही है। व्यापारियों का कहना है सिंगल टाइम टैक्स योजना अगर लागू होती है तो इससे टैक्स चोरी पर पूरी तरह रोक लग सकती है। सिंगल पॉइंट एंड सिंगल टाइम टैक्स की ओर अगर सरकार ध्यान देगी तो ना केवल इससे व्यापार प्रगति करेगा बल्कि चोरी जैसे संगीन मामलों में भी अप्रत्याशित कमी आ सकती है। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स चोरी और आमदनी छुपाने के लिए पूरे महाकौशल अंचल में हवाला कारोबार जमकर फला-फूला था। कटनी से लेकर जबलपुर और दिल्ली के बीच उजागर हुआ हवाला कांड पार्ट-2 किसी से छुपा नहीं है। बहरहाल जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे टैक्स चोरों पर लगाम बेहद जरूरी है।

मप्र सहित पूरे देश में एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और तब से अभी तक मप्र जीएसटी विभाग द्वारा 5 हजार करोड़ रुपए

कोरोनाकाल में देश आर्थिक बढहाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार के सामने कमाई का सबसे बड़ा जरिया जीएसटी है। लेकिन मप्र सहित देशभर में जीएसटी की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों मप्र में कई जगह छापामार कार्यवाही कर जीएसटी चोरी पकड़ी गई।

अरबों की जीएसटी चोरी



1800 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, शासन ने मांगी रिपोर्ट

वाणिज्यिक कर विभाग की टैक्स रिसर्च विंग की जांच में पकड़े गए 1800 करोड़ के जीएसटी घोटाले से मप्र समेत 7 राज्यों की सरकार सकते में है। मप्र सरकार ने घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंदौर से मांग ली है। घोटाले की सभी सातों राज्यों में जांच तेज हो गई है। इनमें मप्र के अलावा उप्र, दिल्ली, बिहार, असम, हिमाचल, हरियाणा आदि राज्य हैं। भोपाल की फर्म मेसर्स एमपीके ट्रेडर्स द्वारा जिन-जिन कंपनियों ने ट्रांजेक्शन बताए हैं, उन सभी को जांच के दायरे में लिया जा रहा है। इस कंपनी की जांच में मौके पर कुछ नहीं पाया गया है। ट्रांजेक्शन से पता चला है कि कंपनी ने 29 जनवरी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था।

से ज्यादा के फर्जी बिलिंग के मामले पकड़े जा चुके हैं। इसमें 700 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का अनुमान है। दिसंबर 2018 में वाणिज्यिक कर विभाग ने फर्जी कंपनियों के रैकेट पर छापे मारे थे। इसमें 1200 करोड़ से अधिक की फर्जी बिलिंग पाई थी। सभी कंपनियां बोगस थीं। इसमें 100 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला मिला था। जुलाई 2019 में विभाग ने

पूरे प्रदेश में लोहा कारोबार करने वाली 650 से ज्यादा कंपनियों पर छापे मारे। इसमें 285 बोगस निकली थीं। इसमें 1150 करोड़ की फर्जी बिलिंग थी। साल 2019 में ही छोटी ग्वालटोली सहित अन्य जगहों पर कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की फर्जी बिलिंग सामने आई थी। एक कर सलाहकार ने आत्महत्या भी की थी। मार्च 2020 के पहले सप्ताह में हुई कार्रवाई में अभी तक 1800 करोड़ की फर्जी बिलिंग का मामला सामने आ चुका है, जो ढाई हजार करोड़ से अधिक का हो सकता है। कंपनी ने 23 दिन में 20 फरवरी तक बंद होने से पहले ही करीब 600 करोड़ के बिल काट दिए। कंपनी ने ई-वे बिल के माध्यम से जिन वाहनों से माल का परिवहन बताया, इसमें अधिकांश फर्जी हैं। ये नंबर कैब, ऑटो, टैम्पो आदि के पाए गए हैं।

जानकारों का कहना है कि वैट एक्ट की तरह ही जीएसटी में भी व्यापारी के रजिस्ट्रेशन पर नियंत्रण होना जरूरी है और इसके लिए फिर से भौतिक सत्यापन की शर्त लानी चाहिए। साथ ही ई-वे बिल की पात्रता भी धीरे-धीरे बढ़ाई जाए, जिससे बड़े घोटाले रोके जा सकेंगे। साथ ही किसी भी संदिग्ध कंपनी, कारोबारी के जीएसटी नंबर को तत्काल निलंबित करने के अधिकार विभाग को होने चाहिए।

● राकेश ग्रोवर

म प्र सरकार ने रबी सीजन में रिकार्ड गेहूं खरीदी करके किसानों को मालामाल कर दिया। इससे उत्साहित होकर किसानों ने खरीफ की बुवाई भी खूब की है। लेकिन मौसम की मार ने उनपर कुठाराघात कर दिया है। प्रारंभिक आंकलन में प्रदेश के 24 जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से साढ़े 9 हजार करोड़ रुपए की फसल और अधोसंरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। 11.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 11 लाख 34 हजार किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। 60 हजार मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 8 हजार 442 गांवों में नुकसान हुआ है। सड़क, बिजली के खंभे, पुल-पुलिया सहित अन्य संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रारंभिक आंकलन के बाद प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

उधर, केंद्रीय अध्ययन दल ने मप्र के प्रभावित जिलों का दौरा कर क्षति का आंकलन किया है। केंद्रीय संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री की अगुवाई में आए दल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर खेतों का मुआयना किया और किसानों तथा अधिकारियों से बात कर नुकसान का आंकलन किया। जिसमें यह बात सामने आई कि प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण 24 जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 13 हजार 344 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उज्जैन, खरगोन, खंडवा, विदिशा, निवाड़ी, नरसिंहपुर, सिवनी जिलों में 22 हजार 546 लोगों को उनके निवास स्थान से हटाकर सुरक्षित किया गया। 231 राहत शिविरों में लोगों को ठहराया गया। सड़क, पुल-पुलिया और पशुओं को भी नुकसान पहुंचा है। जनहानि न हो इसके प्रयास किए गए थे, जिसमें सफलता भी मिली।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय दल से आग्रह किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण करने और प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा करने के बाद क्षति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उधर, अधिकारियों द्वारा अध्ययन दल के समक्ष अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर राजस्व विभाग ने प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें सभी तथ्य रखे गए। गौरतलब है कि प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से पहले सोयाबीन की फसल को बड़े पैमाने पर यलो मोजेक, इल्ली सहित अन्य रोग लगने से नुकसान पहुंचा। 17



साढ़े 9 हजार करोड़ का नुकसान

लाख से ज्यादा किसानों की 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की फसल प्रभावित हुई है। सरकार अपने स्तर पर फसल बीमा और राहत राशि से नुकसान की भरपाई दिलाने का काम कर रही है। कृषि और राजस्व विभाग नुकसान का आंकलन कर रहा है। इसके लिए अलग से केंद्रीय अध्ययन दल भेजा जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अध्ययन दल को बताया कि 28-29 अगस्त को अतिवृष्टि से पानी खेतों और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच गया था। सेना और अन्य राहत दलों ने दिन-रात काम किया। 12 जिले गंभीर और 23 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हुए। में स्वयं 48 घंटे नहीं सोया। प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, पेयजल, दवा और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने आए केंद्रीय दल ने हरदा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर क्षति का अवलोकन किया। उन्होंने माना कि क्षेत्रों में व्यापक रूप से नुकसान हुआ है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने अतिवृष्टि और बाढ़ के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राहत कार्यों से

अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय दल से प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दिए जाने की मांग की।

केंद्रीय दल ने हरदा जिले के हंडिया के मालपौन में हुई क्षति का नजरी मुआयना किया। गांव में अधिकांश मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मंत्री पटेल ने केंद्रीय दल को अवगत कराया कि अतिवृष्टि से नर्मदा नदी में पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। परिणामस्वरूप हरदा जिले के कई गांवों में पानी भर गया और फसलें जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हो गईं। कृषि मंत्री ने बताया कि बाढ़ से क्षति का प्रारंभिक अनुमान लगभग 10 हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने केंद्रीय दल से कहा कि कोरोना संकट में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। यदि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज प्रदेश को मिल जाएगा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास और बाढ़ पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए बेहतर इंतजाम करने में प्रदेश सरकार को मदद मिल सकेगी। किसानों की उम्मीद है कि जल्द ही उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी।

● प्रवीण कुमार

कर्ज लेकर बोई थी फसल... बाढ़ व अतिवृष्टि ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा

अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय दल ने विभिन्न जिलों का दौरा किया। केंद्रीय दल रायसेन, गैरतगंज और गौहरगंज तहसील में बाढ़ और अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचा तो किसानों ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। दल में शामिल अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर उनकी बात को सुना और उन्हें सहायता दिलाने का भरसा भी दिलाया। केंद्रीय दल में शामिल सौरभ चन्द्र दुबे डायरेक्टर एनआरएलएम, हरिशंकर मिश्रा अपर आयुक्त (आईएएस) व सुमित कुमार सीनियर इंजीनियर आरआरडीए शामिल थे। मेढकी गांव के भगवान सिंह लोधी और कैलाश लोधी ने बताया कि कर्ज लेकर सोयाबीन की फसल बोई थी। बेतवा में आई बाढ़ ने उनके खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल को नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं खेत में बने मकान में रखा खाने-पीने और गृहस्थी का सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया। गांव के विनोद कुमार ने बताया कि उसने तीन प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए कर्ज लेकर तीन एकड़ में धान लगाई थी, जो बाढ़ के पानी में बह गई है। फसल बर्बाद होने से अब उसका कर्ज कैसे चुकता होगा, इसको लेकर परेशान है।

जै से-जैसे दुनिया हाईटेक होती जाती है, वैसे-वैसे जालसाजों के जाल में फंसती जा रही है। मद्र सहित देशभर में सायबर क्राइम अब आम बात हो गई है। रोजाना लोग ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही एक गिरोह भोपाल की सायबर क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है। पुलिस ने हाईटेक जालसाज गिरोह के मुखिया समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो युवतियां शामिल हैं। यह गिरोह फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी करता था। गिरोह का मुखिया अपनी मंगेतर के साथ मिलकर अब तक 10 हजार लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। क्राइम ब्रांच को अब तक ऐसी 12 वेबसाइट्स का पता चल चुका है और ठगी का शिकार हुए एक हजार लोगों से संपर्क कर चुकी है।

सायबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक जनवरी में पद्मेश सिंह ने शिकायत की थी कि दिसंबर 2019 में www.swiftfinance.in द्वारा पर्सनल लोन देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी डेविड कुमार जाटव, नेहा भट्ट और मनीषा भट्ट को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एक साथी कमल कश्यप फरार है। आरोपियों के कब्जे से 6 लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, 21 पेन ड्राइव, 8 एक्टिवेटेड सिम, 19 डेबिट कार्ड और वेबसाइट संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी डेविड फर्जी वेबसाइट डेवलप कर इनका गूगल के माध्यम से विज्ञापन देता था। जब ग्राहक लोन के लिए अपनी पर्सनल डीटेल अपलोड करते थे, तब कंपनी के कॉल सेंटर से उन्हें कॉल करके युवतियां उनसे अलग-अलग चार्जस के नाम पर 30-40 हजार रुपए फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेती थीं। आरोपी औसतन 1000-1200 लोगों को ठग कर वेबसाइट को दो से ढाई महीने में बंद कर देते। गिरोह ने दो कॉल सेंटर नोएडा उप्र में डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह के किराए पर ले रखे थे। 10-15 हजार रुपए मासिक वेतन पर यहां युवतियों को रखा जाता था जो हर ग्राहक का रिकॉर्ड साफ्ट कॉपी में एक्सल में नोट करती थीं। इनका परीक्षण करने पर खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 10 हजार लोगों से 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है।

आरोपी फर्जी वेबसाइट का गूगल ऐड के माध्यम से विज्ञापन देते थे। इस पर ग्राहक लोन लेने के लिए अपनी पर्सनल जानकारी डालते थे। जानकारी के अनुसार कंपनी के कॉल सेंटर से ग्राहकों को लड़कियां कॉल करती थीं। लोगों से प्रोसेसिंग फीस, सिक्थीरिटी डिपोजिट, जीएसटी एवं वनटाइम ट्रांजेक्शन के नाम पर अलग-अलग चार्ज के लिए करीब 40 हजार रुपए ऑनलाइन जमा करवाते थे। एक वेबसाइट करीब ढाई माह ही चलाते थे। इस दौरान करीब 12 लोगों को

हाईटेक जालसाजी



9 महीने लगे पकड़ने में

एडीजी भोपाल उपेंद्र जैन ने बताया कि जनवरी 2020 में आवेदक पद्मेश सिंह ने शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 में www.swiftfinance.in पर पर्सनल लोन का विज्ञापन देखा। कॉल करने पर आरोपियों ने बहुत कम दर पर लोन दिलाने का भरोसा दिलाया। उसके बाद उन्होंने अलग-अलग खातों में रुपए जमा करवा लिए। रुपए पहुंचने के बाद वेबसाइट दिखना बंद हो गई। उनकी शिकायत की जांच में सायबर क्राइम ब्रांच को 9 महीने तक मेहनत करनी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने नोएडा से मुख्य आरोपी डेविड कुमार जाटव उसकी मंगेतर नेहा भट्ट और उसकी बहन मनीषा भट्ट को गिरफ्तार किया। उनका एक साथी कमल कश्यप नाम का चौथा आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कॉल सेंटर और ठगी की वारदात करने के लिए उपयोग दस्तावेजों के साथ ही उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से कॉल सेंटर और ठगी की वारदात करने के लिए उपयोग दस्तावेजों के साथ ही उपकरण भी जब्त किए हैं।

शिकार बना लेते थे। हर महीने फर्जी बैंक खातों एवं सिम कार्ड बदल देते थे।

आरोपियों ने नोएडा में दो कॉल सेंटर किराए पर ले रखे थे। इनका 1.50 लाख रुपया एक महीने का किराया था। इसमें 10 से 15 हजार

रुपए के वेतन पर 30 लड़कियों को रखा गया था। लड़कियों को प्रत्येक ग्राहक का रिकॉर्ड साफ्ट कॉपी में एक्सल में नोट करना होता था। इनसे अब तक करीब 10 हजार लोगों का रिकॉर्ड मिला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह लैपटॉप, 25 मोबाइल फोन, 21 पेन ड्राइव, 8 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 19 डेबिट कार्ड, 3 रेंट एग्रीमेंट संबंधी दस्तावेज, 3 वेबसाइट संबंधी दस्तावेज, 1 राउटर मय मोडेम मय इंटरनेट कंटेनर व एक बलेनो कार जब्त की है।

मद्र में पकड़े गए सायबर ठगों से इस बात का खुलासा हुआ है कि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं, जहां पर सायबर गैंग सक्रिय है। इस गैंग के लोग झारखंड में बैठे-बैठे ही भोपाल समेत दूसरे जिलों के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। स्टेट सायबर सेल ने गुना-शिवपुरी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। यह मॉड्यूल भी झारखंड के मॉडल की तरह बैंकिंग फ्रॉड का काम करता था। इस मॉड्यूल का तार पूरे देशभर से जुड़ा है। इसके अलावा भोपाल सायबर क्राइम भी समय-समय पर ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन ठगों के तार भी झारखंड के अलावा दिल्ली राजस्थान और दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों से कनेक्शन होने की वजह से पुलिस को जांच करने में दिक्कत आती है और आरोपी अक्सर उनकी गिरफ्त से बाहर रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

● श्याम सिंह सिकरवार

फाइलों में दफन टाइगर सफारी

शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की सीमा का विस्तार करने और उद्यान में एक बार फिर टाइगर सफारी शुरू करने के लिए माधव नेशनल पार्क प्रबंधन ने 40 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। 13 गांवों का विस्थापन करते हुए मुआवजा भी बांट दिया लेकिन अब तक पार्क में टाइगर सफारी की शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके कारण टाइगर देखने आने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लगती है। यहां तक कि नेशनल पार्क के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन भी स्थानांतरित कर दी गई है। बावजूद इसके गांव खाली नहीं कराए जा सके और ग्रामीण आज भी खेती कर रहे हैं। प्रशासनिक मंशा की कमी के चलते बीते कई सालों से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ है।

माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विस्तार करने और टाइगर सफारी की पुनर्स्थापना करने के लिए कवायद वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। उसके बाद इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद 13 गांवों के विस्थापन का काम शुरू किया गया। मुआवजे का निर्धारण कर ग्रामीणों को पार्क प्रबंधन तथा राजस्व अमले ने मिलकर मुआवजा भी बांटा। इस दौरान 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अर्जुनगावां, लखनगवां, बलारपुर, मितलौनी, कांठी सहित कुछ अन्य गांवों का विस्थापन किया गया था जो माधव नेशनल पार्क की सीमा में बसे हुए थे। इन गांव के ग्रामीणों को खेती सहित मकान का मुआवजा भी प्रति परिवार के हिसाब से दिया गया था लेकिन मुआवजा लेने के बाद भी कई ग्रामीण आज भी इन इलाकों में खेती कर रहे हैं।

नेशनल पार्क के अंदर टाइगर सफारी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पहल पर शुरू की गई थी और यहां पर पेटू और तारा नाम के टाइगर साल 1988 में लाए गए थे। इसके बाद वंश वृद्धि हुई और एक समय संख्या 10 तक जा पहुंची थी। बाद में किसी कारणवश शावकों की मौत होती गई। यहां तक बताया जाता है कि तारा के नरभक्षी हो जाने के चलते उसे वन्य प्राणी उद्यान भोपाल भेज दिया था। इसके बाद टाइगर सफारी साल 1999 में बंद कर दी गई थी, जिसे पुनर्स्थापित करने की कवायद शुरू हुई थी।

एक तरफ जिला प्रशासन अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है तो वहीं विस्थापित होने वाले ग्रामीण अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उन्हें जो मुआवजा दिया गया, वह पुरानी दर पर था। निर्णय कई साल पहले हो गया था इसलिए बढ़ाकर राशि नहीं दी गई। उक्त इलाके में रहने वाले होतम, सुल्तान व बारेलाल गुर्जर का कहना है कि उनके कुछ लोगों ने इस मामले को ऊपर तक उठाया है और कुछ न्यायालय भी गए हैं। सीसीएफ वन विभाग एवं



18 साल तक रही थी टाइगर सफारी

माधव नेशनल पार्क में वर्ष 1988-89 में टाइगर सफारी शुरू की गई थी, जिसमें भोपाल वन विहार से पेटू व तारा टाइगर का एक जोड़ा मंगवाया गया था। इस जोड़े से अक्टूबर 1991 में एक नर व दो मादा बच्चों ने जन्म लिया। तीसरी बार तीन मादा बच्चों का जन्म 1993 में हुआ। नवंबर 1995 में दो नर व दो मादा बच्चे पैदा हुए। एक समय था जब टाइगर सफारी में कई टाइगर हो गए थे। लेकिन वर्ष 2006 में इसे बंद कर दिया गया। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क अभी 165 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लेकिन बफर जोन बनाए जाने के लिए पार्क के अंदर मौजूद 7 गांव खाली कराए जा रहे हैं। जिनमें से छह गांव तो खाली हो गए, लेकिन कुछ परिवार अभी हाईकोर्ट से स्ट्रे ले आए। यह एरिया खाली होगा तो 189 वर्ग किमी एरिया पार्क में बढ़ जाएगा, और माधव नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किमी हो जाएगा। बफर जोन बनने के बाद नेशनल पार्क में टाइगर को घूमने के लिए एक लंबा क्षेत्र मिलेगा।

संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी वायपी सिंह कहते हैं कि टाइगर पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट पर फिलहाल कोई प्रोग्रेस नहीं है। हम इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जल्द ही बातचीत करने वाले हैं। जिसके बाद उम्मीद है कि प्रोजेक्ट पर आगे काम हो सकेगा।

ज्ञात रहे कि पूर्व में भी नेशनल पार्क में टाइगर सफारी था, जो वर्ष 2006 में खत्म हो गया। माधव नेशनल पार्क के असिस्टेंट डायरेक्टर बीएस यादव ने बताया कि अभी हाल ही में प्रदेश के 6 जिलों में टाइगर सफारी शुरू किया जाना था, जिसमें ग्वालियर को शामिल किया गया। चूँकि ग्वालियर में एक बड़ा जू है, इसलिए अब ग्वालियर के लिए स्वीकृत टाइगर सफारी को शिवपुरी ट्रांसफर कर दिया गया। यादव ने बताया कि इसके लिए हमने प्रस्ताव भी भेज दिया है और पार्क में टाइगर सफारी के लिए 2500 हैक्टेयर एरिया भी चिह्नित कर लिया गया है। चूँकि नेशनल पार्क में सैलानियों को घूमने का ओपन एरिया है, इसलिए टाइगर रिजर्व के क्षेत्र

को 12 फीट ऊंची जाली से कवर्ड किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बनाई जाने वाली टाइगर सफारी में शिकार के लिए सांभर, हिरण सहित अन्य शाकाहारी वन्यजीवों को भी रखा जाएगा, ताकि टाइगर को अपने एरिया में ही शिकार मिल सके। यादव ने बताया कि पूर्व में जो टाइगर सफारी थी, उसका एरिया काफी कम होने के साथ ही वो कई नियमों को पूरा नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो नई टाइगर सफारी शुरू होगी, उसमें सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। माधव नेशनल पार्क में सफारी बनने के बाद जब उसमें खुले में टाइगर विचरण करेगा तो सैलानियों की संख्या बढ़ना तय है। क्योंकि विदेशी सहित देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद टाइगर होते हैं। जब शिवपुरी में सैलानियों की आमद बढ़ेगी तो शहर की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। क्योंकि शिवपुरी में जितने हैरीटेज व प्राकृतिक झरने हैं, उतने कहीं दूसरी जगह नहीं है।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

डि जिटल भारत में साड़ियों की आड़ लगाकर बने शौचालय...यह बात जानकर चौंकिए नहीं। यह हकीकत है उस बुंदेलखंड की, जहां आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी यहां के लोग सरकारी योजनाओं के तहत बने शौचालयों में साड़ियों की

आड़ करने को मजबूर हैं। जाहिर है इनकी दीवारों पर भ्रष्टाचार की दीमक लग गई होगी। यही नहीं, जिस ग्राम पंचायत को प्रशासनिक अधिकारियों ने खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया वहां भी लोगों को साड़ियों की आड़ में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ रहा है। टीकमगढ़ जिले में प्रशासन द्वारा 1,82,738 शौचालय बने होने का दावा किया जा रहा है। टीकमगढ़ जनपद पंचायत के पांच हजार की आबादी वाले सापौन गांव में कई घरों में फटी हुई साड़ियों को लकड़ियों के चारों ओर लपेटकर शौचालय बना लिए गए हैं। जिले के मोहनगढ़, खरगापुर और बड़ागांव क्षेत्र में भी स्वच्छ भारत अभियान का हाल कुछ ऐसा ही है। यहां पर न तो शौचालय बने हैं और न ही जागरूकता के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खरगापुर के सौरया गांव में भी ऐसे ही शौचालय देखे जा सकते हैं। यह हाल तब है जब जिला पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन की टीम भी अलग से तैनात है, लेकिन उसने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हकीकत देखने से मुंह फेर रखा है।

प्रशासन ने टीकमगढ़ जनपद पंचायत को ओडीएफ घोषित करते हुए हजारों शौचालय निर्माण कराने का दावा किया है। शौचालय निर्माण के लिए हितग्राही को 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने के दस्तावेज भी पूरे हैं। हालांकि यह रकम एक शौचालय बनाने के लिए कम पड़ती है लेकिन गांवों में किसी तरह दीवारें खड़ी कर शौचालय बना लिया जाता है। इलाके में साड़ियों की आड़ वाले शौचालय स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रहे हैं। गौरतलब है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची में शामिल लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है।

ऐसी स्थिति यह भी बताती है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने दफ्तरों में बैठकर ही ग्राम पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया। खुले में शौच से मुक्त गांवों को पुरस्कार सहित प्रमाण-पत्र भी दे दिए गए लेकिन हितग्राही आज भी परेशान दिखते हैं। इसकी एक वजह पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाकर शौचालय निर्माण करवाना भी रहा। जिले में ऐसे करीब 20 हजार शौचालय हैं जिनका निर्माण इस एजेंसी के जिम्मे था लेकिन वे भी पूरी तरह बन नहीं पाए हैं। इसके लिए भी ग्रामीण सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते देखे जा सकते हैं। मैदानी हकीकत यही है कि जिले का एक भी गांव ऐसा नहीं है, जहां शौचालय पूरे बने हों और



फटी साड़ियों के शौचालय

लड़कियों वाले गांव में शौचालय नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं। राज्य सरकार भी खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चला रही है, मगर जमीनी हकीकत अलग ही कहानी बयां करती है। ऐसा गांव, जहां लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां शौचालय नहीं है, तब बाकी गांवों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के हरपुरा मड़िया गांव की पहचान लड़कियों वाले गांव के तौर पर है, मगर यहां शौचालयों का अभाव है और महिलाओं से लेकर लड़कियों तक को मजबूरी में खुले में शौच को जाना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हरपुरा मड़िया गांव। इस गांव की आबादी लगभग डेढ़ हजार है। यह लड़कियों का गांव इसलिए कहलाता है, क्योंकि हर घर में बेटों से ज्यादा बेटियां हैं। यही कारण है कि इस गांव की पहचान बेटियों के गांव के तौर पर बन गई है। मगर यहां की बेटियों को हर रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि महिलाओं से लेकर बेटियों को सुबह 4 बजे से हाथ में लोटा लेकर शौच के लिए निकलना पड़ता है।

उनका उपयोग हो रहा हो। फर्जी ओडीएफ पर अदम गोंडवी की पंक्ति याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है।

ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया छतरपुर जिले के ब्लॉक छतरपुर, ग्राम चंद्रपुरा आदिवासी मोहल्ला में, जहां शौचालय ना होने से

महिलाएं झाड़ियों का पर्दा कर के शौच के लिए जाती हैं। क्योंकि उनके पास शौचालय नहीं बने हैं 500 की आबादी वाली इस बस्ती के लोग खुले में शौच जाने से काफी परेशान हैं, लेकिन शौचालय निर्माण को लेकर यहां न कोई अधिकारी आया और न ही कोई जनप्रतिनिधि, जबकि इस बस्ती में सभी गरीब असहाय और मजदूर लोग रहते हैं उनको दो वक्त का खाना जुटाना मुश्किल पड़ता है, तो खुद से शौचालय कैसे बना सकते हैं।

क्षेत्र की महिलाओं का कहना है- 'इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और हम सभी महिलाएं पर्दा कर के शौच के लिए निकलते हैं तो डर बना रहता है कि कहीं से कोई कीड़ा ना निकल आए जैसे बिच्छू, सांप न काट ले। इस समय वैसे ही कोरोना जैसी बीमारी चल रही है और बाहर जाना शौच के लिए खतरा ही है जब बाहर जाते हैं, तो कुछ लोग हम लोगों को डंडे मारकर भगा देते हैं, पर शौचालय की मांग सरपंच से कई बार की है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोगों से कमीशन की मांग की जा रही है।

बुंदेलखंड में सरकारी अनुदान से बनाए गए शौचालयों के हाल, बेहाल हैं। इनमें किया गया भ्रष्टाचार अपने आप में इनके पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। आप बुंदेलखंड के किसी भी नेशनल हाइवे से जुड़े गांव की सड़क पर सफर में सुबह निकलें तो सहज ही 'मेरा भारत महान' की बदबूदार तस्वीर से रूबरू हो जाएंगे। घरों में देहरी के अंदर लम्बा सा घूंघट निकालने को बेबस महिला यहां आम सड़क के किनारे सवेरे-सवेरे और संध्या में एक अदद आड़ के लिए भी तरसती नजर आती है।

● सिद्धार्थ पांडे

कैसे खुशहाल होगा किसान?

घोटालों की नर्सरी बना उद्यानिकी विभाग



केंद्र और राज्य सरकारें 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर काम कर रही हैं। मप्र में तो खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान ने खजाना खोल रखा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश अभी तक 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड पा चुका है। इस बार सबसे अधिक गेहूं खरीदी कर मप्र देश का सिरमौर बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उससे सवाल उठता है कि किसान कैसे खुशहाल हो पाएगा?

● राजेंद्र आगाल

मप्र वाकई अजब है, गजब है। एक तरफ प्रदेश अनाज उत्पादन में साल दर साल रिकार्ड दर्ज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां के किसान धोखाधड़ी, ठगी, कालाबाजारी, शोषण और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। रबी सीजन में यूरिया घोटाले से किसान परेशान थे कि इसी

दौरान घटिया चावल के वितरण ने उन्हें हैरान कर दिया। अभी यह मामला चल ही रहा है कि करीब 100 करोड़ का पावर टिलर घोटाला सामने आया है। उद्यानिकी विभाग के **अफसरों ने कंपनियों** के साथ मिलकर यह घोटाला किया है, जिसमें किसानों को बड़ी चपत लगी है। दरअसल, इस पूरे घोटाले की नींव 1996 बैच के एक

आईएफएस अफसर एम काली दुर्ई ने रखी है। दरअसल, दुर्ई उद्यानिकी विभाग में 1 अगस्त 2019 से लेकर 14 मई 2020 तक आयुक्त के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर किसानों के लिए **ऑफलाइन पावर टिलर** खरीदने का ऑर्डर देकर घोटाले को अंजाम दिया है।



विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 100 करोड़ रुपए का यह घोटाला केंद्र और प्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी से जुड़े किसानों के लिए यंत्र खरीदने की योजना से संबंधित है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदी पर अनुदान दिया जाना था मगर कुछ अधिकारियों ने धांधली कर अनुदान की राशि निजी कंपनियों के बैंक खातों में जमा करवा दी। मंदसौर के एक किसान की शिकायत पर उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो इस धांधली की परतें खुलने लगीं। जब इस मामले में उद्यानिकी विभाग भोपाल से जानकारी ली गई तो प्रदेश में बड़ा घोटाला सामने आया। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में यह घपला हुआ है।

पावर टिलर की जगह पावर विडर

प्रदेश में अफसर मौका मिलते ही किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए वे फर्जी कंपनियों का सहारा लेने से भी पीछे नहीं रहते हैं। वर्ष 2019-20 में उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन आयुक्त एम काली दुर्ई सहित कुछ अधिकारियों ने किसानों को पावर टिलर के स्थान पर पावर विडर व पावर स्प्रेयर वितरित कर दिए। पावर टिलर की कीमत लगभग 1.50 लाख रुपए होती है। जबकि पावर विडर और पावर स्प्रेयर 21 हजार से 52 हजार रुपए तक के आते हैं। प्रदेश में इस योजना में कुल 1618 पावर टिलर किसानों को कथित रूप से प्रदाय किए गए। इस घोटाले की शुरुआत मंदसौर में किसान की शिकायत पर लोकायुक्त जांच से प्रारंभ हुई। लोकायुक्त जांच में स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार अनुदान की राशि कंपनी के खाते में जमा की गई है। जबकि नियमानुसार अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिए। जब इस घोटाले की गूंज राजधानी तक

निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिए नियम

शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन आयुक्त एम काली दुर्ई और उपसंचालक राजेंद्र कुमार राजौरिया ने केंद्र सरकार के नियम भी बदल डाले थे। केंद्र द्वारा भेजी गई राशि कृषि उपकरण खरीदी लिए किसानों के खाते में भेजी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दरअसल केंद्र की इस योजना में नियमों के मुताबिक हितग्राही के खाते में सीधे 50 फीसदी रकम जाती है, यानी डीबीटी। नियम था किसान का पंजीयन, सत्यापन, स्वीकृति आदेश के बाद किसान बाजार से यंत्र खरीदे, अधिकारी जाकर सत्यापन करें फिर बिल जनरेट होकर किसान को अनुदान का पैसा जाता था, लेकिन आरोप है कि किसानों के खातों में राशि भेजने की जगह कंपनियों को भुगतान करवा दिया गया। जानकारी के अनुसार नियम यह है कि उद्यानिकी विभाग किसानों के लिए यंत्रों की खरीदी एमपी स्टेट एग्री के माध्यम से कराएगा। पावर टिलर खरीदने के लिए एमपी एग्री ने 4 संस्थाओं से टेंडर भी बुला लिया था, पर उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने पूरी प्रक्रिया को बदलकर अपने स्तर पर निजी कंपनियों से खरीदी कर ली। किसानों को जो 50 फीसदी अनुदान मिलता था। यह अनुदान किसानों के खाते में जाना था। लेकिन उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने कंपनियों के साथ मिलीभगत कर उसे डायरेक्ट कंपनियों को दे दिया और किसानों को सप्लाई की गई घटिया मशीनों का 50 प्रतिशत भुगतान कंपनियों ने जाकर उनसे वसूल लिया। यही नहीं किसानों के साथ ठगी भी की गई। उन्हें कम कीमत की मशीन पकड़ाकर लाखों के पावर टिलर का दाम लिया गया। अब मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उधर, किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।

पहुंची तो आनन-फानन में एक कमेटी बनाकर जांच कराई गई।

शासन ने इस घोटाले की जांच के लिए एमपी एग्री कॉर्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक श्रीकांत बनोट की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। जिसमें 4 तकनीकी अधिकारी सदस्य थे। समिति ने सभी जिलों से योजना के अंतर्गत वितरित यंत्रों को भोपाल बुलवाया था। सभी जिलों से 2-2 यंत्र अवलोकन हेतु बुलवाए गए थे। जांच के पश्चात समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने घोटाले के तार पूरे प्रदेश से जुड़े होने का हवाला देते हुए इसकी जांच अर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो या लोकायुक्त से कराने की अनुशंसा की है।

5 कंपनियों ने किया घोटाला

उद्यानिकी विभाग की यंत्रोपकरण योजना में करोड़ों के घोटाले में प्रथम दृष्टया 5 कंपनियां दुर्ग इंटरप्राइजेज रायपुर, गणेश इंटरप्राइजेज जबलपुर, किसान एग्रीटेक गुजरात, छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेज दुर्ग और जेएम इंटरप्राइजेज दुर्ग के नाम आ रहे हैं। इन सभी कंपनियों का संचालक एक ही व्यक्ति जिनेश पटेल बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार योजना में प्रदाय किए गए कुल 1618 पावर टिलर में से 1291 पावर टिलर इन्हीं 5 कंपनियों ने सप्लाई किए थे। लोकायुक्त पुलिस ने मंदसौर जिले के गरोठ, सीतामऊ, मल्हारगढ़ आदि क्षेत्र के किसानों से बयान लिए हैं। जिन कंपनियों के खाते में अनुदान की राशि जमा हुई है, उन्हें नोटिस जारी कर बयान देने के लिए बुलाया गया है। खास बात यह है कि ये कंपनियां शासन द्वारा प्रमाणित भी नहीं हैं। तीन कंपनियों किसान एग्री लिमिटेड, जेएम इंटरप्राइजेज और गणेश ट्रेडिंग से कृषि उपकरणों की खरीदी हुई है। इनमें जेएम इंटरप्राइजेस को छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी के कारण ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। इन तीनों कंपनियों का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फर्म्स एवं सोसायटी में पंजीयन भी नहीं था। एमपी एग्री से एमओयू के बिना ही तीनों कंपनियों ने यंत्रों की आपूर्ति कर दी। तीनों कंपनियों का कर्ताधर्ता गुजरात के आणंद का रहने वाला जिनेश पटेल बताया जा रहा है।

जांच में ये पाया गया है कि पावर टिलर छत्तीसगढ़ की कंपनी कृषि क्राफ्ट के माध्यम से खरीदे गए हैं। ये सारी खरीदी तीन एजेंसियों छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस, गणेश ट्रेडिंग कंपनी और जेएम इंटरप्राइजेस से हुई है। इनका कर्ताधर्ता जिनेश पटेल है। इन तीनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में नहीं मिला है। इनका जीएसटी भी नहीं है। इन्हें सहकारिता संस्था बताया गया है। लोकायुक्त ने पटेल को 10 सितंबर को दस्तावेजों के साथ तलब किया है।

प्रदायकर्ता फर्म

फर्म	संख्या
मे. गणेश टेडिंग कंपनी, जबलपुर	460
मे. जेएम इंटरप्राइजेस, भिलाई	171
मे. श्रीराम ट्रेडर्स, अनूपपुर	1
मे. ग्रीन एग्रो, बैतूल	34
मे. छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस, दुर्ग	244
मे. पाटीदार एग्रो इंडस्ट्रीज, सुसनेर	1
मे. हरिओम एग्रो एजेंसी, कारखेड़ा	17
मे. किसान एगरोटेक, दुर्ग	417
मे. श्री सिद्ध विनायक एग्रो, बुरहानपुर	16
मे. जयकिसान ट्रेडर्स, बुरहानपुर	1
मे. श्रीजी कृषि पंप, रावेर	1
मे. शांति एग्रो हार्डटेक, छिंदवाड़ा	1
मे. विन स्पायर प्रालि, अहमदाबाद	9
मे. विनायक ट्रेडर्स, भोपाल	43
मे. मां नर्मदा कृषि सेवा, खरगोन	25
मे. आरएस एग्रो	91
मे. ओम सांईराम सेल्स, खरगोन	3
मे. स्वास्तिक इंटरप्राइजेस कंपनी	2
मे. हार्टिका वन स्टॉप, भोपाल	2
मे. किसान कुंज कृषि केंद्र, ग्वालियर	26
मे. जैन ट्रेवटर्स, बालाघाट	1
मे. नंदिनी ट्रेवटर्स, बालाघाट	1
मे. सिद्धी एग्रो इंडस्ट्री, भोपाल	50
मे. राजा इंटरप्राइजेस, संगरूर	1



घोटाले को लेकर राजनीति शुरू

मप्र उद्यानिकी विभाग के भोपाल दफ्तर में मौजूद छोटे से पावर टिलर ने मप्र में करोड़ों को उद्यानिकी घोटाले की परतें खोली हैं। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने कंपनियों के साथ मिलकर किस तरह किसानों को पावर टिलर की जगह पावर विडर सौंप दिया है। किसानों की सब्सिडी में घालमेल करने का यह खेल बड़े स्तर पर खेला गया है। मॉडल वाइजर, विडर अलग चीज है जो निंदाई, गुड़ाई के लिए काम आता है। वहीं पावर टिलर छोटा ट्रैक्टर है जो कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है। छोटे से पावर टिलर जो राज्य में कुल 1647 किसानों को बांटे गए उसने मप्र में पावर गैलरी को हिला दिया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस 2017 से शिवराज सरकार के वक्त की भी जांच कराने की मांग कर रही है। उधर, शिवराज सरकार के मंत्री पूर्व की कमलनाथ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन पूर्व उद्यानिकी मंत्री सचिन यादव वो नोटशीट लेकर बैठे हैं जिसमें पिछले साल 23 अक्टूबर को ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। सचिन यादव कहते हैं कि ये घोटाला पूर्व भाजपा सरकार के वक्त से चल रहा है। जब मैं मंत्री था तो मंदसौर से शिकायत मिली जिसके आधार पर 23 अक्टूबर 2019 को नोटशीट पर मामले की जांच करने को कहा, लेकिन हमारी सरकार चली गई।

उपकरण अमानक स्तर के

जांच में यह बात भी सामने आई है कि कंपनी ने जो उपकरण एमपी एग्रो के माध्यम से किसानों को दिए थे वो अमानक स्तर के थे। प्रथम दृष्टया कुछ अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। जांच पूरी होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उच्चजैन लोकायुक्त पुलिस ने उद्यानिकी विभाग, भोपाल को इस शिकायत के संबंध में पत्र लिखकर योजना संबंधित जानकारी मांगी थी।

उद्यानिकी विभाग ने यंत्रीकरण योजना के नाम पर वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में आदिवासी किसानों को करीब 100 करोड़ रुपए के चाइना मेड घटिया कृषि यंत्र थमा दिए। 5 एचपी का बिल लगाकर 2 से 3 एचपी की चाइना मेड मशीनें खपाई गई हैं। जिस फर्म के माध्यम से कृषि यंत्रों की सप्लाई करवाई गई, उस फर्म का प्रदेश में रजिस्टर्ड ऑफिस, सर्विस सेंटर एवं जीएसटी नंबर नहीं है। घोटाला पकड़ में आने पर डायरेक्ट सप्लाई ऑर्डर की बजाय एमपी एग्रो से कार्य करवाने के निर्देश दिए गए।

यंत्रीकरण योजना का कार्य जैसे ही एमपी एग्रो को सौंपा गया, तो उसकी रफ्तार धीमी हो गई। यही नहीं आदिवासी कृषकों से बिल सत्यापित कराकर फर्जी कृषक अंक की रसीदें लगाकर अनुदान राशि सीधे डीलर ने अपने खाते में शिफ्ट करवा ली। शिकायत में विशेष रूप से कृषि क्राफ्ट कंपनी पर धोखाधड़ी आदि का आरोप भी है। यह भी बताया गया है कि उनके द्वारा अन्य डीलरों के माध्यम से चाइना में घटिया माल जिनके पार्ट आदि भी उपलब्ध नहीं हैं, वह प्रदाय किया गया है।

नियमानुसार प्रदायकों द्वारा प्रस्तुत देयकों में यंत्र का पूर्ण विवरण लिखा जाना आवश्यक होता है। जिसमें निर्माता कंपनी का नाम, मॉडल, सीरियल नंबर, इंजन चेचिस नंबर महत्वपूर्ण है। लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि अधिकांश देयकों में पूर्ण जानकारी अंकित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर पावर टिलर के स्थान पर रोटरी टिलर या पावर विडर लिखा गया है। वहीं कुछ बिलों में कुछ भी नहीं लिखा गया है, मात्र मॉडल का कोड अंकित है।

अधिकांश प्रकरणों में किसानों से कृषक अंश

का भुगतान नगद प्राप्त किया हुआ पाया गया है। जबकि किसानों के बैंक खाते उपलब्ध हैं। शिकायत में प्राप्त प्रकरणों का एमपी एग्रो द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं जिला प्रबंधकों के माध्यम से रैंडम आधार पर पुनः भौतिक सत्यापन करवाया गया। बुरहानपुर, शाजापुर, आगर-मालवा, भिंड, सीधी, सिंगरौली, उमरिया आदि जिलों में सत्यापन के बाद कई तरह की खामियां सामने आईं। बुरहानपुर में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को 1.50 लाख का पावर टिलर बताकर रोटरी टिलर थमा दिया है। शाजापुर में पावर टिलर के इंजन के आकार को देखकर प्रतीत होता है कि 10 एचपी के गुणवत्ता के इंजन नहीं हैं। आगर-मालवा में यह तथ्य सामने आया कि वहां किसानों से कृषक अंश काफी कम लिया गया है, जबकि प्रदायक ने रसीद 75 हजार की दी है। भिंड में किसान सियाराम के पावर टिलर के स्थान पर रिपर पाया गया, जिससे किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसान दिनेश सिंह को 7.5 एचपी का मॉडल दिया गया, जबकि दरें 9 एचपी के बराबर पाई गईं। इसी तरह सीधी, सिंगरौली, उमरिया में भी किसानों को दूसरी मशीनें देकर पावर टिलर की राशि वसूली गई है।



बिना सामान खरीदे भुगतान

आरोप ये भी है कि नेताओं-अफसरों की मिलीभगत से घोटाला करने के लिए अफसरों ने न सिर्फ नियम बदले, बल्कि किसानों को घटिया उपकरण मुहैया कराए। किसानों की सब्सिडी का हिस्सा भी सीधा निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया है। यंत्रीकरण योजना में पावर टिलर खरीदने में प्रारंभिक जांच में आर्थिक अनियमितता की पुष्टि हो चुकी है। किसानों को केंद्र से अनुदान देने के नाम पर इस मशीन की जगह सस्ते और घटिया चीन के बने उपकरण किसानों को बांटकर फर्जी कागज पर बनी कंपनियों ने करोड़ों कमाए और इसमें मदद की किसानों का हक छीनने वाले उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने। मंदसौर के किसान मुकेश पाटीदार ने बताया, भारत सरकार का नियम है कि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी (सब्सिडी सीधा खाते में ट्रांसफर) होना चाहिए। कोई भी अनुदान हो किसान के खाते में ही आना चाहिए। इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वेंडर पेमेंट कर रहे हैं। इसमें तो एक ही व्यक्ति को ठेका दे दिया।

दोगुने दाम में खरीदे गए उपकरण

आरोप है कि उपकरणों को दोगुने से ज्यादा दामों में खरीदा गया, किसानों के खाते की जगह सीधे कंपनियों को भुगतान किया गया, पहले योजना में ट्रैक्टर विथ रोटावेटर दिए जाते थे, जिनका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन 2019-2020 में पावर टिलर और पावर विडर दिए गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि एमपी एग्री ने जिन कंपनियों से पावर टिलर खरीदे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 में अफसरों ने किसानों को डेढ़ लाख रुपए कीमत के पावर टिलर की जगह 21 से 52 हजार रुपए के सस्ते पावर विडर और पावर स्प्रेयर बांटे। ये सारे कृषि यंत्र मेड इन चाइना हैं। डीबीटी खत्म करके, एमपी एग्री से खरीदी शुरू हुई, आरोप लगे कि सप्लायर एमपी एग्री में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें फायदा पहुंचाने ऐसे

मंत्री ने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त से जांच के सुझाव को ठुकराया

केंद्र की यंत्रीकरण योजना के तहत प्रदेश के उद्यानिकी विभाग को मिले 100 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच को लेकर नया पेंच मंत्री ने लगा दिया है। घोटाले की प्राथमिक जांच में आईएसएस अफसर के नेतृत्व वाली चार सदस्यीय टीम ने विभागीय अफसरों को दोषी पाया था और मामले की विस्तृत जांच ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से करवाने की अनुशंसा की थी। उद्यानिकी विभाग के मंत्री भारत



सिंह कुशवाह इस अनुशंसा से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है जांच किसी अन्य एजेंसी से करवाने के बजाय विभाग स्तर से ही करवाना चाहिए। हालांकि, वे अभी जांच रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने और एक सप्ताह बाद इस मामले में कोई निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रहते वर्ष 2019 में योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से कृषि यंत्र खरीदे जाने थे। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जानी थी, लेकिन अफसरों ने नियमों में फेरबदल कर राशि को कंपनी के खाते में उलवा दिया। इस मामले की शिकायत हुई तो जांच का जिम्मा एमपी एग्री के एमडी श्रीकांत बनोट को दिया गया। चार सदस्यीय टीम ने शुरुआती जांच में पाया कि योजना में प्रदेश स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। टीम ने शुरुआती जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी थी। यह रिपोर्ट अधिकारियों ने मंत्री के सामने रखते हुए ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से जांच कराने की सिफारिश की। इस पर मंत्री कुशवाह ने स्पष्ट इनकार कर दिया है।

आदेश निकाले गए कि कंपनी के खाते में अनुदान की राशि जा सकती है, काम को भी ऑफलाइन करने के आदेश दे दिए गए ताकि घटिया काम, भ्रष्टाचार नजर से बचे रहें।

जाहिर सी बात है, घटिया मशीन है सो किसानों के किसी काम की नहीं हैं। छतरपुर के किसान गंगाराम कुशवाहा की मानें तो मोटी जमीन है वो काम नहीं करती, ट्रैक्टर भर दिया

कल्टीवेटर दिया। वहीं खुद उद्यानिकी विभाग के अफसर कह रहे हैं, जो सामग्री दी गई वो टिलर का विकल्प नहीं हैं। कृषि इंजीनियर एसपी अहिरवार के मुताबिक 85 हजार किसानों को सब्सिडी देने का है मॉडल वाइज, विडर अलग चीज है जो निंदाई, गुड़ाई के लिए काम आता है, पावर टिलर छोटा ट्रैक्टर है कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है। जांच समिति ने जब टीकमगढ़, बुरहानपुर, होशंगाबाद और देवास जिलों में बांटे गए यंत्रों का देखा तो पता चला कि वो पावर टिलर थे ही नहीं, सभी मशीनों में इंजन नंबर एक ही लिखा है। इन पर जिस कंपनी ने बनाया उनका नाम नहीं लिखा था। सभी मशीनों में एक ही इंजन नंबर मिला। मशीन से संबंधित मापदंड खुदे हुए नहीं बल्कि स्टीकर से चिपकाए हुए थे। 5 हार्स पावर की मशीन की जगह दो और तीन हार्स पावर की मशीन लगी हुई थी।

आरक्षित वर्ग के नाम पर घोटाला

मामले की जांच लोकायुक्त उज्जैन पुलिस भी कर रही है। इसमें पता चला है कि यह योजना पहले आओ पहले पाओ की थी। सामान्य वर्ग के किसानों को इसमें 60 हजार रुपए की अनुदान राशि दी जानी थी। जबकि, आरक्षित वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपए तक की अनुदान राशि दी जानी थी। विभागीय अफसरों का कारनामा यहां भी कम नहीं रहा। उन्होंने आरक्षित वर्ग को ज्यादा अनुदान होने पर मंदसौर जैसे जिले में कागजों में सिर्फ इसी वर्ग के किसानों को यंत्र देना दर्शा दिया। जबकि किसानों को यंत्र दिए ही नहीं, इस तरह अफसरों और कंपनी ने मिलकर आरक्षित वर्ग के नाम पर ज्यादा अनुदान हासिल कर लिया। जिस डीलर ने ये यंत्र दिए वो कनाडा का नागरिक है, गुजरात से कारोबार किया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया लेकिन वहां भी ना रजिस्टर्ड दफ्तर था ना जीएसटी नंबर, इसी एक मालिक की 3 कंपनियों को सांठगांठ करके पूरी योजना का लगभग 95 फीसदी काम दिया गया। भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्रालय ने जिस कंपनी, मॉडल और मापदंडों की बात कही उसकी भी धज्जियां उड़ाई गईं। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि नियम है भारत सरकार की सूची में होना चाहिए, फिर टेस्टिंग होती है कमेटी होती है किसान को छूट देना चाहिए उसमें सब्सिडी भारत सरकार देगी। भारत सरकार की सूची में नहीं। जांच चल रही है।

वैसे देखा जाए तो जब भी किसानों के साथ ठगी होती है तब सरकार उन्हें न्याय देने के लिए बड़े-बड़े दावे करती है। लेकिन कुछ ही मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो पाई है। प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी विभाग में हुए घोटाले की जांच तो जोरशोर से शुरू की है, लेकिन क्या दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे।

घटिया चावल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

बालाघाट तथा मंडला जिलों में अमानक (पोल्ट्री ग्रेड) चावल पीडीएस दुकानों से वितरित करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने के साथ ही तीखे तेवर दिखाए जिसके बाद नागरिक आपूर्ति निगम के कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इस मामले में परत-दर-परत जो खुलासे हो रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। यह बात सामने आई है कि माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से यह घोटाला 250 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है कि राजनेताओं के संरक्षण में इस गठजोड़ ने घटिया चावल गोदामों तक पहुंचाया है। इस प्रकार के घपले-घोटाले उस स्थिति में ही अंजाम दिए जा सकते हैं जबकि राजनेताओं का संरक्षण हो। इसलिए जरूरी है कि संरक्षण देने वाले राजनेता किसी भी दल के हों उन्हें न केवल बेनकाब किया जाना चाहिए बल्कि कार्रवाई भी की जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले घोटालों पर रोक लग सके। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राशन माफिया हर साल 1000 करोड़ का घोटाला करता है।

घटिया चावल की जांच प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो गई है तथा गोदामों से सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। जांच में पता चला है कि मिलर्स ने अच्छे चावल को बाजार में बेचा और खराब चावल को जिला प्रबंधकों से मिलकर गोदामों में रखवाया और इस प्रकार घोटाला किया गया। इस मामले में जिला प्रबंधकों की बड़ी संलिप्तता सामने आ रही है क्योंकि उन्होंने खराब चावल को अच्छा बताकर गोदामों में रखवा लिया था। अभी तक 1550 सैंपल लिए गए इनमें से 535 की रिपोर्ट आ गई है और उसमें से 70 सैंपल अमानक पाए गए हैं। अब उन सभी गोदामों से सैंपल लिए जा रहे हैं जहां चावल रखे हुए हैं।

चावल घोटाला माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजनेताओं के संरक्षण में इस गठजोड़ ने घटिया चावल सरकारी गोदामों तक पहुंचाया। जांच में यह उजागर हो चुका है। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की जगह चावल को वापस



मिलरों को लौटाया जा रहा है। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू ने अब तक जांच में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। सर्वाधिक 47 करोड़ रुपए मूल्य का घटिया चावल बालाघाट में पाया गया है।

जांच का पुख्ता तंत्र नहीं

दरअसल, चावल की गुणवत्ता जांच का कोई पुख्ता तंत्र मप्र में नहीं है। प्रदेश में अनाज की खरीदी और भंडारण की जिम्मेदारी 4 संस्थाओं- नागरिक आपूर्ति निगम, एमपी एग्री, खाद्य विभाग और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी अमानक खरीदी या भंडारण की जांच नहीं कर पाता है। इनके रहते केंद्र की टीम आती है और 52 हजार टन चावल की सैंपलिंग करती है, जिसमें से 3 हजार टन खराब निकलता है। दरअसल, प्रदेश में एक आउटसोर्स कंपनी गुणवत्ता देखती है। लेकिन मिलर्स और विभाग की मिलीभगत से अमानक चावल गोदामों में रखा जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कोई भी विभाग इसकी जांच-पड़ताल नहीं करता है कि जो अनाज गोदाम में रखा गया है वह कैसा है? राज्य का नागरिक आपूर्ति निगम अपने और भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं लेकर काम चला रहा है, जो माफिया के गठजोड़ का आसानी से हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार की जांच का हल्ला मचने के बाद 73 हजार 540 टन चावल मिलर्स को वापस लौटाया जा रहा है।

खरीदी प्रक्रिया भी गलत

मप्र में धान सहित अन्य अनाजों की खरीदी की प्रक्रिया भी गलत है। दूसरे राज्यों में आढ़तियों के माध्यम से अनाजों की खरीदी होती है, जबकि मप्र में सरकार खुद खरीदती है। ऐसे में किसान कूड़ा-करकट भरा अनाज बेच देते हैं। यही नहीं धान की मिलिंग अन्य राज्यों में मार्च में ही हो जाती है, जबकि मप्र में बरसात में होती है। बरसात में मिलिंग होने के कारण चावल में नमी पकड़ लेती है। नमी रहित चावल बोरो में भरकर गोदामों में रख दिया जाता है, जो धीरे-धीरे खराब होने लगता है। उच्च स्तरीय जांच में सामने आया है कि चावल की गुणवत्ता को लेकर चलने वाला खेल बिना अधिकारी, मिलर और गोदाम के कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। दरअसल, नियमों में चार स्तर पर जांच का प्रविधान है पर इसकी अनदेखी जानबूझकर की जाती है। धान खरीद के समय, मिलर को मिलिंग के लिए देते समय मिलिंग के बाद अधिकारियों से नमूना जांच और सबसे अंत में गोदाम में चावल जमा कराते समय गुणवत्ता की जांच होती है। इस व्यवस्था के बाद भी प्रदेश के 22 जिलों में 73 हजार 540 टन निम्न गुणवत्ता का चावल गोदामों में पहुंच गया, जो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। सरकार को एक क्विंटल चावल पर करीब 3100 रुपए का खर्च आता है। इस हिसाब से देखें तो यह खेल बड़ा है।

विधायक के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं?

चावल घोटाले में यह तथ्य निकलकर आया है कि जबलपुर संभाग के एक विधायक के संरक्षण में यह सारा खेल खेला गया है। उक्त विधायक संभाग के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। सूत्रों का कहना है कि संभाग के साथ ही आसपास के जिलों के गोदामों में रखे अमानक चावल का संबंध उनसे है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विधायक के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय दल द्वारा घोटाला पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनन-फानन में सुबह 10 बजे बैठक बुलाकर सबको फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों से कहा कि यह कितनी शर्मनाक बात है कि केंद्र की टीम आकर सर्वे कर रही थी और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। अगर समय रहते आप लोग देख लेते तो मैं केंद्र को मैनेज कर लेता।

पांव फैलाने के प्रयास

दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूती से जमा लेने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी देशभर में विस्तार की रणनीति पर आक्रामक तरीके से अमल करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या उत्तर प्रदेश के प्रभारी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह या आप के अन्य राज्यों के नेता, ये सभी दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का विस्तार करने के लिए आक्रामक अंदाज में सक्रिय हो गए हैं।

पहले बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश वो राज्य है, जहां के मतदाता लोकसभा में 80 सांसद चुनकर भेजते हैं। उप्र के मतदाताओं के समर्थन के बिना दिल्ली की गद्दी पर बैठना लगभग असंभव-सा ही है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने देश को अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। इस प्रदेश के महत्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आने का फैसला किया तब उन्होंने उप्र के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय ही आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी प्रदेश के महत्व का अंदाजा बखूबी था इसलिए उन्होंने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वाराणसी से ही मोदी के खिलाफ चुनावी रण में ताल ठोंकी थी। हालांकि 2014 का लोकसभा चुनाव आप के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पार्टी को पंजाब छोड़कर किसी राज्य में कामयाबी नहीं मिली। सबसे दुखद स्थिति तो यह थी कि अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा था। उस हार से सबक लेते हुए केजरीवाल ने उस समय यह ऐलान किया था कि अब आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर ही ध्यान केंद्रित करेगी लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में मोदी-शाह की जोड़ी को बुरी तरह से पटखनी देने के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में जोश पैदा हो गया है। इसी का नतीजा है कि पार्टी ने एक बार फिर से अन्य राज्यों में चुनावी विस्तार की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी संजय सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर मैदान में उतार दिया है। प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उप्र की कमान संभालते ही राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। संजय सिंह ने पहले राम मंदिर भूमि शिलान्यास का मुद्दा उठाकर सीधे प्रधानमंत्री और संघ पर हमला बोला और उसके बाद से वो लगातार राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साध रहे हैं। प्रदेश



दिल्ली मॉडल के सहारे आप

यह एक सच्चाई है कि आप का संगठन आज की तारीख में जितना दिल्ली में मजबूत है उतना देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। आप के नेता भी इस तथ्य को बखूबी समझते हैं। इसलिए बार-बार वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। आप के बड़े नेताओं का यह दावा है कि जिस मॉडल या चुनावी रणनीति के सहारे उन्होंने पहले शीला दीक्षित जैसे दिग्गज को मात दी। दिल्ली की राजनीति से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को साफ कर दिया। जिस मॉडल के सहारे उन्होंने मोदी-शाह के विजयी रथ को रोक दिया, उसी मॉडल के सहारे वो कमजोर संगठन के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य में भी चुनावी जीत हासिल कर सकते हैं। चुनावी मैदान- चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का या पंजाब का या अन्य किसी राज्य का, कितनी बड़ी तादाद में मतदाता झाड़ू का बटन दबाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल तो आप के चुनावी इरादों ने कई राज्यों की राजनीति में हलचल तो पैदा कर ही दी है।

के अलग-अलग जिलों में अपने खिलाफ दर्ज होने वाले एफआईआर के लिए भी संजय सिंह सीधे मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस के तमाम व्यापक इंतजामों के बावजूद गत दिनों उप्र विधानसभा में पहुंचकर भी संजय सिंह ने सीधे योगी सरकार को चुनौती देने का काम किया।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति नायडू को पत्र लिखकर संजय सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो सड़क से लेकर संसद तक भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। संजय सिंह के आक्रामक अंदाज की वजह से उप्र में पार्टी के कैडर में जोश आ गया है। यही वजह है कि अब आप दिल्ली मॉडल पर उप्र विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी का यह दावा है कि प्रदेश में वो बिजली, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर जनता का समर्थन हासिल करेगी। पार्टी के नेता यह भी दावा कर

रहे हैं कि इस मॉडल पर चलने की वजह से पार्टी संगठन के कमजोर होने के बावजूद उन्हें उप्र में चुनावी फायदा होगा। हालांकि वास्तविकता यह भी है कि इन तमाम मुद्दों से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी प्रदेश में जातिगत मुद्दों को भी हवा दे रही है क्योंकि संजय सिंह यह बखूबी जानते हैं कि उप्र के चुनावी रण में जाति सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। उत्तर प्रदेश से सटे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी एक रणनीति बनाकर पहाड़ी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में एक वैकल्पिक तीसरी ताकत बनने की कोशिश करेगी।

● नवीन रघुवंशी

गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल सहित 23 नेताओं की पूर्णकालिक अध्यक्ष की मौजूदा पहल कांग्रेस में किसी नए विभाजन का संकेत तो नहीं? देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं के पत्र में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। उसमें पार्टी के हित की ही बात कही गई है, लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी को वह इसलिए चुभी, क्योंकि उसमें दो ऐसी मांगें हैं जो कांग्रेस-संस्कृति पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं। एक मांग कांग्रेस आलाकमान संस्कृति को खत्म कर पार्टी में संस्थागत नेतृत्व प्रक्रिया स्थापित करने से संबंधित है, जो कांग्रेस में नेहरू-गांधी वंश का एकाधिकार समाप्त करती। दूसरी मांग राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित है, जिसे समाप्त करने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1969 में ही कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप जून 1975 में जब उन्होंने देश में आपातकाल थोपा, तब कांग्रेसी नेताओं-हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम और युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आदि ने नेतृत्व का विरोध करने के बजाय उससे किनारा कर लिया। आज पार्टी के हित में नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेसियों ने हिम्मत का काम किया है। यह काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जनता तो समझने लगी थी कि कांग्रेस में ऐसी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है।

नेतृत्व परिवर्तन की मांग के असहमति पत्र से उज्जवा कांग्रेस पार्टी का संकेत फिलहाल टल गया है, वहीं कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव ने अगले अध्यक्ष के चुनाव को रोडमैप दिया है। सोनिया गांधी भी 'भूल जाओ और माफ करो' अपनाते हुए आगे बढ़ने का आव्हान कर चुकी हैं। हालांकि संसद के मानसून सत्र से पहले संसदीय पैनल में प्रमुख पदों की नियुक्ति में असंतुष्ट खेमे की अनदेखी हुई है। लोकसभा में पार्टी के सबसे विश्वसनीय चेहरों मनीष तिवारी और शशि थरूर को नजरअंदाज किया गया है। संसद में पार्टी की नई नियुक्ति में अधिकतर टीएम राहुल से जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि तभी से पार्टी के गांधी और गैर गांधी समर्थक धड़ों के रुख सख्त हो चले हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला समिति ने कथित तौर पर पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर बागी खेमे के प्रमुख चेहरे कपिल सिब्बल ने पीछे हटते हुए ट्वीट किया कि दुर्भाग्य से उग्र में जितिन प्रसाद को खुलेआम निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस को भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए न कि अपनों पर ऊर्जा खर्च करनी चाहिए।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक प्रमुख नेता ने एक न्यूज चैनल को नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि राहुल गांधी 2024 में 400

पार्टी के कार्याकल्प की योजना तैयार करने के मकसद से पत्र लिखने वाले 23 कांग्रेसी नेताओं की जिस तरह उपेक्षा हो रही है, उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस एक और विभाजन की ओर बढ़ रही है। क्योंकि वह दिशाहीन हो गई है और इसके चलते उसके कार्यकर्ता हताश हैं। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान इस हताशा को कैसे रोक पाता है।

विभाजन की ओर



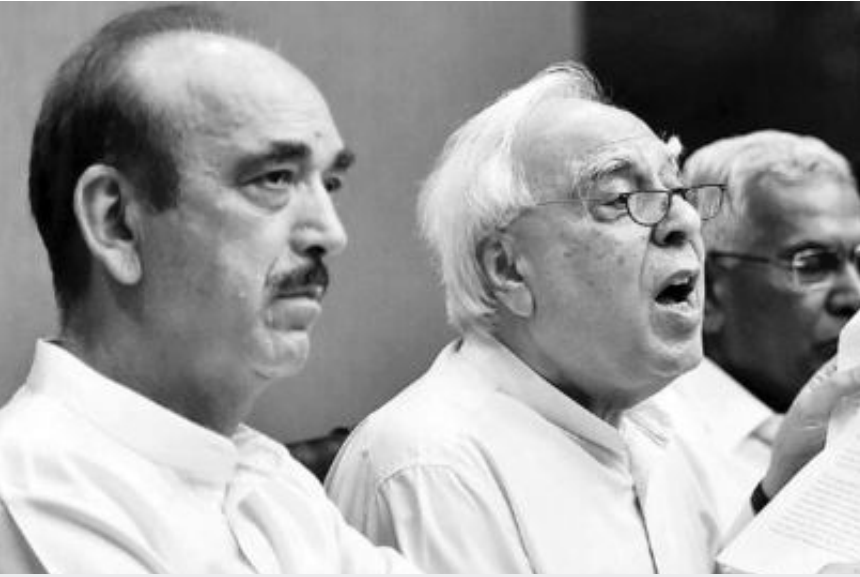
सोनिया का पुत्र मोह

राहुल गांधी की पार्टी अध्यक्ष पद पर दोबारा ताजपोशी का रास्ता खुद सोनिया गांधी ने ही साफ कर दिया है। सोनिया ने बतौर अंतरिम अध्यक्ष पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राहुल की पसंदीदा टीम को मौका दिया है और महासचिव पद से बुजुर्ग नेताओं की छुट्टी कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया है। नया अध्यक्ष चुनने में सोनिया की मदद के लिए 6 नेताओं की नई कमेटी बनाई गई है। हालांकि, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नई सीडब्ल्यूसी में बरकरार रखा गया है। दिग्विजय सिंह को सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी में शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुइजिनो फैलेरियो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। इनमें से गुलाम नबी उन 23 नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने सोनिया गांधी को 7 अगस्त को तब चिट्ठी लिखी थी, जब वे अस्पताल में भर्ती थीं। इस चिट्ठी में इन नेताओं ने पार्टी में ऐसी 'फुल टाइम लीडरशिप' की मांग की थी, जो 'फील्ड में एक्टिव रहे और उसका असर भी दिखे'। गुलाम नबी आजाद को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे राज्यसभा में अभी विपक्ष के नेता भी हैं।

सीटों पर पार्टी का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं हैं। इधर, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि पार्टी ऐतिहासिक गिरावट पर है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो अगले 50 वर्षों तक हम विपक्ष में ही बैठते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद क़िदवाई संकेत करते हैं कि समर्थन के लिए बागी समूह शरद पवार और ममता बनर्जी से संपर्क कर सकता है।

कांग्रेस संगठन का सफर कई विभाजनों का गवाह रहा है। बंटवारे की सबसे पहली घटना 1923 में हुई, जब जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने गांधी के साथ मतभेदों के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया था। फारवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिनका 1939 में अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर गांधी से मतभेद था। 1950 में आचार्य कृपलानी को हटाया गया, तो उन्होंने 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी। नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की समाजवादी नीतियों के खिलाफ सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था।

विचारों के आधार पर विभाजित होती रही कांग्रेस नेहरू की मृत्यु के बाद गुटबाजी के चलते बंटी। 1969 में अध्यक्ष वीवी गिरि के चुनाव के बाद एक समूह ने इंदिरा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से



कांग्रेस में कई विसंगतियां भी घर कर गईं

गत 73 वर्षों में कांग्रेस ने केवल कमजोर हुई है, बल्कि उसमें कई विसंगतियां भी घर कर गई हैं। यही उर गांधीजी की था। तभी उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर उसकी जगह लोकसेवक संघ बनाया जाए, जिससे लोकतांत्रिक स्पर्धा के लिए नई-नई पार्टियों को बराबर की जमीन मिले और कांग्रेस को कोई शुरुआती लाभ न मिल सके। इसी लाभ ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई, क्योंकि उसे भ्रम हो गया कि वह अपराजेय है, जिससे उसका संगठनात्मक, वैचारिक और नेतृत्वमूलक क्षरण होता गया। कांग्रेसियों को पार्टी और लोकतंत्र के हित में कांग्रेस में नवचेतना के अंकुरण के इस ऐतिहासिक क्षण को गंवाना नहीं चाहिए। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा को दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला 1998 से 2004 तक और दूसरा मई, 2004 से अभी तक का। उनके नेतृत्व में पार्टी दो चुनाव 1998 और 1999 में हारी और दो 2004 और 2009 में जीती। पिछले दो लोकसभा चुनावों की हार राहुल गांधी के खाते में जाती है। आप चाहें तो इसे परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी मान लें, तो छह में से सिर्फ दो लोकसभा चुनावों में जीत, वह भी स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। छह में दो यानी 33 फीसदी। आजकल तो इतने नंबर पर पास भी नहीं होते। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी और भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने के लिए भी सोनिया को याद किया जाएगा। अब सोनिया गांधी की राजनीतिक विदाई का समय आ गया है। उन्हें चाहिए कि वह अध्यक्ष पद ही नहीं, बेटे को हर हाल में अध्यक्षी सौंपने की जिद भी छोड़ें। आगे का फैसला पार्टी और राहुल गांधी पर छोड़े दें।

निष्कासित कर दिया। इंदिरा ने प्रतिद्वंद्वी संगठन की स्थापना की, जिसे कांग्रेस (आर) आर फॉर रिक्वायरमेंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरे समूह वाली कांग्रेस को कांग्रेस (ओ)- ओ फॉर ऑर्गनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1997 में ममता बनर्जी ने अलग होकर तृणमूल कांग्रेस, तो 1999 के चुनावों से पहले मराठा दिग्गज शरद पवार ने सोनिया के विदेशी मूल मुद्दे के खिलाफ विद्रोह करते हुए पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। 2011 में जगनमोहन रेड्डी ने पिता की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री पद से वंचित होने के बाद पार्टी छोड़ दी। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई।

कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट तीन बड़े विभाजन के बाद से देखी गई है। इन विभाजन ने राज्यों में कांग्रेस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ममता पश्चिम बंगाल में वास्तविक कांग्रेस के रूप में उभरी हैं। वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने

दूसरे कार्यकाल में हैं। जगन ने आंध्र में कांग्रेस को कम कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को 15 वर्षों तक पवार के साथ गठबंधन में सत्ता में रहना पड़ा। दोनों पार्टियां राज्य में कांग्रेस के साथ जूनियर विकास के रूप में महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा हैं। इन तीन पार्टियों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 8.1 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, जिसमें 49 सीटें जीतीं, जो कांग्रेस की 52 की तुलना में 3 सीटें कम हैं। यदि ये विभाजन नहीं हुए होते, तो कांग्रेस 110 सीटों की सम्मानजनक जीत हासिल कर लेती। साथ ही उसे आम चुनाव में 28 प्रतिशत वोट मिलते।

इससे इंकार नहीं कि कांग्रेस गांधी परिवार पर आश्रित है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि पार्टी को कामचलाऊ ढंग से चलाया जाए। राहुल के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से ऐसा ही किया जा रहा है। राहुल के इस्तीफा देने के बाद जब सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया तब यह माना गया था कि कांग्रेस जल्द

पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन करेगी और हो सकता है कि वह गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य हो, लेकिन एक वर्ष बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। इससे यही संकेत मिला कि गांधी परिवार यथास्थिति कायम रखना चाह रहा है। इसकी पुष्टि राहुल की ओर से बिना कोई पद लिए पार्टी के फैसले लेते रहने से भी हुई है।

राहुल गांधी पार्टी को कोई दिशा नहीं दे पा रहे, इसकी पुष्टि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से तो हुई ही, राजस्थान कांग्रेस के संकट से भी हुई, जो जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचा। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को वरिष्ठ नेता अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। दरअसल वे राहुल के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य उज्ज्वल नहीं देख रहे हैं। राहुल की राजनीति का एकमात्र मकसद प्रधानमंत्री पर लांछन लगाना नजर आता है। उनके ट्वीट और बयान यदि कुछ कहते हैं तो यही कि उनकी राजनीति प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने पर केंद्रित है। उनके इस रवैए से कांग्रेस का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि राहुल के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी की साख कई गुना अधिक है।

राहुल ने न तो 2014 की पराजय से कोई सबक सीखा और न ही 2019 की हार से। कांग्रेस ने 2019 का लोकसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा था। चुनावों के दौरान राहुल ने राफेल सौदे को तूल देकर प्रधानमंत्री पर खूब अमर्यादित हमले किए, लेकिन नतीजे में कांग्रेस को एक और करारी हार मिली। इस हार से शर्मिंदा होकर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उन तौर-तरीकों को नहीं छोड़ा जो उनकी छवि के साथ कांग्रेस पर भी भारी पड़ रहे हैं। उनकी अपरिपक्व राजनीति से कांग्रेस के तमाम नेता सहमत नहीं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े हैं। शायद इसलिए कि उनकी चाटुकारिता करने वाले उन्हें इसके लिए शाबासी देते हैं कि वह मोदी पर हमला करके बिल्कुल सही कर रहे हैं।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला अवश्य लिया गया कि 6 महीने में पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज की जाएगी, लेकिन इसमें संदेह है कि यह कैसे हो सकेगा जैसे कांग्रेस के 23 नेता चाह रहे हैं। भले ही राहुल यह कह रहे हों कि वह अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और प्रियंका गांधी भी कह चुकी हों कि अध्यक्ष परिवार से बाहर का बनना चाहिए, लेकिन एक गुट राहुल को ही अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा है। राहुल के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष बनीं सोनिया गांधी ने जिस तरह पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई उससे यह नहीं लगता कि परिवार के बाहर का कोई नेता पार्टी अध्यक्ष बन सकता है।

● इन्द्र कुमार

पिछले 2 साल से भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध कटु होते जा रहे हैं। ऐसे में चीन अपने आपको मजबूत करने में लगा हुआ है। इसको देखते हुए भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति का नया रखाका तैयार किया है। अब देखना यह है कि भारत सरकार के यह नीति कितनी कारगर होती है।



नेबरहुड फर्स्ट नीति का नया रंग

मोदी सरकार के कार्यकाल में नेबरहुड फर्स्ट की नीति का नया रंग अब देखने को मिलने वाला है। एक तरफ भारत जहां सीमाओं से परे दिल के करीब देशों के साथ व्यवहार गहराएगा। वहीं छोटे-छोटे देशों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं की भी नींव रखेगा। गत दिनों पहले ही मालदीव की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजना लगाने का ऐलान करने के बाद भारत की तरफ से जल्द ही नेपाल को लेकर इस तरह की घोषणा होगी। भारत की इकोनोमी खुद मंदी की गिरफ्त में है, लेकिन मदद पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

सूत्रों के मुताबिक इन सभी परियोजनाओं को लेकर भारत की तरफ से होने वाली तैयारियां लगभग पूरी हैं। जैसे वर्ष 2017 में भारत की तरफ से जो रेलवे परियोजनाओं की मदद का ऐलान किया गया था और अब दोनों की संभाव्यता रिपोर्ट जल्द ही पूरी होने वाली है। भारतीय अधिकारी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हाल के महीनों में नेपाल की तरफ से राजनीतिक मानचित्र को लेकर जो बयानबाजी की गई है उससे इन परियोजनाओं की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा है। सनद रहे कि 15 अगस्त को नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली व मोदी के बीच बात हुई है। चीन से बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों की खबरों के बीच भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद से मिलने पिछले महीने ढाका पहुंचे तो उन्हें लगभग 3-4 घंटे तक इंतजार कराया गया। इससे पहले बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास ने अपनी अर्जी लगा रखी थी। लेकिन चार महीनों के इंतजार के बाद भी शेख

हसीना ने उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया। बांग्लादेश के अखबार 'भोरेर कागोज' ने खबर छपी कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में भारतीय प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए हैं लेकिन चीनी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को खूब बढ़ावा मिल रहा है।

भारत के दूसरे पड़ोसी देश नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लिपुलेख-लिंप्याधुरा और कालापानी विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता था। लेकिन हमारी सरकार की ओर से कोशिश के बावजूद भारत ने विदेश-सचिव लेवल की बातचीत के हमारे आग्रह का कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर है दोनों देशों के संबंध इस दौरान लगातार खराब हुए हैं और सीमा पर टकराव तक की घटना हो गई, जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी।

एक अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से

दरखास्त की थी कि उनके देश पर भारत के लगभग 96 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगी की मियाद आगे बढ़ा दें। लेकिन पांच महीने बाद भी भारत की ओर से इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। श्रीलंका ने चीन से मदद मांगी। चीन ने उसे आसान शर्तों पर 50 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया। ये तीनों मामले यह बताने के लिए काफी हैं कि 2014 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने के लिए जिस 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी की स्क्रिप्ट लिखनी चाही थी, वो अब एंटी क्लाइमेक्स में पहुंचती दिख रही है।

याद कीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान समेत सभी दक्षिण एशियाई यानी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने भी हिस्सा लिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही नरेंद्र मोदी सीधे विमान से पाकिस्तान पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशिया में विदेश नीति का

पड़ोसी देशों को मदद करने की भारत की मंशा

पड़ोसी देशों को मदद करने की भारत की मंशा का पता मालदीव के लिए तीन दिन पहले की गई घोषणा से भी चलता है। भारत ने वहां के तीन द्वीपों को कनेक्ट करने वाली मालदीव की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए अभी 40 करोड़ डॉलर की मदद दी जा रही है जिसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। 6.72 किलोमीटर लंबी यह हाईवे परियोजना चीन की मदद से तैयार फ्रेंडशिप परियोजना तकराबन चार गुना बड़ी होगी। पिछले कुछ महीनों में भारत मालदीव के लिए 2.50 अरब डॉलर की परियोजनाओं का ऐलान कर चुका है। असलियत में भारत द्वारा हिंद महासागर के तीनों पड़ोसी देशों श्रीलंका और मॉरीशस को अभी 7.5 अरब डॉलर की परियोजनाओं व आर्थिक मदद दी जा रही है। आगे इसे बढ़ाने को भी भारत तैयार है और कई दूसरी परियोजनाओं पर भी विमर्श हो रहा है। श्रीलंका की पस्त इकोनोमी व स्थानीय मुद्रा को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 40 करोड़ डॉलर की मदद देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा 1.1 अरब डॉलर की दूसरी परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है जिसकी घोषणा भी जल्द की जा सकती है।

कोई नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही पठानकोट पर हुए आतंकी हमलों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ उलझे रिश्तों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कम ही लोगों की उम्मीद थी कि वह अपनी चाल बदलेगा। अलबत्ता नेपाल और बांग्लादेश के साथ रिश्ते मजबूत करने में प्रधानमंत्री को शुरुआत में अच्छी सफलता मिली। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने नेपाली संसद को संबोधित किया तो पूरा नेपाल मानो अभिभूत हो गया। लेकिन जल्द ही मजबूत होते दिख रहे इस रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगी क्योंकि भारत ने उप्र और बिहार से सटे तराई वाले इलाकों में रहने वाले मधेशियों का साथ देना शुरू किया। तराई की मधेशी पार्टियों ने भारत से आ रहे सामानों की 2015 में नाकेबंदी शुरू कर दी और इससे नेपाल में हाहाकार मच गया।

भारत नेपाल के लोगों के लिए दुश्मन नंबर एक बनकर उभरा। इस बीच केपी ओली और उनकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भारत के खिलाफ उभरे आक्रोश को धुनाने में सफल रही। लेकिन ओली जब सत्ता में आए तो मोदी सरकार उनसे बेहतर संबंध बनाने में जुट गई। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को तुरंत काठमांडू भेजा गया। ओली को खुश करने के चक्कर में भारत ने मधेशी दलों और अपने पुराने सहयोगी नेपाली कांग्रेस पार्टी दोनों को छोड़ दिया। आज ओली चीन की शह पर भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं।

मधेशियों की नाकेबंदी हाल के दिनों में भारत-नेपाल रिश्तों का सबसे खराब प्रसंग बन गई और यही वह दौर था, जब चीन को नेपाल को पूरी तरह अपने पाले में करने का मौका मिल गया। अब चीन नेपाल की राजनीति से लेकर इसकी अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं से लेकर इसके लोगों के दिलो-दिमाग पर पूरी तरह छा गया है।

चीन और नेपाल के बीच कारोबार अब तक के सर्वोच्च स्तर 1.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन नेपाल को आर्थिक मदद देने वाला सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। नेपाल किस कदर चीन के पाले में चला गया है इसका सबूत तो उसी समय मिल गया, जब चीनी राजदूत ने खुलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में प्रचंड और ओली गुट के बीच मध्यस्थता की। नेपाल में हालात अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण से बाहर लग रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भी भारत के रिश्ते ढलान पर दिख रहे हैं। हाल के दिनों में बांग्लादेश के साथ मनमुटाव को खत्म करने के लिए इसने

काफी फुर्ती दिखाई। बांग्लादेश को लगातार मदद की खेप पहुंचाने से लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अचानक प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद से मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भारत उस पर बढ़ते चीन के प्रभाव से किस कदर परेशान दिख रहा है। मोदी सरकार को अपने पहले दौर में बांग्लादेश से रिश्तों को मजबूत करने में खासी सफलता मिली थी। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक जमीन समझौता हुआ था। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर सहमति बनती दिखी, कुल 22 समझौते हुए थे। लेकिन पिछले साल भारत में सीएए और एनसीआर लागू होने के साथ ही बांग्लादेश के साथ रिश्तों की रंगत बदलने लगी। सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने जिस तरह से बांग्लादेशी विरोधी बयान दिए उनसे बांग्लादेश के लोगों के तन-बदन में

आग लग गई।

गृहमंत्री अमित शाह ने 2018 में असम में रह रहे बांग्लादेशियों को दीमक करार दिया। बंगाल भाजपा के चीफ दिलीप घोष ने कहा कि उनके राज्य में एक करोड़ बांग्लादेशी दो रुपए किलो वाले चावल पर पल रहे हैं। इन सभी बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। लगभग 7 से 8 फीसदी की दर से विकास कर रहे और कई सोशल और डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन वाले बांग्लादेश के सम्मान पर यह बड़ी चोट थी। सीएए के मामले में बांग्लादेश पर हमले इतने बढ़े कि उसके विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। शेख हसीना को यह चिंता भी हुई कि मुकदमे और जेल भेजे जाने के डर से भारत में रह रहे लाखों बांग्लादेशी वापस देश लौट सकते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों

का बोझ ढो रहे बांग्लादेश के लिए यह नई मुसीबत बन सकती थी। बांग्लादेश के स्वाभिमान पर जिस तरह चोट की गई, उसने इसे चीन की ओर झुकने को मजबूर किया। बांग्लादेश ने हाल में सिलहट में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण का ठेका बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दे दिया। चीन ने बांग्लादेश की नौसेना को मजबूत करने के लिए कई डिफेंस डील की हैं। हाल में बांग्लादेश से निर्यात होने वाले 97 फीसदी सामान चीन में ड्यूटी फ्री कर दिए।

भारत श्रीलंका में भी मौके गंवाता जा रहा है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के



भारत पड़ोसी देशों पर अपनी पसंद की परियोजनाओं को नहीं थोपेगा

भारतीय कूटनीति की यह भी कोशिश होगी कि बांग्लादेश और भूटान की इस तरह से मदद की जाए ताकि वो कोविड-19 के प्रभाव से जल्द से जल्द निकल सके। कोविड-19 के बावजूद इन देशों के साथ भारतीय मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं पर लगातार विमर्श चल रहा है और उनकी समीक्षा की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत इन देशों पर ना तो अपनी पसंद की परियोजनाओं को थोपेगा और ना ही इन्हें शर्तों के साथ मदद दी जाए। इस बारे में सारा फैसला इन देशों को ही करना है। यह तरीका चीन की तरफ से दी जाने वाली मदद से अलग है। सनद रहे कि कई देशों में चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर काफी बेचैनी है। चीन पर मदद के बहाने के ऋण से जाल में फंसाने के आरोप लग रहे हैं।

भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे तो चीन से बहुत लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तुरंत कोलंबो पहुंच गए थे। इसके बाद राजपक्षे भारत दौरे पर आए थे। इसके बावजूद भारत ने जिस तरह से कर्ज भुगतान की मियाद बढ़ाने के श्रीलंका के अनुरोध की अनदेखी की उससे उसके सामने एक बार फिर साफ हो गया कि बड़े दावों के बावजूद भारत की दोस्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछले डेढ़-दो साल से इन तीनों अहम पड़ोसियों के साथ भारत के खराब रिश्तों ने इसकी 'नेबरहुड फ्रेंड' पॉलिसी पर स्वालिया निशान लगा दिया है। कोविड-19 ने पड़ोसियों को पैसे से जीतने की भारत की ताकत को और कमजोर कर दिया है। चीन इस स्थिति का बेजा फायदा उठा सकता है। अमेरिका और अरब देशों से संबंध मजबूत करने में पूरी तरह व्यस्त मोदी सरकार की विदेशी नीति नजदीकी पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने के मामले में मात खाती दिख रही है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली छत्तीसगढ़ भाजपा इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में एकछत्र होकर राज करने वाली भाजपा के सामने इस वक्त खुद अपनी ही पार्टी का नारा चाल चरित्र और चेहरे को लेकर संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है।

भाजपा के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अनुशासन की दीवार को ढहाते दिख रहे हैं। राज्य की सत्ता से भाजपा के बाहर होने के

बाद पार्टी कार्यकर्ता सीधे तौर पर बड़े नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को एक कमजोर अध्यक्ष बताया जा रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करने को लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

राज्य की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जब कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर डॉ. रमन और सौदान के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मीडिया प्रमुख रहे देवेन्द्र गुप्ता ने तो सौदान सिंह को भाजपा का सौदागर तक कह दिया। बता दें, प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के दिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद उपेक्षा से नाराज कार्यकर्ताओं को बल मिला और उन लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर बम फोड़ना शुरू कर दिया। मामले को लेकर एक कार्यकर्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सच्चिदानंद उपासने जैसे वरिष्ठ, कर्मठ, जमीन, निष्ठवान की जब नहीं सुनी जा रही है, तो कार्यकर्ताओं की क्या सुनी जाएगी। भाजपा के पत्रों में खुद के लिए देवतुल्य शब्द सुनकर ही कार्यकर्ता खुश हो ले। अपने फेसबुक प्रोफाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लगाए अंबिका ठाकुर ने पोस्ट किया- सत्ता में जो बीज बोए जहर का, वह सत्ता जाने के बाद अमृत पाने की अपेक्षा क्यों पाले हैं। पूर्व में संगठन का कार्यकाल दो वर्ष का था, फिर तीन वर्ष किया गया, अब कार्यकर्ता पूछ रहा है कि जिलाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का है। मांग की जा रही है कि पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष बने और रायपुर का जिलाध्यक्ष कब चुना जाएगा इस बारे में भी जानकारी चाही।

महाभारत का 16वां अध्याय शुरू कर रहे कार्यकर्ता भाजपा नेता अनूप मसंद ने सोशल मीडिया पर महाभारत का 16वां अध्याय शुरू करने के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया

भाजपा में अंतर्कलह



रमन के इर्द-गिर्द सिमटकर रह गई भाजपा

छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहते हुए पूरी पार्टी मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई। रमन सिंह पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ भाजपा का एकमात्र चेहरा थे और भाजपा ने विधानसभा चुनाव भी रमन सिंह के चेहरे पर ही लड़ा लेकिन चुनाव में जिस तरह भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा उसके बाद पार्टी के अंदर से ही रमन सिंह के विरोध में स्वर उभरने लगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 15 साल सत्ता में रहते हुए जिस तरह चाल यानी काम किया उस पर विधानसभा चुनाव के परिणाम ने सवाल उठा दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा जिस रमन सरकार के मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में पीटती थी वो पार्टी विधानसभा चुनाव में 15 सीट पर सिमट गई। सूबे में बड़े नेताओं के बीच गुटबाजी शुचिता की राजनीति करने वाली पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। जिसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा।

है। मसंद ने लिखा- सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भाजपा को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। किसके कारण हुआ, सब जानते हैं। आइए हम सब मिलकर विसंगतियों को दूर करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ताला लगाएं। हम महाभारत का 16वां अध्याय आरंभ करते हैं और सौगंध खाते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा का कमल फिर खिलेगा। इसके लिए पहले आंतरिक चक्रव्यूह तोड़ा जाएगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदरानी खुलकर एक-दूसरे के खिलाफ आ गए हैं, लेकिन दुर्गा, सरगुजा, राजनांदगांव में भी नाराजगी सतह पर आने लगी है। सरगुजा और सूरजपुर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया है। सरगुजा में लल्लन प्रताप सिंह और सूरजपुर में बाबूलाल अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। बाबूलाल को रेणुका का विरोधी कहा जाता है, इसलिए आने वाले समय में विवाद बढ़ने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा में कार्यकर्ता पहले ही सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे थे। अब नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। वरिष्ठ नेता उपासने और पूर्व विधायक सुंदरानी के बीच विवाद को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि दोनों

प्रवक्ता की जिम्मेदारी पर हैं। पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में दोनों पक्ष रखते थे। यही वजह है कि दोनों के बीच विवाद को भाजपा के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। अब केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह के नाराज होने की खबर आ रही है। रेणुका सरगुजा में भारत सिंह सिंसोदिया और सूरजपुर में शशिकांत गर्ग को अध्यक्ष बनाना चाहती थीं। इसके विपरीत संघ के करीबी नेताओं को मौका दिया गया है। इससे पहले रायपुर सांसद सुनील सोनी की पसंद सुरेंद्र टिकरिया को दरकिनार कर पूर्व विधानसभा स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल की पसंद पर डॉ. सनम जांगड़े को जिलाध्यक्ष बना दिया गया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय भी मधुसूदन यादव को जिलाध्यक्ष बनाने से संतुष्ट नहीं हैं। दुर्गा और भिलाई संगठन जिलों में अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि सांसद विजय बघेल की पसंद के मंडल अध्यक्ष भी नहीं बने। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर साहू ने उपासने और सुंदरानी के बीच लड़ाई के संबंध में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पार्टी के भीतर का मामला है, इसलिए बाहर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि संगठन को हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाना चाहिए।

● रायपुर से टीपी सिंह

मुंबई में कंगना रनौत का दफ्तर तोड़े जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है, लेकिन राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। जहां कंगना के समर्थन में रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई महाराष्ट्र में मोर्चा संभाले हुए है। वहीं सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को फ्रंटफुट पर आगे बढ़कर खेलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन असल बात तो यह है कि शिवसेना और भाजपा की राजनीतिक जंग में कंगना रनौत मोहरा बन कर रह गई हैं। तात्कालिक तेजी तो इसमें बिहार चुनाव की वजह से देखने को मिल रही है, लेकिन ये तूल तब ज्यादा पकड़ सकता है जब बिहार चुनाव के बाद भाजपा महाराष्ट्र पर फोकस शुरू करेगी और वही वक्त उद्धव ठाकरे सरकार के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा।

कंगना रनौत के मामले में बीएमसी ने हद से ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाई होती तो मणिकर्णिका फिल्म का दफ्तर अपनी जगह यूं ही बना हुआ होता। बीएमसी को भी तो ये एहसास होगा ही कि मामला अदालत पहुंचा तो उसके जेसीबी पर हाईकोर्ट का हथौड़ा भारी पड़ेगा ही, लिहाजा गेट पर एक नोटिस चिपकाने के बाद घड़ी देखकर 24 घंटे होते ही बीएमसी ने अपने टास्क को अंजाम दे डाला। ऐसा भी नहीं कि बीएमसी ने पहली बार किसी बॉलीवुड स्टार के खिलाफ ऐसी सख्ती दिखाई है। शाहरूख खान से लेकर कपिल शर्मा जैसी हस्तियां भी बीएमसी के निशाने पर आ चुकी हैं, लेकिन 24 घंटे में तोड़फोड़ की जैसी तत्परता बीएमसी ने कंगना रनौत के मामले में दिखाई है वो पहली बार देखने को मिला है।

कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को उनके और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की एक-दूसरे के प्रति तीखी बयानबाजी के नतीजे के तौर पर देखा जा सका है। एक इंटरव्यू में संजय राउत वैसे तो सीधे-सीधे कुछ बोलने से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीएमसी के एक्शन को वो सही ठहरा रहे थे। संजय राउत ने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि शिवसेना के पास भी उसकी जानकारी हो ही। दफ्तर में तोड़फोड़ की टाइमिंग को लेकर पूछे जाने पर संजय राउत का कहना रहा कि इसकी टाइमिंग क्या है इसका जवाब बीएमसी कमिश्नर ही दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि आगे अदालत में भी इसका जवाब बीएमसी को ही देना है।

शिवसेना को ये निराश कर सकता है कि बीएमसी के एक्शन को महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार एनसीपी नेता शरद पवार ने भी ये सही नहीं माना है। शरद पवार ने तो बीएमसी के एक्शन में भेदभाव को लेकर भी सवाल उठाया है। महाराष्ट्र की गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार में एनसीपी भी एक साझीदार है। एनसीपी प्रमुख



कंगना रनौत तो बहाना है

कंगना ने अयोध्या से लेकर कश्मीर तक जोड़ा

कंगना रनौत ने अपने वीडियो मैसेज में उद्धव ठाकरे को कोसते हुए अयोध्या से कश्मीर तक की याद दिलाई है। कंगना ने अपने साथ हुई बीएमसी की कार्रवाई को कश्मीरी पंडितों के साथ हुए व्यवहार से जोड़ने की कोशिश की है। कंगना रनौत का कहना है कि अयोध्या के साथ ही साथ वो कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। कश्मीर पर फिल्मों तो बहुत बनी हैं, लेकिन कंगना की फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर फोकस रहेगी, फिल्म स्टार ने ऐसा संकेत दिया है। कंगना रनौत ने मणिकर्णिका फिल्म के दफ्तर को राम मंदिर बताया है और शिवसेना को बाबर बताते हुए ऐलान किया है कि मंदिर फिर बनेगा, जय श्रीराम। कंगना रनौत के दफ्तर को मंदिर बताते हुए अयोध्या से जुड़ी धार्मिक भावनाओं और कश्मीर के साथ राष्ट्रवाद से जोड़कर उन लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। शिवसेना के खिलाफ भाजपा को ऐसे ही मुद्दे की जरूरत है जिसकी बंदोबत वो मराठी मानुष और मराठी अस्मिता में फंसे बगैर शिवसेना को कठघरे में खड़ा कर सके, क्योंकि बिहार के बाद और पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले भाजपा का अगला एजेंडा महाराष्ट्र सरकार ही तो है।

शरद पवार का कहना है कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना रनौत को बोलने का मौका दे दिया है। शरद पवार ने मुंबई की दूसरी गैरकानूनी इमारतों की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये देखने की जरूरत है कि बीएमसी के अफसरों ने ये निर्णय क्यों लिया। शरद पवार ने ये भी कहा कि हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है, साथ ही शिवसेना को इशारों में समझाने की भी कोशिश की- 'आपको इन लोगों को प्रचार नहीं देना चाहिए।'

ध्यान देने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार में तो एनसीपी और कांग्रेस साझीदार हैं, लेकिन बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है।

महाराष्ट्र में सत्ता की अगुवाई कर रही शिवसेना बीएमसी और मुंबई पुलिस से वैसे ही काम ले रही प्रतीत होती है जैसे भाजपा के विरोधी केंद्र सरकार पर श्वष्ट और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगाते रहे हैं। उधर कंगना रनौत ने सीधे-सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर खूब खरी-खोटी सुनाई है और भाषा भी ऐसी कि आज तक ठाकरे परिवार के लिए शायद ही किसी ने खुलेआम ऐसे बोलने की हिमाकत की हो- 'तुझे क्या लगता है।' सवाल है कि कंगना रनौत में इतनी हिम्मत आई कहां से? साफ है बगैर राजनीतिक संरक्षण के कंगना रनौत के लिए भी ये सब संभव नहीं था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी के एक्शन को बदले की कार्रवाई और कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसा करने से महाराष्ट्र का सम्मान नहीं होता। कंगना रनौत ने एक साथ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को टारगेट किया। कंगना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के नाम पर केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ऐसा लगता है जैसे कंगना रनौत के चुप न होने से शिवसेना के गुरूर को धक्का लगा है। अब तक किसी ने शिवसेना को कंगना की तरह चैलेंज नहीं किया है। एक तो जमाना वो भी रहा है कि फिल्मों के शांतिपूर्ण रिलीज के लिए बड़ी-बड़ी फिल्मी हस्तियों को दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे के सामने भी लोग हाथ जोड़े खड़े नजर आए थे, लेकिन कंगना रनौत ने उस गुरूर को चुनौती दे डाली है।

● बिन्दु माथुर

राजस्थान में अब तक जो सियासी घमासान मचा हुआ था उसका निपटारा हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान फिलहाल भले ही थमती नजर आ रही है, लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि सियासी उठापटक का दूसरा अध्याय पहले से ही शुरू हो गया है। पहले सचिन पायलट की ही बात करें तो वे राजस्थान आ तो गए हैं, लेकिन अब उनके पास न तो उपमुख्यमंत्री का पद है और न ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का। फिर जयपुर आने के बाद उन्होंने मीडिया में जितने भी बयान दिए हैं उनमें एक ही लाइन को बार-बार दोहराया है कि 'पद हो या ना हो, प्रदेश की जनता के प्रति अपने दायित्व को निभाता रहूंगा'। उनकी इस बात का यह मतलब निकाला जा रहा है कि शायद राजस्थान में उन्हें पार्टी या सरकार में हाल-फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है। वे अपने समर्थकों को जताना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ स्वाभिमान के लिए ही थी और उन्हें कभी किसी पद का कोई लालच नहीं था। संभावना यह भी जताई जा रही है कांग्रेस हाईकमान पायलट को संगठन में प्रदेश के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी सौंप सकता है। हालांकि यह किसी से नहीं छिपा है कि उनका मन केंद्र के बजाय राजस्थान की राजनीति में ही ज्यादा रमता है।

विश्लेषकों के मुताबिक यदि सचिन पायलट तमाम हालातों के मद्देनजर दिल्ली में कोई जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो उनके लिए 2023 के अगले विधानसभा चुनाव तक राजस्थान की सरकार और पार्टी संगठन में कोई प्रत्यक्ष और प्रभावशाली भूमिका निभा पाने की गुंजाइश कम ही नजर आती है। इस हिसाब से राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कैरियर कम से कम तीन वर्ष के लिए पीछे खिसकता दिख रहा है। और यदि 2023 में राजस्थान के मतदाताओं ने चुनाव-दर-चुनाव सत्ता बदलने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पायलट को कम से कम 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक उनकी उम्र 50 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। और उस वक्त भी उनका वक्त तब आएगा जब सारी राजनीतिक परिस्थितियां उनके पक्ष में होंगी। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस दौरान पार्टी



सियासी उठापटक का दूसरा अध्याय

हाईकमान सूबे में किसी तीसरे चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकता है। कई पायलट समर्थकों का भी यह कहना है कि सचिन पायलट की पूरी लड़ाई खुद मुख्यमंत्री बनने की नहीं बल्कि गहलोत को पद से हटाने की थी। इनकी बात के समर्थन में कहा जा सकता है कि तीसरे मुख्यमंत्री का विकल्प पायलट ने 2018 में भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा था। हालांकि इसे समझना कोई मुश्किल बात नहीं कि पायलट के लिए यह मजबूरी का विकल्प ही रहा होगा। और इस विकल्प को सामने रखकर वे किसी न किसी तरह खुद की दावेदारी ही मजबूत करना चाह रहे होंगे।

वर्तमान घटनाक्रम से पहले तक इस बात का ठीक-ठाक अंदाजा शायद कम ही लोगों को था कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी विधायकों में से कितने पायलट के पक्ष में हैं और कितने गहलोत के। लेकिन हालिया घटनाक्रम के दौरान पायलट के साथ पार्टी के 100 में से सिर्फ 18 और तेरह निर्दलीय में से महज तीन विधायकों ने ही हरियाणा में डेरा जमाया था। गौरलतब है कि मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खोले गए मोर्चे में

पायलट अपने कई करीबी विधायकों और मंत्रियों तक का समर्थन हासिल नहीं कर पाए। इनमें राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रमुख थे जो इस पूरे विवाद के दौरान अपने बयानों के जरिए पायलट पर बड़े हमले बोलने की वजह से चर्चाओं में रहे थे। जबकि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा बहुत पहले ही पायलट से दूरी बना चुके हैं।

जानकारों की मानें तो कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की सचिन पायलट की मांग पर सिर्फ तभी विचार कर सकता था जब वे पांच सप्ताह हरियाणा में जमे रहने के बजाय शुरूआती दिनों में ही उससे जाकर मिल लेते। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के मौके पर एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोनों ही खेमे सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक पक्ष के विधायकों को तो मन मसोस कर रहना पड़ेगा। सत्याग्रह से हुई बातचीत में महान आगे जोड़ते हैं, 'इस सब के चलते राजस्थान कांग्रेस में जो अस्थिरता पैदा हो सकती है उसे भुनाने में भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चूक नहीं करेगी। वो तो वैसे भी किसी भी राज्य में 'ऑपरेशन लोटस' को अंजाम देने के लिए हरदम तैयार रहती है!' जानकारों की मानें तो इस पूरी रस्साकशी के बाद सचिन पायलट को राहुल गांधी के करीबी होने का लाभ तो मिला ही है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

इस पूरी उठापटक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीते हुए भी नजर आ रहे हैं और नहीं भी! वे अपने पद और सरकार को तो बचा पाने में सफल नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो मुख्य कवायद पायलट की सदस्यता रद्द करवाकर उन्हें हमेशा के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की थी उसमें वे नाकाम हुए हैं। कुछ जानकारों के अनुसार शायद गहलोत को इस बात का अंदाजा पहले से था कि देर-सवेर गांधी परिवार पायलट के

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर असर!

साथ संवाद करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए ही उन्होंने इस मामले में अति की जल्दबाजी भी दिखाई। लेकिन पहले तो पायलट गुट ने अदालत जाकर और फिर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा बुलाने की अनुमति न देकर गहलोत को अपनी रणनीति में कामयाब नहीं होने दिया। कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वह बागियों को मौके देने में विश्वास रखती आई है।

वि धानसभा और लोकसभा में परचम लहरा रही भाजपा ने 2022 के उप्र विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को संजोकर रखने के लिए 'मिशन 7500' तैयार किया है। दरअसल भाजपा सहकारिता के क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को जगह दिलाने की कोशिश में है। भाजपा की नजर उन सहकारी समितियों पर है, जहां शिवपाल यादव का झंडा बुलंद है। पशुपालन, दुग्ध विकास और हथकरघा जैसे अन्य समितियों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव तक शिवपाल यादव पर मुलायम दिख रही भाजपा अब सख्त नजर आ रही है। सहकारिता के लिए अब होने वाले चुनाव के लिए महामंत्री संगठन सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, महामंत्री विद्यासागर सोनकर सहित पार्टी पदाधिकारियों ने रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए एक सहकारिता से जुड़े लोगों की बैठक भी बुलाई गई। भाजपा की मानें तो भाजपा कार्यकर्ता सहकारिता को मजबूत करने के उद्देश्य से मैदान में उतर रहे हैं।

उत्तरप्रदेश में यह बैंक ग्रामीण स्तर के माने जाते हैं। इन्हीं बैंकों पर मुलायम परिवार 'तीन दशकों से कब्जा जमाए बैठा हुआ था।' मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों में सहकारिता समितियां बनाई थीं। इसके तहत किसानों, मजदूरों को संगठित करना, उन्हें लोन दिलाना, बैंक स्थापित करना, लैंड डेवलपमेंट करवाना मुलायम का बड़ा योगदान माना जाता है। यही नहीं मुलायम की राजनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार यही रहा है।

यहां तक कि मायावती के दौर में भी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक पूरी तरीके से 'यादव परिवार के कंट्रोल में ही रहा', लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार न सिर्फ 'सपा का तिलिस्म तोड़ा' बल्कि प्रचंड जीत के साथ भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। बता दें कि उत्तरप्रदेश सहकारी ग्रामीण बैंकों के लिए चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान है। इन बैंकों की शाखाओं के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए गए जिसमें भाजपा ने 323 शाखाओं में 293 पर जीत दर्ज कर शानदार परचम फहराया है। विपक्ष (जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है) को ग्रामीण बैंक की सिर्फ 19 सीटें मिली हैं, जबकि 11 सीटों पर चुनाव रद्द कर दिए गए थे।

सहकारी ग्रामीण बैंकों के चुनाव में कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट अमेठी के जगदीशपुर में ही जीत दर्ज करा सकी। दूसरी ओर विपक्षी दलों द्वारा जीती गई अन्य प्रतिष्ठित सीटों में वाराणसी, बलिया, गाजीपुर और इटावा है। इस जबरदस्त जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने

सहकारिता भगवामय

मुलायम कुनबा



समाजवादी पार्टी का दबदबा 1991 से

बात 1977 की है। जब उप्र सरकार में मुलायम सिंह यादव ने सहकारिता मंत्रालय संभाला था। दरअसल प्रदेश का सहकारिता विभाग पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से याद किया जाता है। बता दें कि 1991 से अब तक सहकारिता के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा बना हुआ था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को सहकारी ग्रामीण बैंकों का मुखिया बना दिया था। इन बैंकों पर शिवपाल सिंह यादव की इतनी तगड़ी पकड़ हो चुकी थी कि बसपा भी उसे नहीं तोड़ सकी थी, जबकि 2007 से 2012 तक मायावती पांच साल तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। बसपाकाल में सपाइयों ने कोर्ट में मामला उलझाकर चुनाव नहीं होने दिए थे और अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने सहकारी समितियों से समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव का किला ध्वस्त कर दिया है।

कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार ने चुनावों को हाइजैक कर लिया था, तभी हमारी हार हुई है।

मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव वर्ष 2005 से लगातार इस बैंक के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। इस बार प्रदेश की योगी सरकार ने सहकारी ग्रामीण बैंकों के नियमों में बदलाव करने से शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ सके हैं। प्रदेश में सहकारी ग्रामीण विकास बैंक की 323 शाखाएँ हैं। प्रत्येक शाखा से एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधि सूबे में अब 14 डायरेक्टर्स का चुनाव करेंगे, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति चुना जाएगा। इन जीते हुए शाखा प्रतिनिधियों द्वारा बैंक की प्रबंध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन 22 और 23 सितंबर को किया जाएगा। इस चुनाव के बाद अब बैंक के प्रबंध कमेटी पर भाजपा का नियंत्रण हो जाएगा और 23 सितंबर को बैंक के सभापति, उप सभापति और अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। बता दें कि उप्र सहकारी ग्रामीण बैंकों में शिवपाल यादव की

'बादशाहत' अभी तक कायम थी। पिछले दिनों शिवपाल की भाजपा सरकार से नजदीकियां भी सुखियों में रही थीं। इसके बावजूद उन्हें इन चुनावों में कोई फायदा नहीं मिल सका है। इन सहकारी बैंकों के चुनावों में शिवपाल अपनी और पत्नी की सीट बचाने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हो सके हैं।

वैसे कहने के लिए तो सहकारिता किसानों, मजदूरों, गरीब लोगों के लिए एक हथियार था, लेकिन आंदोलन कहीं और रह गया और विभाग राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का यंत्र बन गया। अब भाजपा की निगाहें इस पर लग गई हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सहकारिता के पशुधन, दुग्ध विकास, हथकरघा जैसे क्षेत्र में चुनाव होने हैं, वहां भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की एडजस्ट करने की जुगत में है। अभी तक सहकारिता में जहां-जहां चुनाव हुए हैं। वहां-वहां भाजपा का कब्जा नजर आ रहा है। समितियों का चुनाव सितंबर में होना है, जिस पर भाजपा की निगाहें लगी हुई हैं। 7500 सहकारी समितियों पर कब्जा अब भाजपा का लक्ष्य है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अटकलों का बाजार अभी से गर्म है। तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, पर राज्य के चुनावी गणित को समझने वालों के लिए यह कोई पहली नहीं है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजों से यह साफ है कि राज्य के अधिकतर मतदाता तीन राजनीतिक

शक्तियों—जदयू, भाजपा और राजद के साथ प्रमुखता से जुड़ चुके हैं। इनमें से कोई भी दो दल मिलकर तीसरे को हरा देते हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू ने मिलकर कुल 243 में से 206 सीटें हासिल कर ली थीं तो 2015 के विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद मिलकर विजयी रहे थे। दरअसल असली ताकत जदयू-राजद की ही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस गठबंधन में शामिल होकर 27 सीटें हासिल कर ली थीं।

आगामी चुनाव में जदयू, भाजपा और लोजपा साथ-साथ रहेंगे, इसकी संभावना है। ऐसी स्थिति में राजद के लिए कोई संभावना नहीं बनती प्रतीत हो रही है। 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद और लोजपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों को मिलाकर विधानसभा की मात्र 25 सीटें ही मिल पाई थीं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तत्व अधिक प्रभावकारी रहता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू भाजपा के साथ नहीं थी। इसके बावजूद राजग को बढ़त मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा, जदयू और लोजपा ने मिलकर बिहार में कमाल ही कर दिया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज को छोड़कर बाकी सभी 39 सीटें राजग को मिल गईं। उसी मोदी लहर की पृष्ठभूमि में बिहार विधानसभा का अगला आम चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश बिहार में राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का भी असर पड़ता रहता है। हाल के महीनों में इस तरह की कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मिला है।

रामविलास पासवान ने लोजपा की कमान पुत्र चिराग पासवान को सौंप दी है। उन्हें भाजपा से तो नहीं, किंतु नीतीश कुमार से कई शिकायतें हैं। चिराग के ऐसे बयान आते रहते हैं, जिनसे लगता है कि शायद उनकी पार्टी राजग से अलग हो जाएगी, लेकिन लगता यही है कि विधानसभा की अधिकाधिक सीटों पर लड़ने के लिए लोजपा का नया नेतृत्व दबाव बना रहा है।

सत्ता के समीकरण



मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर पहुंचाना एक चुनौती

कोरोना काल में हो रहे चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर पहुंचाना भी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती होगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अल्पसंख्यक और यादव मतदाता पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, किंतु राजग के मतदाता खासकर शहरी मतदाता आलस्य और कोरोना ग्रंथि के शिकार हो सकते हैं। वैसे चुनावी मुकाबले में राजद जब-जब अपनी अधिक ताकत दिखाने लगता है, तब-तब लालू विरोधी मतदाता भी सक्रिय हो जाते हैं। याद रहे कि लालू प्रसाद का परंपरागत यादव-मुस्लिम वोट अपवादों को छोड़कर अभी भी राजद के साथ है, पर साथ ही 15 साल का जंगलराज झेल चुके लालू विरोधी मतदाताओं में इस बार भी उत्साह की कमी नहीं होगी, ऐसी उम्मीद राजग जाहिर कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजग का पलड़ा भारी जरूर नजर आ रहा है, पर कई कारणों से बिहार का यह चुनाव पहले की तरह ही दिलचस्प और तनावपूर्ण रहेगा, भले ही पहले की तरह हिंसक न हो।

नीतीश विरोधी बयान उसी रणनीति का हिस्सा है। अंततः क्या होगा, यह तो आने वाले कुछ सप्ताह बताएंगे, पर यदि महत्वाकांक्षी लोजपा राजग से अलग भी हो जाए तो उसका कोई खास

असर नतीजे पर नहीं पड़ेगा। लोजपा के विकल्प के जुगाड़ में भी बिहार राजग का नेतृत्व लगा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी राजग को चुनावी लाभ पहुंचा सकती है। गत लोकसभा चुनाव में किशनगंज में भले कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत हुई हो, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार को 2 लाख 95 हजार वोट मिले थे। 2019 में हुए किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में तो ओवैसी के उम्मीदवार की जीत हो गई थी। इससे एआईएमआईएम का मनोबल बढ़ गया है।

ओवैसी ने देश में अपनी पार्टी के फैलाव की महत्वाकांक्षी योजना बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनके दल ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया है। जाहिर है ये 32 सीटें वही होंगी, जहां मुसलमानों की अच्छी-खासी आबादी है। एम-वाई यानी मुस्लिम-यादव वोट समीकरण पर

निर्भर राजद की राह में ओवैसी का दल रोड़ा बनने वाला है। इसका सीधा लाभ राजग को मिलेगा। वैसे तो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पिछली गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, किंतु राजद ने सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक का जो विरोध किया, उसके लिए उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। इस विरोध के कारण गत लोकसभा चुनाव में राजद के कम से कम दो जीतने योग्य सवर्ण उम्मीदवार हार गए थे। सवाल है कि विधानसभा चुनाव में अपवादों को छोड़कर सवर्ण मतदाताओं के मत राजद को कैसे मिल पाएंगे? राजद के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है।

बीते दिनों राजद से जुड़े विधान परिषद के पांच सदस्य जदयू में शामिल हो गए। छह विधायकों ने भी राजद छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया। आश्चर्यजनक रूप से उनमें तीन यादव थे। राजद छोड़ने वाले पांच एमएलसी में भी यादव और मुस्लिम थे। इतने कम समय में इतनी संख्या में विधायकों के राजद छोड़ने का हाल के वर्षों में यह एक रिकॉर्ड है। सवाल है कि ये विधायक राजद में अपना राजनीतिक भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्या उन्होंने हवा का रुख पहचान लिया है? अपने चुनावी भविष्य के प्रति चिंतित कांग्रेस और राजद के विधायकों में से कुछ अन्य विधायक भी आने वाले दिनों में दल छोड़ दें तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी।

● विनोद बक्सरी

ची न अपने दो प्रतिद्वंद्वियों से लड़ाई मोल लेने पर उतारू दिखता है- क्षेत्रीय स्तर पर भारत और वैश्विक स्तर पर अमेरिका से। और वह पिछले कुछ महीनों के दौरान दोनों के खिलाफ बारी-बारी से अपना जोर दिखा रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए चीन ने हाल ही में विवादित स्प्रेटलीज द्वीपों के पास दक्षिण चीन सागर में मध्यम दूरी की कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। जबकि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भारत के साथ उसकी तनातनी जारी है, और दोनों पक्षों की राजनीतिक-सैन्य चर्चाओं में कोई खास प्रगति नहीं हो रही है। यदि टकराव जारी रहा तो किसी सैन्य विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि रक्षा सेवा प्रमुख (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के हालिया बयान से जाहिर है।

चीन की इन गतिविधियों के पीछे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भूमिका है। शी दूसरा माओ बनने की उम्मीद पाले हुए हैं। हाल ही में उन्हें हटाए जाने के प्रयासों के बारे में भी अफवाहें सामने आई थीं। इसलिए वह अधीर नजर आते हैं। ऐसी खबरें हैं कि वह माओ द्वारा सुशोभित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के चेयरमैन के पद को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सीसीपी के चेयरमैन के रूप में अपना चौथा औपचारिक कार्यकाल हासिल कर वह जनता के बीच खुद को आधुनिक माओ दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से उन्हें अपने शासन के किसी भी तरह के विरोध को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके लिए शी जिनपिंग को अपनी जनता की नजरों में खुद की वैश्विक नेता की छवि भी बिठानी पड़ेगी। इसी उद्देश्य के लिए शी सबसे शक्तिशाली वैश्विक किरदार (अमेरिका) और सबसे ताकतवर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी (भारत) को चुनौती देने की रणनीति पर चल पड़े हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण चीन की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और आम चीनियों के कल्याण पर ध्यान देने के बजाय शी ने भारत के खिलाफ अपनी विस्तारवादी नीति को आजमाने के लिए अपने पश्चिमी सैन्य सेक्टर पर फोकस किया है। इसकी अन्य वजहें हो सकती हैं- कोरोनावायरस की उत्पत्ति पर छिड़े विवाद में चीन को भारत का साथ नहीं मिलना, और जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने की भारत की एकतरफा कार्रवाई। उसने सैनिक अभ्यास के बहाने चुपके से सैनिक जमावड़ा करके पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो के फिंगर कहे जाने वाले इलाकों, हॉट स्पिंग और गलवान में अतिक्रमण की कई वारदातें की हैं। अप्रैल-मई में, कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर ट्रंप प्रशासन के साथ

शी जिनपिंग दूसरा माओ



चीन को उसी की भाषा में जवाब

भारतीय और चीनी बलों के बीच सीमा पर तनातनी होती ही रही है, लेकिन इस बार चीन ने दोनों देशों के बीच हुए सीमा प्रबंधन समझौतों का उल्लंघन किया। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर अकारण हमला किया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत सरकार के अनुसार भारतीय जनहानि के मुकाबले चीनी पक्ष को 'दोगुनी से भी अधिक' मौतों का सामना करना पड़ा है। दक्षिण चीन सागर में विमानवाही पोतों को नष्ट करने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइलों डीएफ 21डी और डीएफ 26 को दाग कर चीन ने अमेरिका को एक रणनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि वह दक्षिण चीन सागर के द्वीपों और ताइवान पर उसके दावे के मामले में नहीं पड़े। 31 अगस्त को, अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान के तीसरे बेड़े ने अपना छमाही सैन्य अभ्यास संपन्न किया। बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल स्कॉट डी. कॉन ने कहा है कि अमेरिका चीनी कार्रवाइयों से डिगेगा नहीं क्योंकि दक्षिण चीन सागर समेत पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके 38 पोत मौजूद हैं। शी को हतोत्साहित करने की कार्रवाइयों के तहत अमेरिका ने 24 चीनी कंपनियों पर इस आधार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं कि उन्होंने दक्षिण चीन सागर में चीन के विवादास्पद द्वीप विकास कार्यक्रम में योगदान किया था।

हुई झड़प के बाद शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य कार्रवाइयों के जरिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की है।

सर्वप्रथम, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स (पीएलएएएफ) ने ताइवान के पास अप्रैल में 36 घंटे का सतत सैन्य अभ्यास किया। उसके तुरंत बाद पीएलए नौसेना के विमानवाही पोत

लियाओनिंग और पांच युद्धक पोतों के बेड़े को मियाको जलसंधि से होकर गुजारा गया। ताइवान को चीनी शक्तिप्रदर्शन की प्रतिक्रिया में अपने युद्धक विमानों और पोतों को सक्रिय करना पड़ा था। उससे पहले मार्च में पीएलएएएफ के प्रथम रात्रिकालीन मिशन की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के अनुसार, चीन ने फिलिपींस की नौसेना के पोत को धमकाने, वियतनाम की एक मछलीमार नौका को डुबोने तथा क्षेत्र में फिशिंग तथा तेल-गैस उत्खनन को लेकर क्षेत्र के अन्य देशों को डराने-धमकाने का काम किया है। इन परिस्थितियों में अमेरिका को क्षेत्र के देशों में आत्मविश्वास भरने के लिए दक्षिण चीन सागर में बारी-बारी से दो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभियान (एफएन ऑप्स) चलाने पड़े। शी के ताजा क्रियाकलापों की एक और वजह हांगकांग के आंदोलन से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बंटाना भी हो सकती है। वहां चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने की प्रतिक्रिया में आंदोलन शुरू हुए हैं। वैश्विक स्तर पर चीन निर्विवाद रूप से दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है और ऐसा लगता है कि वह अमेरिका के संकल्प की परीक्षा ले रहा है। वह नाइन-डैश लाइन तक के इलाके पर अपना अधिकार चाहता है, ताकि अमेरिका का प्रभाव खत्म करना तथा वियतनाम, फिलिपींस और मलेशिया जैसे क्षेत्रीय किरदारों को दबाकर रखना, और साथ ही ताइवान को अपने में आत्मसात करना संभव हो सके। उल्लेखनीय है कि ताइवान पर चीन अपना अधिकार जताता है। इसी तरह, यदि वह भारत को बेअसर कर पाता है, तो उससे क्षेत्र के देशों को चीनी इशारे पर चलने का स्पष्ट संदेश जाएगा।

● ऋतेन्द्र माथुर

भा रतीयों के मन में ये सवाल उमड़ रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ठीक रहेगा या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे कार्यकाल के चुना जाना। इस सवाल का जवाब पाने के लिए आइए देखें

कि पिछले दो दशकों के दौरान जो बाइडेन का भारत के प्रति क्या रुख रहा है। दिसंबर 2006 में रीडिफ इंडिया अब्राड को दिए इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था, 'मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया के सर्वाधिक निकटता से जुड़े दो राष्ट्र भारत और अमेरिका होंगे।' उन दिनों वह सीनेट की विदेश मामलों की समिति (एसएफआरसी) के वरिष्ठतम डेमोक्रेट सदस्य थे और उसके अगले महीने जनवरी 2007 में समिति के प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करने वाले थे क्योंकि नवंबर 2006 के चुनाव में सीनेट डेमोक्रेट के नियंत्रण में आ गया था।

इसके ठीक पहले बाइडेन ने समिति के तत्कालीन अध्यक्ष रिपब्लिकन सीनेटर रिचर्ड लुगार के साथ मिलकर 85-12 के अंतर से उस प्रस्ताव को पारित कराया था जिसमें भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए वार्ताएं जारी रखने की अनुमति दी गई थी। आखिरकार अक्टूबर 2008 में उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बीच की दो वर्षों की अवधि में दोनों ही देशों में समझौते की राह में कई चुनौतियां आईं और बाइडेन समझौते के लिए दृढ़ता से सीनेट में, खासकर विरोध में खड़े अपनी खुद की पार्टी के सदस्यों का, समर्थन जुटाते रहे। समझौते को लेकर आशंकित सीनेटरों की जमात में तब बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन भी शामिल थे, जो परमाणु अप्रसार लॉबी की चिंताओं से प्रभावित थे। इससे पूर्व एसएफआरसी का अध्यक्ष रहने के दौरान बाइडेन ने अगस्त 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी, जो कि मई 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के बाद से जारी थे।

बाइडेन इस समय अमेरिका के अधिकांश राष्ट्रव्यापी सर्वे में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पर 7-10 प्रतिशत की बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि नजदीकी

ट्रंप या बाइडेन



मुकाबले वाले कई राज्यों में उनकी बढ़त थोड़ी कम है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक होने वाले तीन प्रेसिडेंशियल बहसों में दोनों उम्मीदवारों का प्रदर्शन कैसा रहता है। उल्लेखनीय है कि 2016 में हिलेरी क्लिंटन लगातार आगे चल रही थीं, 19 अक्टूबर 2016 को तीसरी बहस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी बढ़िया रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक परिस्थितियां बदल गईं और चुनाव में प्राप्त कुल मतों में 3 प्रतिशत की बढ़त लेने के बावजूद निर्वाचक मंडल के मुकाबले में वह पीछे हट गईं। उस चुनाव में आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक रुझान रखने वाले मिशिगन, विस्कॉसिन और पेन्सिल्वेनिया जैसे राज्यों की जनता ने ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' के नारे और भूमंडलीकरण में खोए रोजगार को वापस अमेरिका लाने के वादे में भरोसा जताया। इसीलिए बाइडेन की जीत भी पक्की तो नहीं, लेकिन संभव जरूर कही जा सकती है।

भारत के लिए यह चुनौती और अवसर दोनों ही होगा। एक स्तर पर यह तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग जैसे क्षेत्रों में चीन के निरंकुशतावादी कार्यों को निशाना बनाने का मंच साबित हो सकेगा। बाइडेन समेत अनेक अमेरिकी नेता बारंबार भारतीय लोकतंत्र और साझा मूल्यों को भारत-अमेरिका संबंधों की बुनियाद बताते हुए इसे चीन एवं हिंद-प्रशांत संबंधी रणनीतियों के संदर्भ में अहम करार दे चुके हैं। हालांकि मुस्लिम-अमेरिकी समुदाय के लिए बाइडेन के चुनावी एजेंडे में कश्मीर में 'सभी के अधिकारों' की पुनर्बहाली का जिक्र है, जिसके अनुसार असहमति

जताने पर रोक तथा इंटरनेट पर पाबंदी या उसे धीमा करने जैसे उपाय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। साथ ही, बाइडेन 'असम में एनआरसी को लेकर निराशा' व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि सीएए भारत की 'लोकतंत्र की लंबी परंपरा तथा बहुजातीय एवं बहुधार्मिक लोकतंत्र को बरकरार रखने' की उपलब्धि के अनुरूप नहीं है।

यह रवैया केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील गुट के प्रभाव को ही प्रतिबिंबित नहीं करता है। विदेशी मामलों की अमेरिकी कांग्रेस की समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष और सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के वरिष्ठतम डेमोक्रेटिक सदस्य संयुक्त रूप से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर भारत की नागरिकता संशोधन कानून पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। साथ ही, पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और पार्टी के उभरते प्रगतिशील सांसदों में से एक प्रमिला जयपाल समेत कई भारतीय-अमेरिकी डेमोक्रेटों ने इन मुद्दों पर आलोचनात्मक रुख दिखाया है। हालांकि बाइडेन और उनके मुख्य विदेश नीति सलाहकार एंथनी ब्लिंकेन दोनों ने ही कहा है कि इन मुद्दों पर मतभेदों को मित्रों और साझेदारों के बीच होने वाले संवाद के जरिए निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। वैसे, अमेरिका को खुद अपने यहां समुदाय विशेष के वोटों को हतोत्साहित करने, चुनाव क्षेत्रों के मनमाफिक पुनर्निर्धारण, अप्रौकी-अमेरिकियों के खिलाफ हिंसा समेत अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सवालियों का सामना करना पड़ रहा है।

● कुमार विनोद

मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी के सख्त रुवें के

मद्देनजर भारत में बहुतांश के मन में ये दुविधा हो सकती है कि भारत के लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति सही रहेगा या रिपब्लिकन। इस बात को याद करना उपयोगी रहेगा कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किया था, और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध में चीन को शामिल करने के लिए गुप्त प्रयास भी किए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को रिपब्लिकन

रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट

राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मजबूत किया था, जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ को भगाने के वास्ते 'उग्रवादी जिहाद' के लिए उन्होंने आईएसआई के जरिए समर्थन और फंड की व्यवस्था की थी। भारत को पहले पंजाब में और फिर जम्मू-कश्मीर में आईएसआई प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया, और 2000 में भारत की ऐतिहासिक यात्रा कर अमेरिका और भारत के बीच नए संबंधों की नींव रखी।

मोदी सरकार द्वारा किए गए सारे काम एक तरफ ट्रिपल तलाक बिल एक तरफ। मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ट्रिपल तलाक बिल के लिए जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। ध्यान रहे कि ट्रिपल तलाक कानून को संसद से पास हुए एक साल पूरा हो गया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया है। चाहे वो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हों या फिर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार सहित कई मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। भाजपा के मंत्रियों का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को जाता है।

बात भाजपा और मोदी सरकार की हुई है तो बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी की शान में कसीदे पढ़ते हुए ये तक कह दिया है कि कि मोदी सरकार 'सियासी शोषण' नहीं बल्कि 'समावेशी सशक्तिकरण' के संकल्प के साथ काम करती है और तीन तलाक को खत्म करके सरकार ने मुस्लिम समाज की आधी आबादी को सम्मान, सुरक्षा और समानता दिलाने का काम किया है। ध्यान रहे कि संसद में कानून पास होने से पहले तलाक के मद्देनजर मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। शरिया कानून का हवाला देकर जरा-जरा सी बात पर तलाक दे दिया जाता था। पूर्व में हम ऐसे तमाम मामले देख चुके हैं जिनमें उस परिस्थिति तक में तलाक दे दिया गया जब पति को खाने में नमक कम मिला या फिर पति की किसी नाजायज मांग पर पत्नी ने अपनी आवाज बुलंद की।

गौरतलब है कि कानून पास होने से पहले मुस्लिम वर्ग शरिया की दुहाई देता था और तब मुसलमानों के एक तबके द्वारा यहां तक कहा जाता था कि मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं में किसी की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। बात उस दौर की चल रही है तो हमारे लिए दारुल उलूम देवबंद और बरेली मरकज जैसे इदारों की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात काबिल-ए-गौर है कि



ट्रिपल तलाक आसान नहीं

जिस वक्त सरकार ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति पर लगाम कसने पर विचार कर रही थी उस वक्त यही वो संस्थाएं थीं जिन्होंने मामले पर खूब हो हल्ला मचाया था और सड़क पर आकर मोदी सरकार की नीति का विरोध किया था मगर सरकार ने इनकी कोई परवाह नहीं की और एक ऐसा फैसला लिया जो तारीखी है।

करीब एक साल पहले जिस वक्त ये बिल लोकसभा में पास हुआ बिल के पक्ष में 245 जबकि विरोध में 11 वोट पड़े। बिल के पास होने के बाद कांग्रेस, एआईएडीएमके, डीएमके और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। तब इन दलों के सदस्यों के सदन से वॉकआउट ने खुद-ब-खुद इस बात की अनुभूति करा दी थी कि कैसे इन दलों ने आजादी के 70 सालों बाद मुस्लिम समाज और इस समाज की महिलाओं को बेवकूफ बनाया और अपनी सियासत चमकाने के

चलते इन्हें हाशिए पर रखा। बताते चलें कि क्योंकि विधेयक में सजा के प्रावधान का जिक्र था इसलिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिल का कड़ा विरोध किया था। तब विपक्ष द्वारा मांग उठाई गई कि बिल को जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। वहीं बिल पर सरकार का तर्क था कि यह किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना है।

तीन तलाक और इसके कानून पर गौर करें तो मिलता है कि तीन तलाक स्त्री या फिर पुरुष का मसला नहीं है। ये समस्या देश के एक आम मुसलमान की समस्या है। इसका शिकार मुस्लिम समाज में कोई भी हो सकता है। किसी की भी मां, बहन, भाभी इत्यादि को तलाक दिया जा सकता है। जिस वक्त ये बिल आया उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की खूब आलोचना हुई थी। कहा गया है कि इस बिल को पास करके प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज के लोगों से बदला लिया है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि चूंकि मुस्लिम पुरुष भाजपा को वोट नहीं करते इसलिए इस पहल के जरिए भाजपा आम मुस्लिम महिलाओं को रिझाने और उनके वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

मुस्लिम परस्त पार्टियों के मुंह पर पड़े थप्पड़ की तरह है ये बिल

आज हमारे बीच कांग्रेस समेत ऐसे तमाम सियासी दलों की भरमार है जो अपने को मुस्लिम परस्त कहती हैं और कभी रोजा इफतार तो कभी कुछ और करके वोट बैंक की राजनीति को अंजाम देती हैं मगर जब बात ट्रिपल तलाक पर कुछ करने की आई तो इन्होंने देश के मुसलमानों को पीट दिखा दी। सवाल ये है कि इस बिल के पास होने तक आखिर मुस्लिम दल क्या कर रहे थे? आखिर क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखी थी? साफ है कि इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने न सिर्फ एक बड़ा रिस्क लिया बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाया। साफ बात है कि

इस कानून ने तमाम मुस्लिम परस्त पार्टियों के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ने का काम किया। बहरहाल अब इस कानून को आए एक साल हो गए हैं। साथ ही जिस तरह की सजा इस कानून में है उसने बड़े से बड़े तुरम खां की हवा टाइट कर दी है और जिस तरह मुस्लिम समाज के लोग बड़े ही गर्व के साथ अपने घर की महिलाओं को सीना टोक के तलाक दे दिया करते थे अब ये उनके लिए दूर की कोड़ी हो गया है। वाकई ये मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है जिसके लिए मुस्लिम समाज की औरतें हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी की आभारी रहेंगी।

भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से सवाल किया था कि निर्गुण और सगुण की उपासना में क्या फर्क है? अर्जुन ने पूछा, 'जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है।' भगवान श्रीकृष्ण बोले, 'जो लोग मुझमें अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन-बुद्धि से परे सर्वव्यापी, निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझमें लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ।'

जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हों, फिर भी जो नहीं है, उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है, उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही, वह कहते हैं, 'अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है, तो वह भी मुझे पा सकता है।' जब वह 'मैं' कहते हैं, तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। 'यदि कोई वह रास्ता अपनाता है, तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।' क्योंकि जो चीज नहीं है, उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत पड़ती है, जिससे आप जुड़ सकें।

'सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है।' इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि-विवेक युक्त जीव की तरह, अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ भी रहे हैं या यूँ ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव हैं, उनके लिए संभावना मौजूद है क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क-वितर्क नहीं करना पड़ता- वे अपने झुकाव और प्रवृत्ति के मुताबिक चलते हैं। अगर वे आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं, तो वे आमतौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यह उनका सोचा-समझा चयन नहीं होता, बल्कि

निराकार और साकार भक्ति



उनका झुकाव होता है। इसलिए, अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है क्योंकि वे पंचतत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं।

मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है, जिससे आप जुड़ सकें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहाँ के वहाँ अटक रह सकते हैं।

'मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझमें लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ।' यह सिर्फ कृष्ण ने नहीं कहा है। हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव किसी न किसी रूप में यही कहता है। जब लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि 'क्या मुझे इस जन्म में मुक्ति मिलेगी?' तो मैं उनसे कहता हूँ, 'आप सिर्फ मेरी बस में चढ़ जाइए। आपको झाड़व नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बस में बैठना है।' मगर आपका अहम ऐसा है, कि आप बस को चलाना भी चाहते हैं। बहुत से लोग बैकसीट में बैठकर झाड़विंग करते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ ब्रेक लगाते हैं।

अगर आप किसी खास इंसान की मौजूदगी में हैं, तो आखिरी वक्त में आपकी मुक्ति आसान हो जाती है। सवाल यह है कि आप अपने बाकी जीवन को कितनी खूबसूरती से जीते हैं। चाहे आपने मूर्खतापूर्ण जीवन जिया हो, फिर भी किसी खास की मौजूदगी में आपकी चरम मुक्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। बस अपने जीवन के आखिरी पलों में आप सारा काम बिगाड़ न दें। अगर आखिरी पल में भी आपको जरूरी अक्ल नहीं आती है और आप गुस्सा, नफरत या लालसा

की भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो आपका अगला जन्म हो सकता है। वरना, एक बार आप मेरे साथ बैठने की गलती कर लें, तो जब आप मरेंगे तो वह अच्छे के लिए होगा। यहां पर भी वह यही कह रहे हैं। अंग्रेजी में ये अनुवाद बिल्कुल सटीक नहीं हैं। वास्तव में वह कहते हैं, 'अगर कम से कम एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मुझमें लगा हुआ है, तो तुम मुझे पा लोगे।'

वह अर्जुन से कहते हैं, 'युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो। तुम यहां हो। तुम्हें लड़ना है। तुम जीतोगे या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो, तो राज्य का आनंद उठाओ। अगर तुम मर जाते हो, तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा।' यहां पर भी वह यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी हालात की होती है, तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते। आंतरिक हालात में पूरी गारंटी होती है। मगर वह कहते हैं, 'मैं यह पक्का करूंगा कि आपको आगे जन्म न लेना पड़े।' मेरे साथ भी यह सच है। मैं पक्का कर सकता हूँ कि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मगर मैं यह पक्का नहीं कर सकता कि आपको कल नाश्ता मिल जाए। किसी तार्किक दिमाग को यह बात बेतुकी लग सकती है, 'अगर आप इतनी बड़ी चीज सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप नाश्ता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते?' जीवन की हकीकत यही है। मैं आपके लिए कल का नाश्ता पक्का नहीं कर सकता, मगर मैं आपका परम कल्याण सुनिश्चित कर सकता हूँ। जब आंतरिक आयामों की बात आती है, तो मैं उसका पूरा जिम्मा ले सकता हूँ। जब बाहरी हालातों की बात आती है, तो कोई गारंटी नहीं होती- हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है।

● ओम



40 साल सरकारी नौकरी और लगभग प्रतिदिन 15-20 किलोमीटर साईकिलिंग करने के बाद वे आज सेवानिवृत्त होकर जिंदगी के एक अहम मोड़ पर हैं। अक्सर मैं सोचा करता था कि दादा इतना सोते क्यों हैं। दिन में दो बार नहाते क्यों हैं। दिनभर सोना उनकी फितरत बन गई थी। मैं ही नहीं पूरा परिवार भी इस बात से परेशान कि ऐसा क्यों? एक उम्र के बाद चिड़चिड़ाहट होना स्वाभाविक है। बार-बार उनका यह कहना कि मेरा घर है, मैंने इसे बनाया है। मैं यहीं खाना खाऊंगा, यहीं सोऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो और कई अपशब्दों की भरमार सुनकर अच्छा नहीं लगता था। जरूर कोई ना कोई तो परेशानी हैं। हमारी परेशानी तो अपनी जगह हैं-खासकर अपमान सहने की।

सुबह नहाने के बाद एक-दो मंदिरों के दर्शन कर आना उनकी आदत में शुमार था। एक दिन दादा के बारे में पास में ही रहने वाली दीदी ने कहा- 'तुम्हारे दादा एक दिन मुझसे पता पूछ रहे थे।' मैंने कहा- 'क्यों?' उसने कहा- 'अरे, घर भूल गए होंगे।' मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने दादा से पूछा- 'आप घर भूल गए थे क्या?' दादा ने दृढ़ता और गुस्से में आकर कहा- 'मुझसे फालतू बात मत कर।' मैंने

संयम रखकर एक बार फिर पूरे आदरभाव के साथ कहा- 'यदि ऐसा हो रहा हो तो आप मंदिर मत जाया कीजिए, जुही को साथ ले जाया कीजिए।' उन्हें मेरी बात पर और गुस्सा आया बोले- 'तू ज्यादा समझदार है क्या?' इस पर मुझे भी परिवार वालों ने चुप रहने का इशारा किया।

एक दिन मैं किसी काम से बाहर जाने हेतु निकला। मां से पूछा- 'दादा मंदिर से आए क्या?' मां बोली- 'नहीं, अभी नहीं आए, आ जाएंगे।' कॉलोनी से थोड़ा बाहर निकला ही था कि मुझे दादा दूसरी ही दिशा में जाते हुए नजर आए। मैं दौड़कर उनके पीछे गया और बोला- 'कहां जा रहे हैं।' बहुत ही नम्रता के साथ उन्होंने जवाब दिया- 'मैं घर जा रहा हूं।' मैंने उन्हें कहा- 'दादा, अपना घर इधर है।' तब मुझे समझ आया कि दादा अब भूलने लगे हैं। उनकी मेमोरी लॉस होने लगी हैं। अब समझ में आया कि वे दो बार क्यों नहा रहे थे। उन्हें लगता था कि वे उठते हैं तो सुबह हो गई है। इस वाक्य के बाद लगा कि परेशान हम ही नहीं वे भी हो रहे हैं। इसके बाद हम सभी ने अपने व्यवहार में भी बदलाव किया और अतिरिक्त ध्यान रखना प्रारंभ किया।

— संजय एम. तराणेकर

जंग जीत ही जाएंगे

कोरोना से छिड़ी भयंकर,
जंग जीत ही जाएंगे।
अभी जरा विचलित हैं लेकिन,
कब तक यूं घबराएंगे।।
मानवता के शुष्म शत्रु का,
छद्म रूप दिखलाना है।
है सवार संकल्प शीश पर,
अब पाषाण गलाना है।
उग्र ज्वाल यदि हृदय भरेंगे,
नष्ट तभी कर पाएंगे।।
कोरोना से छिड़ी भयंकर...।
रख कर दूरी भीड़-भाड़ से,
कहीं नहीं आए-जाएं।
अभिवादन हो हाथ जोड़कर,
न मिले न गले लगाएं।
अब सख्ती से अनुशासन के,
नियम सभी अपनाएंगे।।
कोरोना से छिड़ी भयंकर...।
हमें बढ़ानी है प्रतिरक्षा,
नित्य योग व्यायाम करेंगे।
संक्रमण पर विजय प्राप्त कर,
नहीं रुग्ण असमय मरेंगे।
स्वच्छता को हथियार बना हम,
भारत देश बचाएंगे।।
कोरोना से छिड़ी भयंकर...।
सार समझ लो श्वास-श्वास का,
बंद करो नित मनमानी।
हां! बचाव में ही इलाज यह,
बात समझ ले हर प्राणी।
कब तक घेरेंगी विपदाएं,
दिन यह भी टल जाएंगे।।
कोरोना से छिड़ी भयंकर...।

— रीना गोयल

पि ता जी को लौटकर आते देख शिवपूजन आश्चर्यचकित हो बोला- क्या बात है पिताजी, बस छूट गई क्या?

पिता - 'नहीं, मैंने सोचा मैं गांव में अकेले रहते तुम लोगों की चिंता करता रहूंगा और यहां तुम मेरी। तुम अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हो। इसी शहर में रहते मैं बच्चे की देखभाल भी कर सकूंगा। बच्चों में संस्कार मां-बाप और दादा-दादी से ही आते हैं।

शिवपूजन कहने लगा- पिताजी, मैंने तो ऊपर के दोनों कमरे ढाई हजार रुपए माह के किराए पर देकर एक माह का अग्रिम भी ले लिया। वह बस सामान लेकर आता ही होगा।

घर परिवार और देश का भविष्य



पिता बोले- बेटा, अच्छा किया। रात को तेरी और बहू की बातें सुनकर मुझे लगा तुम्हें किराए की आय की सख्त आवश्यकता है। मैंने इसी शहर में कमरा किराए पर ले लिया है। मकान मालिक का कपड़े का बड़ा शोरूम है, जहां उसने मुझे दस हजार रुपए माहवार पर काम पर रख लिया है। गांव जाकर तो तुम पर बोझ ही बनता। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। संस्कारी और योग्य बच्चों के हाथों में ही घर परिवार और देश का उज्वल भविष्य निर्भर है।

शिवपूजन और उसकी पत्नी आंख नहीं मिला पा रहे थे।

— लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला

1971 का साल था। ओवल में इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच खेला जा रहा था। भागवत चंद्रशेखर (38 रन पर छह विकेट) की फिरकी के सामने अंग्रेज टीम बिखर गई थी और भारत को जीत के लिए चौथी पारी में 176 रन का लक्ष्य मिला था। टीम ने चार विकेट हाथ में रहते ही इसे हासिल कर लिया। 24 अगस्त, 1971 की उस तारीख को क्रिकेट की दुनिया का शक्ति संतुलन हल्का सा ही सही भारत की तरफ झुक गया था। ओवल मैदान की बॉलकनी में खड़े भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर की आंखें डबडबाई थीं, लेकिन शायद उन्हें भारतीय क्रिकेट का पूरा परिदृश्य साफ नजर आ रहा था। इंग्लैंड दौरे से पहले वे गैरी सोबर्स की महान टीम को 1-0 से हरा कर आए थे, लेकिन अपनी आत्मकथा में उन्होंने इंग्लैंड को उसी की सरजमीं पर हराने को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया।

1971 की वह जीत कई मायनों में अहम थी। क्रिकेट इतिहासकार गिडियन हेग ने लिखा है कि इस जीत ने भारतीय टीम की मानसिक स्थिति ही बदल दी थी। वे लिखते हैं, '1971 के लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत ने इंग्लैंड से ड्रा खेला। इसके बाद टीम के कप्तान वाडेकर और मैनेजर हेमू अधिकारी ने भारतीय खिलाड़ियों की रुकने की व्यवस्था पर जोरदार आपत्ति दर्ज कराई। और ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय टीम के मुताबिक व्यवस्था की गई।' अजीत वाडेकर को टेस्ट टीम में आने में भले थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उनके गणित और विज्ञान वाले तर्कशील दिमाग के लिए कप्तानी ज्यादा दूर नहीं थी। जब अजीत टीम में आए तो टाइगर पटौदी भारतीय टीम के कप्तान थे। उनकी अगुवाई में 1967-68 में न्यूजीलैंड गई भारतीय टीम ने मेजबान टीम को हरा दिया था। लेकिन हालात एकाएक तेजी से बदले। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक 'ए कार्नर ऑफ फरिन फील्ड' में लिखते हैं, 'पटौदी 1970 में भारतीय टीम का शानदार नेतृत्व करने के लिए तैयार लग रहे थे, लेकिन उसी साल इंदिरा सरकार ने राजाओं के प्रिवी पर्स और पदवियां छीन लीं। पटौदी की फार्म भी काफी खराब हो गई।' इसके बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम के लिए नए कप्तान की चर्चा शुरू हुई। 1966 में टीम में आए अजीत वाडेकर अपने प्रदर्शन और क्रिकेटिंग सेंस के चलते कप्तानी के दावेदार हो गए। चयन समिति में पटौदी और वाडेकर के नाम पर वोट बराबर हो गए। अब चेयरमैन विजय मर्चेंट का वोट निर्णायक था। कहा जाता है कि विजय मर्चेंट ने एकबारगी अजीत को अपने कॉलेज में खेलते देखा था तो कहा था कि यह लड़का एक दिन भारत की कप्तानी करेगा। विजय मर्चेंट के वोट



अजीत वाडेकर ने विदेशी पिचों पर जीतना सिखाया

ने अजीत वाडेकर को टीम का कप्तान बना दिया। पटौदी ने प्रिवी पर्स खत्म होने के बाद कप्तानी से हटाए जाने को एक और झटके के तौर पर लिया। खुद को टीम के लिए अनुपलब्ध बताते हुए उन्होंने 1971 का संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि वे कांग्रेस उम्मीदवार से बुरी तरह हारे।

तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीत वाडेकर को अब इतिहास लिखना था। नियति भी उनके साथ थी। सुनील गावस्कर जैसा बल्लेबाज वेस्टइंडीज में उनकी कप्तानी में अपना टेस्ट करियर शुरू करने जा रहा था। उनके पास बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर की ऐसी तिकड़ी थी कि यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि किस टीम में रखा जाए। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की जीत ने अजीत वाडेकर को राष्ट्रीय हीरो बना दिया। 1971 का ओवल टेस्ट जीतने के बाद भारतीय टीम को बंबई के सांताक्रूज हवाई अड्डे आना था। लेकिन फ्लाइट को दिल्ली घुमा दिया गया। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, 'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को भी मिलने के लिए महीनों इंतजार करवाती थीं। लेकिन इस विजयी टीम से मिलने का महत्व वे भी जानती थीं। सभी खिलाड़ियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की।' बाएं हाथ के इस स्टाइलिश आक्रामक बल्लेबाज ने भारत की ओर से 37 टेस्ट खेले और 2113 रन बनाए। उनके नाम एक शतक (143) और 14 अर्धशतक हैं। अजीत की

कप्तानी में भारत ने 16 टेस्ट खेले जिनमें से उसने चार जीते और चार हारे। 8 मैच ड्रा रहे। आंकड़ों की दूर उन्हें भारत का सफलतम कप्तानों में शुमार करती है। हालांकि क्रिकेट विशेषज्ञों का एक खेमा मानता है कि कप्तानी और फिर सफलतम कप्तान बने रहने के दबाव ने उनकी बल्लेबाजी को खासा प्रभावित किया। घरेलू क्रिकेट के कुछ विवादों के चलते अजीत वाडेकर ने 1974 में खेल से संन्यास ले लिया।

अजीत वाडेकर के खेल के अलावा उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलू हैं जो खासे मजेदार हैं। मसलन एक बार वे इंग्लैंड में जल्दी आउट हो गए। बाउंड्री के बाहर एक पत्रकार उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वाडेकर उसके हर सवाल के जवाब में कह देते थे- नो इंग्लिश। आखिर में उस पत्रकार ने खीझकर कहा, 'अजीत तुम पूरे टूर पर मुझसे इंग्लिश में बात करते आए हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी जल्दी सारी इंग्लिश भूल गए।' जब अजीत वाडेकर पहली बार बतौर कप्तान वेस्टइंडीज में सर गैरी सोबर्स की टीम से खेलने पहुंचे तो उस सीरीज में सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। शुरू के मैच में गावस्कर ने अच्छा खेला और उनके कुछ कैच भी छूटे। इसके बाद गैरी सोबर्स भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आते और गावस्कर का कंधा छूकर चले जाते। उनका अंधविश्वास था कि इस समय गावस्कर की किस्मत अच्छी है और उनका कंधा छूने से कुछ गुडलक उन्हें भी मिल जाएगा। तीसरे टेस्ट में यह बात वाडेकर को पता चली। इस टेस्ट की पहली पारी में गावस्कर और गैरी की मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी पारी में गैरी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो अजीत वाडेकर ने गावस्कर को धकेल कर वॉशरूम में बंद कर दिया। गैरी उन्हें दूढ़ते ही रह गए। इतेफाक देखिए कि गैरी सोबर्स उस पारी में सस्ते में आउट हो गए।

● आशीष नेमा



ऐश्वर्या को ऑफर हुई थी ब्रेड पिट के साथ फिल्म



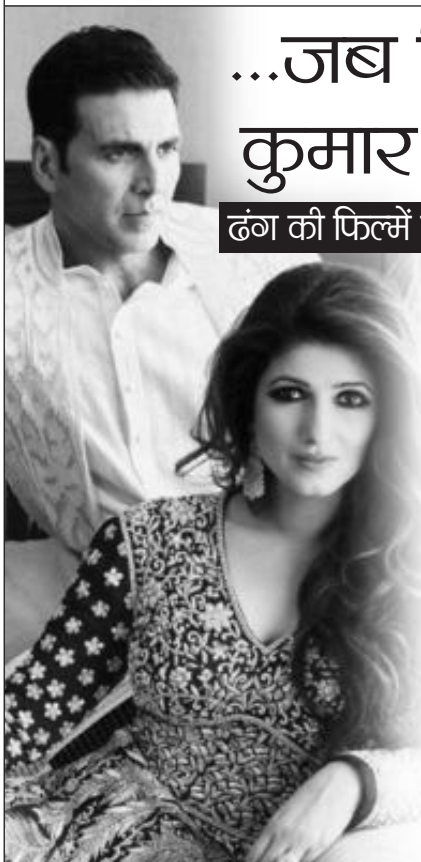
ऐश्वर्या राय बच्चन को भारत ही नहीं दुनियाभर में पहचाना जाता है। उनकी सुंदरता और कलाकारी के कायल विदेशी कलाकार भी हैं। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण से भी पहले ऐश्वर्या ने मुश्किल की स्टार ऐश्वर्या ने हॉलीवुड में धाक जमाई थी। उन्होंने वहां पिक पैथर और प्रोवोकड जैसी फिल्मों में काम किया है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता कि 2012 में ब्रेड पिट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ऐश्वर्या के साथ काम करना अच्छा लगेगा।

एक पुराने इंटरव्यू में ब्रेड पिट ने कहा था 'मौका मिला तो मैं ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम करना चाहूंगा क्योंकि वो वाकई कमाल की कलाकार हैं। वो बॉलीवुड की सबसे मशहूर कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने पश्चिम में भी अपने अंदाज से धूम मचा रखी है। मुझे लगता है कि ट्रॉय में हम लोग साथ कर सकते थे लेकिन यह होते-होते रह गया।' बता दें कि 2004 में ऐश्वर्या को पिट के अपोजिट रोल दिया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वजह यह थी कि इस ट्रॉय में ऐश्वर्या को पिट के साथ लव मैकिंग सीन करना पड़ते।

अक्षय कुमार और दिवंकल खन्ना की लव स्टोरी बहुत कमाल की है। दोनों के स्वभाव की कुछ बातें एक-दूसरे से बिल्कुल उलट है। फिर भी दोनों खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अक्षय कुमार ने एक शो में बताया कि किस तरह दिवंकल खन्ना के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।

...जब दिवंकल ने अक्षय कुमार को दी थी धमकी

ढंग की फिल्में नहीं की तो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे



अक्षय कुमार और दिवंकल खन्ना की कुछ कहानियां तो बहुत रोचक हैं। मसलन, दिवंकल ने एक बार अक्षय कुमार से कह दिया था कि अगर उन्होंने ढंग की फिल्में नहीं की तो वह दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इसके बाद ही अक्षय कुमार ने फिल्में करने की शैली बदली और आज बॉलीवुड के सबसे महंगे कलाकार हैं। यह खुलासा खुद अक्षय कुमार ने कॉफी विद करण शो में किया था। अक्षय कुमार ने बताया कि किस तरह दिवंकल खन्ना के आने से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उसी शो में दिवंकल ने खुलासा किया था कि जब वह अक्षय को डेट कर रही थीं, तो उन्होंने जन्मदिन के मौके पर उन्हें पेपरवेट दिया। बकौल अक्षय कुमार, मैं दिवंकल का जन्मदिन भूल गया था और फिर जब मुझे एहसास हुआ, तो वहीं जाने और गिफ्ट खरीदने का समय नहीं था। मेरे घर में पेपरवेट था, इसलिए मैंने जल्दी से इसे लपेटा और गिफ्ट दे दिया। यह बात दिवंकल को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसी पेपरवेट के आकार का डायमंड गिफ्ट में मांगा।

अक्षय कुमार के कारण बुरी फंस गई थी दिवंकल... एक फैशन वीक के दौरान 2009 में अक्षय और दिवंकल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अश्लीलता करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। कॉफी विद करण पर दिवंकल ने मामले के पीछे की कहानी का खुलासा किया था और बताया था कि कैसे वह अभी भी 500 रुपए की जमानत पर बाहर हैं। दिवंकल ने बताया था कि अक्षय ने उन्हें फैशन शो में आमंत्रित किया और शो शुरू होने से ठीक पहले उन्हें एक फोन आया, जिसमें अक्षय ने उनसे कहा कि शो के दौरान वह उनके सामने रुकेंगी और उन्हें अपनी जींस उतारनी होगी।

‘द फैमिली मैन-2’ का प्रीमियर नवंबर में संभव

मिर्जापुर 2 की रिलीज डेट घोषित होने के बाद अब फैंस को ‘द फैमिली मैन 2’ के दूसरे सीजन का इंतजार रहेगा। इस फिल्म की डबिंग शुरू हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि मनोज बाजपेयी स्टार इस सीरीज का दूसरे सीजन का प्रीमियर नवंबर में हो सकता है।

अमेजन प्राइम वीडियो पिछले कुछ सालों में दमदार हिंदी वेब सीरीज लेकर आया है। इन वेब सीरीज की अपनी फैन फॉलोइंग हैं। लोग इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। मिर्जापुर का



दूसरा सीजन अक्टूबर में रिलीज होने वाला है। फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। अमेजन

प्राइम वीडियो ने साल के शुरुआत में जिन सीरीज को रिलीज करने की लिस्ट जारी की थी, उसमें द फैमिली मैन का दूसरा सीजन भी शामिल है। दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी इस सीरीज के जरिए हिन्दी मनोरंजन इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। उन्होंने अपनी डबिंग का काम पूरा कर लिया है। गत दिनों पहले ‘द फैमिली मैन 2’ के मुख्य कलाकार मनोज बाजपेयी की इस सीरीज की डबिंग के लिए स्टूडियो पहुंचने की फोटोज सामने आई थी।

मिलावटखोरों के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें मिलावट करने की खुली छूट मिलेगी, रिश्वतखोरों के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें रिश्वत लेने की वैधानिक स्वीकृति मिल जाएगी, नेताओं के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें वोट मांगने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा। ईमानदार भी अच्छे दिन के लिए तड़प रहे हैं और बेईमान भी। ईमानदार के अच्छे दिन तब आएंगे जब उनके ईमान को महत्व मिलने लगेगा।

आजकल भाई लोग अच्छे दिनों की आशा में मरे जा रहे हैं, बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, अपनी नौद खराब कर रहे हैं लेकिन अच्छे दिन मृगमरीचिका बन गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं। अच्छे दिन के लिए लोग खूब पसीना बहा रहे हैं, कठिन संघर्ष कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हर फाइल को रोक रहे हैं, अफसर फाइलों को ऊपर-नीचे सरकाने में अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, ठेकेदार सड़क बनाने के लिए सीमेंट की जगह बालू मिला रहे हैं, व्यापारी कालाबाजारी करने के लिए नए-नए तरीके का अविष्कार कर रहे हैं, घूसखोर बाबुओं ने घूस की दर बढ़ा दी है, प्राध्यापक स्कूल-कॉलेज की जगह कोचिंग संस्थानों में अधिक पसीना बहा रहे हैं, डॉक्टर दवा कंपनियों से ज्यादा कमीशन लेने के लिए अधिकतम मोलतोल कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर अपने मालिकों के आदेश से अधिक से अधिक मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर भी अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। अब क्या किया जाए भाई! इतनी मेहनत-मशक्कत करने के बाद भी जब अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं तो क्या किया जाए! जो 70 वर्षों में अच्छे दिन नहीं ला सके वे भी पूछने लगे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे।

मेरा भूतपूर्व और अभूतपूर्व घूसखोर मित्र घोंचूमल भी आजकल अच्छे दिनों की चिंता में दुबला होता जा रहा है। समस्त लम्पटीय गुणों और लोकतंत्रीय कचरे से युक्त भूतपूर्व मगध सम्राट चालू प्रसाद भी आजकल अच्छे दिनों की चिंता में घुले जा रहे हैं जिनके अच्छे दिन का आरंभ अपने परिवार से और अंत अपनी जाति के उद्धार से होता है। चालू प्रसाद जेल में रहकर भी अच्छे दिन लाने के लिए आकुल-व्याकुल हैं। उन्होंने मगध के राज सिंहासन पर बैठकर पंद्रह वर्षों तक अपहरण, लूट और चोरी की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। अतः उनका चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है।

मेरे मोहल्ले में एक चोर रहता है। उसका नाम खेसारीलाल है। खेसारीलाल घोषित रूप से चोर है, लेकिन आज तक वह पकड़ा नहीं गया। एक-दो बार पकड़ा भी गया तो उसने पुलिसवालों को

अच्छे दिन कब आएंगे?



कागजस्वरूपा लक्ष्मीजी के साक्षात् दर्शन करा दिए। लक्ष्मीजी की कृपा से वह कभी जेल नहीं गया। सभी जानते हैं कि खेसारीलाल चोर है लेकिन उसके खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं, किसी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं। इसलिए वह सफेदपोशों के मोहल्ले में शान से रहता है।

अब सफेदपोश भी कितने सफेद और कितने श्याम हैं, यह चिंता और चिंतन का विषय है। जिस प्रकार प्रत्येक कमीज में एक चोरपाकेट होता है उसी प्रकार प्रत्येक सफेदपोश की दाढ़ी में एक स्याह तिनका होता है। जब से सरकार ने पुलिस तंत्र को मजबूत किया है, खेसारीलाल का धंधा मंदा हो गया है। खेसारीलाल अब इस इंतजार में है कि कब पुलिस तंत्र सुस्त हो और उसके अच्छे दिन आएँ। अच्छे दिन क्या पेड़ पर

उगते हैं कि डाल झुकाया और तोड़ लिया। अब तो सभी ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे, राजा भोज और गंगू तेली पूछने लगे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे।

मिलावटखोरों के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें मिलावट करने की खुली छूट मिलेगी, रिश्वतखोरों के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें रिश्वत लेने की वैधानिक स्वीकृति मिल जाएगी, नेताओं के अच्छे दिन तब आएंगे जब उन्हें वोट मांगने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा।

ईमानदार भी अच्छे दिन के लिए तड़प रहे हैं और बेईमान भी। ईमानदार के अच्छे दिन तब आएंगे जब उनके ईमान को महत्व मिलने लगेगा। अभी तो ईमान सिसक रहा है, ईमान बिक रहा है, ईमान खरीदा जा रहा है, ईमान की नीलामी की जा रही है। जब ईमान को जलील नहीं होना पड़ेगा, ईमान को इज्जत से जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ईमान को चौराहे पर फांसी नहीं दी जाएगी तब ईमानदारों के अच्छे दिन आएंगे।

लल्लन हलवाई को भी अच्छे दिनों का इंतजार है और बबन ठेकेदार को भी। मनोज बाबू को भी अच्छे दिनों का इंतजार है और इनकम टैक्स के चपरासी ददन शर्मा को भी। इतिहास गवाह है कि लल्लन हलवाई ने आजतक बिना मिलावट के कोई सामान नहीं बेचा। घी में डालडा, पनीर में आटा और डालडा में मिट्टी की मिलावट कर उसने न जाने कितनों के प्राण हर लिए। इसलिए कुछ लोगों ने उसका उपनाम प्राणहरण मिठाईवाला रख दिया है। वह भी आजकल अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में दुर्बल होता जा रहा है। बबन ठेकेदार के बनाए पुल और भवन उद्घाटन के पहले ही धराशायी हो जाते हैं। न जाने बबन के धराशायी भवनों में दबकर कितने मजदूरों को मोक्ष मिल गया। उसे भी अच्छे दिन का इंतजार है। मनोज बाबू एक सरकारी विभाग में क्लर्क हैं। जिस प्रकार बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, मसिजीवी आदि शब्द होते हैं उसी प्रकार उसने अपने लिए एक नया शब्द गढ़ लिया है रिश्वतजीवी। अन्य रिश्वतखोरों की तरह उसमें कोई पाखंड नहीं है। वह खुलेआम रिश्वत भी लेता है और रिश्वतखोरी के समर्थन में व्याख्यान भी देता है। देखें, इन महापुरुषों के अच्छे दिन कब तक आते हैं।

● वीरेन्द्र परमार

PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म[®] चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-3000-1444

Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us



Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5



Email : shbpl@rediffmail.com



PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687